BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Admission Open
For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Vision -
To prepare the children
empowered
with Indian ethical
and spiritual values
to face the global challenges.

Mission-
To produce
enriched and enlightened
human resource
for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

पोस्टल रजि.नं.यू०-नैनीताल-356-2021-2023

मई 2026

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

क्या महिला विरोधी है विपक्ष

₹:40

बंगाल में भय हारा भरोसा जीता

शुर्भेदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1,956 वोटों से हराया था, इसलिए अमित शाह को भरोसा था कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ शुर्भेदु अधिकारी ही हरा सकते हैं, इसलिए शुर्भेदु अधिकारी को भवानीपुर से ममता के मुकाबले पर उतारा गया, नतीजा चौकाने वाला आया ममता दीदी इस बार 15104 वोटों के बड़े अंतर से हार गई।

ई-मेल: uttaranchaldeepatrika@gmail.com
Web: uttaranchaldeep.com

मासिक
उत्तरांचल दीप
पत्रिका
वर्ष:9, अंक 1, मई 2026

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर ही विवाद नहीं है, उनके नाम को लेकर भी विवाद है, उनका असली नाम राहुल गांधी है या 'राउल विंसी'? यह राज भी उनकी दोहरी नागरिकता वाले विवाद से जुड़ा है। यदि एलओपी और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के असली नाम के...

कांग्रेस
'बगावत' या राष्ट्रहित?
आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और कमल नाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष ...

बंगाल
ममता के साथ खेला हो गया
टीएमसी हर चुनाव में धन-बल का प्रयोग करती रही है, लेकिन इस बार भाजपा की लहर ने ...

वनाग्नि
वन्यजीवों की जान आफत में
उत्तराखंड में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून रहता है, सीजन में बस्तियों से ज्यादा आग जंगलों में लगती है, वनाग्नि की ...

रंग बदलता बुग्याल
अली-बेदनी बुग्याल ट्रेक, ट्रेकर्स को अंतहीन घास के मैदानों की जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां टूरिस्ट हिमालय की सबसे ...

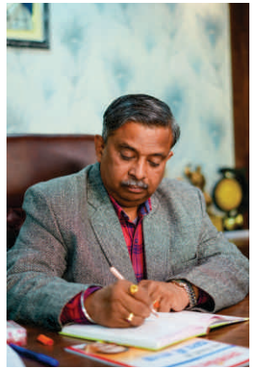

साकेत अग्रवाल

मुस्लिम वोट बैंक का भ्रम टूटा

आपको याद होगा यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। डा.मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसकी क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेसी विचारधारा, क्योंकि कांग्रेस तो देश की आजादी के बाद से ही मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करती आ रही है। कांग्रेस की देखा देख समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव हो या बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, आरजेडी नेता लालू यादव सभी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण से सत्ता में बने रहे। कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे 55 साल तक देश पर राज किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल तक घुसपैठियों और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर सत्ता में बनी रही। मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता हासिल करने की हसरत में कभी हिंदुत्व के नाम पर बनी शिवसेना (उद्धव) ने तो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को ही कलंकित कर दिया। उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए व्याकुल थे लिहाजा उन्होंने भाजपा का दशकों पुराना साथ छोड़कर शिवसेना की विपरीत विचारधारा वाली कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया। अब जैसी संगत वैसी रंगत, वाली कहावत शिवसेना पर फिट हो गई। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोटों पर आश्रित होने लगे। लेकिन उनके पास न तो पार्टी बची और न ही पार्टी का चुनाव चिह्न। 2014 के बाद से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब मुस्लिम वोट बैंक पर जिंदा रहने वाली पार्टियों का भ्रम टूट रहा है। मुस्लिम समुदाय हमेशा कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी जैसे दलों के लिए महज एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं था। ये दल भाजपा का खौफ दिखाकर, भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताकर खुद सत्ता का सुख भोगते रहे। 2014 के बाद से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल चाहे कांग्रेस हो या सपा, बसपा, टीएमसी और आरजेडी सब हासिये पर हैं। क्योंकि केंद्र में नरेंद्र की सरकार बनने के बाद से केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों ने बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्रता के आधार पर दिया है, ना कि जाति धर्म के आधार पर। मोदी सरकार ने ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला के नरक से आजाद किया। जबकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों ने तीन तलाक कानून का विरोध किया था। लिहाजा यूपी में जो सपा और बसपा मुस्लिम वोटों पर जिंदा थी वो 10-15 सालों से सत्ता का मुंह देखने को तरस रही है। बिहार में आरजेडी सत्ता के लिए तड़प रही है। कांग्रेस भारत के नक्शे से लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। महाराष्ट्र में तो शिव सेना (उद्धव) जो खुद को हिंदुवादी पार्टी कहती थी वो भी मुसलमानों की शरण में चली गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम और घुसपैठियों के वोट के दम पर 15 साल राज करने वाली ममता बनर्जी का किला भी ढह गया। लिहाजा जिन राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोट बैंक में सत्ता नजर आती थी। जिन मुसलमानों को यह भ्रम था कि उनके वोट से ही सत्ता आती-जाती है वो पिछले 10-12 सालों में टूट गया है। इसके पीछे हिंदुओं का जातिवाद से ऊपर उठकर सनातन की बात करना। सनातन को बचाने के लिए एकजुट होने भावना जागृत होना भी है। इसलिए शायद अखिलेश यादव भी मंदिर बनवाने लगे हैं। हालांकि अयोध्या जाकर श्रीराम के दर्शन आज तक नहीं किए। भले ही एक मौलाना, अखिलेश की मौजूदगी में उनकी पत्नी डिंपल यादव का अपमान करे, पर मुस्लिम वोट हाथ से नहीं खिसकना चाहिए। ऐसी जिल्लत की राजनीति सिर्फ अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा नहीं करने देती थी। वही ममता दीदी मुस्लिम के त्योहारों पर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ती रही हैं। इंशा अल्लाह, खुदा हाफिज करती रही हैं। सपा सरकार में जैसे यूपी में मुस्लिम हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठियो को महिलाओं का उत्पीड़न करने की खुली छूट थी। यानी महिला सुरक्षा पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले मंदिर बनवाने की घोषणा क्यों की? क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से सत्ता हासिल नहीं हो सकती। वैसे भी एसआईआर ने ममता का खेला खत्म कर दिया था।

राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक, एक्सपर्ट, विद्वान, पॉलिटिकल एडिटर सब के सब 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक की बात तो करते है, लेकिन जब 70 प्रतिशत हिंदू वोट की बात आती है तो ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, यादव, कुर्मी, दलित, कुम्हार, सैनी, कुशवाह, राजभर, निषाद, मल्लाह, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में बंटवारा करते है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत दशकों से हो रहा है। लेकिन अब जातिबंधन की दीवार ढह रही है। अब मुस्लिम समाज में भी जातियां बताई जा रही हैं, इसकी शुरुआत भाजपा ने ही की और बताया कि मुसलमानों में भी पठान, अंसारी, नाई, लोहार, बढ़ई, धोबी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी होते हैं। लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज में एकबड़ा तबका वो है जिसके जहन में सियासी दलों के मौलानाओं ने भाजपा का खौफ भरा है। हालांकि अब ये खौफ धीरे-धीरे मुसलमानों के जहन से निकलने लगा है। क्योंकि मुस्लिम तबका समझ रहा है कि भाजपा अगर उसकी दुश्मन होती तो फिर सरकारी योजनाओं का लाभ शायद उन्हें नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। उनका तो साफ और सपाट नारा है सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास। फिर भी मुसलमान भाजपा को हराने वाले दल को ही वोट देता है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुले मंच से हिंदुत्व को खत्म करने का नारा देते हैं, फिर भी बड़ी संख्या में हिंदू, हिंदुत्व को खत्म करने वाले को वोट देता है। लेकिन अब एक मुस्लिम तबका भाजपा का खुले दिल से समर्थन कर रहा है इसे ही मोदी मैजिक कहा जा सकता है।

ट्रंप पर हमला हुआ या ?

ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप पाकिस्तान का सहारा लेकर भी युद्ध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर ट्रंप के अलावा शायद ही कोई देश भरोसा करता हो, मुस्लिम देश भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, इनमें ईरान भी शामिल है।

अ

उत्तरांचल दीप डेस्क

मेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 25 अप्रैल की रात हाई-प्रोफाइल इवेंट के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोली चलने की आवाज के बीच सीक्रेट सर्विस ने फौरन एक्शन लेते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यानी जैसे ही एक अधिकारी 'शॉट्स फायर्ड' चिल्लाया, आधुनिक हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तेजी से बॉलरूम में दाखिल हुए और ट्रंप व उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को घेरे में ले लिया। यही नहीं फायरिंग के समय हॉल में मौजूद मेहमानों में अफरा-तफरी मच गई और अधिकांश लोग जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए जबकि कुछ लोग जमीन पर लेट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन था। हालांकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया था। हालात सामान्य होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- 'सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेज और बहादुरी से प्रतिक्रिया दी।' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक हत्याओं का अध्ययन किया है और उनका मानना है कि जिन नेताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वही सबसे ज्यादा निशाने पर आते हैं। उन्होंने बटलर, पाम बीच और अब वॉशिंगटन की घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से कर दी, जिनकी हत्या अप्रैल के ही महीने में की गई थी। ट्रंप ने कहा कि जब आप प्रभावशाली होते हैं, तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। जब आप प्रभावशाली नहीं होते, तो आपको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे प्रभावशाली लोग, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे बड़ा असर डालते हैं, वही निशाने पर होते हैं।' डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की? लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं? उन्होंने 1861 से 1865 तक अपनी सेवाएं दीं। वे रिपब्लिकन पार्टी से ही आते थे और उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट-गृह युद्ध से उबारा था। 1861 में जब वे राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, तब बाल्टिमोर प्लॉट नाम की एक साजिश सामने आई थी, जिसमें उन्हें रास्ते में मारने की योजना थी। हालांकि इसे समय रहते नाकाम कर दिया गया था। लिंकन को कई बार धमकियां मिलीं और आखिरकार 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड्स थियेटर में नाटक देखते समय अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ ने पीछे से गोली मार दी थी। इसके अगले दिन 15 अप्रैल,1865 को उनकी मृत्यु हो गई थी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से की और कहा कि जो प्रभावशाली होते हैं, उन्हें ही मारने की कोशिश होती है।

संदेह के दायरे में ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उनके लिए 1 मई का दिन बहुत निर्णायक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ भी हैं। उन्हें सैन्य अभियान शुरू करने का अधिकार है, लेकिन 48 घंटों के भीतर औपचारिक रूप से कांग्रेस (संसद) को सूचित करना भी आवश्यक है। अमेरिका ने 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसकी जानकारी 2 मार्च को अमेरिकी संसद को दी गई। इस हिसाब से 60 दिनों की समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं-या तो अमेरिकी संसद से इस युद्ध की घोषणा कराएं यानी ट्रंप युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लें या फिर अपनी सेना को पीछे हटाएं। अभी तक ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अब कुछ सांसदों के सुर बदलने लगे हैं। यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने साफ कह दिया है कि 60 दिनों के बाद वो बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर युद्ध जारी रखने का भारी दबाव है, लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति बिना संसद (कांग्रेस) की मंजूरी के सिर्फ 60 दिनों तक ही अपनी सेना को युद्ध में रख सकते हैं। यदि वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलता है, तो राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ युद्ध को वैध ठहराने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। क्योंकि 240 साल पहले अमेरिका के संस्थापकों ने संविधान में युद्ध की जिम्मेदारी को विभाजित किया था। राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ की शक्ति दी थी। लेकिन युद्ध की घोषणा करने का अधिकारी सिर्फ कांग्रेस (संसद) को दिया था। इस प्रस्ताव को वियतनाम युद्ध से मिले सबक के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा संघर्ष जो अमेरिका 1955 से लड़ रहा था, लेकिन संसद ने 1964 तक औपचारिक रूप से संघर्ष को मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि जब इसे 1973 में लागू किया गया, तब तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन संसद में दो-तिहाई बहुमत से उनके वीटो को खारिज कर दिया गया था और कानून लागू हो गया था।

ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप पाकिस्तान का सहारा लेकर भी युद्ध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर ट्रंप के अलावा शायद ही कोई देश भरोसा करता हो। मुस्लिम देश भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, इनमें ईरान भी शामिल है। ईरान से युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, जनता में नाराजगी है, खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सदस्य युद्ध नहीं चाहते। ट्रंप चाहते थे कि नाटो देश उनके इस युद्ध में शामिल हों, लेकिन नाटो देशों ने ईरान युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। आमतौर पर युद्ध की घोषणा से बचने वाली अमेरिकी संसद युद्ध की घोषणा नहीं करती है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से सैन्यबल वापस बुलाने पड़ेंगे। क्योंकि संसद का रिकार्ड कहता है कि उसने आखिरी बार युद्ध की घोषणा 4 जून, 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की थी। ऐसे में 25 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कहानी संदेह के दायरे में कही जा रही है।

सुर्खियां

किन्नरों का बधाई
मांगना गैरकानूनी

विवाह शादी अथवा बच्चों के जन्म पर हर किसी के घर आ धमकने वाले किन्नर कई बार नेग में मुंह मांगी रकम न मिलने पर हंगामा करते हैं। परिवार के साथ अभद्रता तक करते हैं, ऐसे ही बसों व ट्रेनों में किन्नर जबरन वसूली करते हैं। रेड लाइट और टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से उगाही करते हैं, दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर बाजार में किन्नर वसूली करते देखे जा सकते हैं, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस तरह की जाने वाली वसूली को गैरकानूनी करार दे दिया है। यानी लंबे समय से चली आ रही सामाजिक परंपराओं और आधुनिक कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किन्नर (ट्रांसजेंडर) द्वारा पारंपरिक रूप से बधाई या 'नेग' मांगने को गैकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि ऐसी प्रथाओं को वैध ठहराया गया, तो इससे अवैध वसूली और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही अदालत ने किन्नरों की क्षेत्र निर्धारण और सुरक्षा की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल यूपी के गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली किन्नर रेखा देवी ने हाई कोर्ट बेंच में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में नेग (बधाई) मांगने का अधिकार दिया जाए और अन्य क्षेत्रों के किन्नरों को उसके में प्रवेश से रोका जाए। रेखा देवी का कहना था कि वह वर्षों से एक निर्धारित क्षेत्र में बधाई मांगती आ रही हैं, लेकिन दूसरे समूहों के आने से विवाद की स्थिति बनती है, जो कई बार हिंसक भी हो जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की वसूली, चाहे वह टैक्स हो, शुल्क हो या बधाई के नाम पर धन, ये सिर्फ कानून के दायरे में ही लिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि 'जजमानी' या पारंपरिक बधाई के नाम पर धन लेना किसी भी कानून के तहत संरक्षित अधिकार नहीं है और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि यदि जबरन या दबाव बनाकर नेग वसूला जाता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कृत्य माना जा सकता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों को कानूनी संरक्षण देना न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि क्षेत्र निर्धारण कर नेग वसूली को मान्यता दी जाती है, तो इससे अवैध वसूली को बढ़ावा मिलेगा और आपराधिक गतिविधियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। अदालत ने इस आधार पर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था के तहत ही किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है।

पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही शहर की पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में आ जाती है। सरकारी और निजी पार्किंग संचालकों पर पर्यटकों से मनमाने तरीके से वसूली करने के आरोप लगते रहते हैं। एक रात की पार्किंग के नाम पर पर्यटकों से 1000 से 0500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि सुविधा के नाम पर पार्किंग स्थलों पर कुछ भी नहीं है। वीकेंड पर भारी भीड़ के कारण सभी पार्किंग फुल रहती है। इसका फायदा उठाकर पार्किंग संचालक मनमानी शुरू कर देते हैं। पर्यटकों ने सवाल उठाया कि मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाती है, लेकिन पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा क्यों नहीं दी जाती। हर पार्किंग स्थल के बाहर बड़े बोर्ड पर निर्धारित शुल्क, समय सीमा और शिकायत नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होने चाहिए ताकि कोई भी संचालक मनमानी न कर सके। पर्यटकों का कहना है कि कई पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में यदि किसी वाहन के साथ चोरी, दुर्घटना या अन्य घटना होती है तो पर्यटकों को मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले को नजर अंदाज कर रहे हैं। हालांकि मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद का कहना है कि प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जल्द ही सभी सरकारी और निजी पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और वहां निर्धारित रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगवाई जाएगी। साथ ही पार्किंग स्थलों पर एसडीएम, पुलिस और अन्य अधिकारियों के संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि पर्यटक सीधे शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पार्किंग संचालक पर्यटकों से अभद्रता करता या निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पार्किंग निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

लकड़ी में जीवंत आकृति

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो...। दुष्यंत कुमार की यह प्रसिद्ध पंक्तियां दृढ़ इच्छाशक्ति, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती हैं। यानी पूरी लगन, ईमानदारी और कोशिश के साथ प्रयास किया जाए, तो सबसे कठिन लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ पहाड़ की शांत वादियों में देखने को मिलता है जहां आज भी कई ऐसे गुमनाम हुनरमंद हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं। बिना सरकारी सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों के ये कलाकार लकड़ी में किसी भी जीवंत आकृति को बनाने का दम रखते हैं। पौड़ी के रहने वाले जसपाल सिंह रमोला अपनी मेहनत और रचनात्मकता के जरिए वेस्ट पड़ी लकड़ियों में नई जान फूंक रहे हैं। कंडोलिया क्षेत्र में दुकान चलाने वाले जसपाल सिंह के लिए ये केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि वो अपना शौक और जुनून भी पूरा करते हैं। दुकान के काम से समय निकालकर, खासकर रविवार या अवकाश के दिनों में वो बेकार पड़ी लकड़ियों को खूबसूरत और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम करते हैं। जसपाल सिंह रमोला बताते हैं कि उन्होंने इस कला की शुरुआत 1993 में की थी। शुरुआत में उन्होंने वेस्ट लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाईं और कुछ समय बाद पौड़ी में एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी। जिसे लोगों ने काफी सराहा। उनकी पहली रचना मां धारी देवी की एक मूर्ति थी, जिसे उन्होंने श्रद्धा के साथ मंदिर में समर्पित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने छोटे-छोटे सजावटी और उपयोगी आइटम बनाने शुरू किए। हालांकि रोजगार की तलाश में उन्हें कुछ समय के लिए पौड़ी छोड़कर अन्य स्थानों पर काम करना पड़ा। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन के तहत जब वे दोबारा अपने घर लौटे, तो उन्होंने फिर से अपने इस शौक को आगे बढ़ाया। आज जसपाल सिंह रमोला वेस्ट पड़ी लकड़ियों से विभिन्न प्रकार के आकर्षक वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, बल्कि स्थानीय कला और हुनर को भी नई पहचान दिला रहे हैं। जसपाल सिंह रमोला का कहना है कि उन्होंने 2020 में कोविड काल के समय दोबारा इस काम की शुरुआत की। उस समय खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए उन्होंने जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में पड़ी बेकार लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें नया रूप देना शुरू किया। धीरे-धीरे यह उनका शौक बन गया और अब यह उनके लिए आजीविका का साधन भी बन गया है। अब तक जसपाल कई तरह की सजावटी और उपयोगी वस्तुएं बना चुके हैं, जिनमें टेबल लैंप, मूर्तियां, गमले और घर की सजावट के विभिन्न आइटम शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी उत्पाद पूरी तरह हाथ से बनाए जाते हैं, जिससे हर वस्तु अलग और आकर्षक दिखती है। उनके बनाए उत्पादों की स्थानीय स्तर पर बिक्री भी हो रही है। हालांकि जसपाल का कहना है कि इस काम में काफी समय और मेहनत लगती है, जिसके कारण उत्पादों की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके उत्पादों को व्यापक पहचान मिल सके। साथ ही विश्वकर्मा योजना के तहत यदि उन्हें आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, तो वे कम समय में अधिक वस्तुएं तैयार कर सकेंगे, जिससे कीमतों में भी कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने पहाड़ के युवा इस कला को सीखने का संदेश देते हुए कहा कि वो भी बेकार पड़ी लकड़ियों से उपयोगी वस्तुएं बनाकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पहाड़ों से पलायन पर भी रोक लगेगी।

फ्रीडम फाइटर के गांव में सड़क नहीं

भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के कमांडर रहे स्वतंत्रता सेनानी मेजर देव सिंह दानू के गांव पिनाऊं में आज भी सड़क नहीं पहुंची। 2015 में स्वीकृत व दो-दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी 23 किलोमीटर की धुराधारकोट-वांक-पिनाऊं सड़क की फाइल लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के कार्यालय में धक्के खा रही है। ब्लॉक के दूरस्थ गांव पिनाऊं को सड़क से जोड़ने के लिए 2015 में स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वाण में इस सड़क के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद 2018 में सीएम ने लोहाजंग में इस सड़क के निर्माण की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क निर्माण की फाइल लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के दफ्तरों में भटक गई है। जबकि ग्रामीण 6 किलोमीटर की पैदल दूरी नाप रहे हैं। मेजर देव सिंह दानू के पौत्र प्रेम सिंह दानू व वांक गांव के विरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सड़क नहीं होने से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां से अस्थाई तौर पर पलायन कर गए हैं। गांव के बीमार, गर्भवती महिला व बुजुर्ग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। गांव में खच्चरों से राशन की सप्लाई होती है। कई बार मुख्यमंत्री, वन विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद इस सड़क को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलीं। करीब 500 की आबादी की ग्राम पंचायत हरमल के लोग पांच किलोमीटर पैदल दूरी नापते हैं तब सड़क तक पहुंच पाते हैं। वहीं झलिया ग्राम पंचायत के लोग 7 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सड़क नहीं होने से हरमल व झलिया ग्राम पंचायत के लोग राशन व भवन निर्माण की सामग्री खच्चरों से लाने को मजबूर हैं।विकास के नाम पर राजनीतिक दल सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। हर गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा के वादे तो किए जाते हैं, पर पूरे कम ही होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के समय यहां पर नाले उफनते हैं, जिससे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए, तो उसे कंधों पर या पालकी में उठा कर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। सरकार के लिए शर्म की बात है कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी मेजर देव सिंह दानू के गांव पिनाऊं के ग्रामीण सड़क सुविधा न होने का दंश झेल रहे हैं।

बंगाल में भय हारा भरोसा जीता

शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1,956 वोटों से हराया था, इसलिए अमित शाह को भरोसा था कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही हरा सकते हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से ममता के मुकाबले पर उतारा गया, नतीजा चौकाने वाला आया ममता दीदी इस बार 15104 वोटों के बड़े अंतर से हार गई।

4

केके चौहान

राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चैंका दिया है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के लिए ही नहीं कांग्रेस और पहली बार चुनाव लड़े विजय के लिए भी ये चुनाव शानदार रहे। जहां भाजपा गठबंधन ने तीन राज्यों में अपना परचम लहरा दिया वहीं कांग्रेस गठबंधन ने केरल का किला फतह कर लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने फिल्म एक्टर विजय की पार्टी टीवीके पहले ही चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। यानी एक्टर विजय फिल्मों की तरह ही राजनीति में भी सुपर हिट हो गए। हालांकि त्रिशंकु विधानसभा होने की वजह से विजय की टीवीके अकेले सरकार नहीं बना सकेगी। टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। विपरीत विचारधारा के दलों के साथ सरकार तो बन गई, लेकिन यह सरकार कितने दिन टिक पाएगी ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने सबसे पहले विजय की पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। यानी अपने दशकों पुराने साथी डीएमके को छोड़कर राहुल गांधी ने नया पार्टनर विजय को बना लिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा लहराया तो हिंदुवादी नेता शुभेंदु अधिकारी को सत्ता सौंप दी गई। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भाजपा में तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरा दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके पहले हिमंजा बिस्व सरमा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और वो दूसरी बार असम के सीएम बन गए हैं। दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने लालू यादव की आरजेडी से राजनीति की शुरुआत की है। तीसरे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से भाजपा में आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह भगवा में रम चुके हैं।

शुभेंदु के तेवर तल्ख

सीएम की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक कह दिया जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, यानी उनका साफ कहना है कि हमें हिंदुओं ने वोट दिया है इसलिए वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे। शुभेंदु ने सत्ता संभालते ही ममता के लिए वसूली करने वाले अफसरों को बदल डाला। पुलिस को साफ कह दिया कि टोलाबाजी बंद, कटमनी बंद, भ्रष्टाचार बंद, गुंडागर्दी बंद, अतिक्रमण बंद, अपराध पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। बंगाल के सीएम ने पेशेवर अपराधियों की फाइलें भी खोल दी हैं। ये वही शुभेंदु हैं जिन्होंने भाजपा को पश्चिम बंगाल में 3 से 77 पर और 77 से 207 तक पहुंचाया है। इसलिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खास हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने हैट्रिक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। असम में एनडीए को 102 सीटें मिली है। पुडुचेरी में एनडीए ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री एन.रंगासामी के नेतृत्व में गठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। यहां 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास

ममता दीदी खुद अपनी भवानीपुर सीट 15 हजार से अधिक वोटों से हार गई, मतलब उनकी हालत दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जैसी हो गई, वो सीएम तो छोड़ों विधानसभा में प्रवेश करने लायक भी नहीं रही, 2026 ममता बनर्जी के लिए आत्मचिंतन का चुनाव साबित हुआ है, उनका 15 साल का मजबूत किला आखिर भाजपा ने ध्वस्त कर दिया।

रचा है। बंगाल का ट्रेंड रहा है कि राज्य में जब भी परिवर्तन हुआ तब मतदान प्रतिशत बढ़ा है और जिसे सत्ता सौंपी उसे मजबूत बहुमत दिया है। बंगाल से ममता सरकार की 15 साल बाद ऐसी विदाई होगी ये खुद ममता ने नहीं सोचा था। टीएमसी गठबंधन सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकी। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट 15 हजार से अधिक वोटों से हार गई। मतलब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जैसी हालत हो गई, वो सीएम तो छोड़ो विधानसभा में प्रवेश करने लायक भी नहीं रही। केरलम जिसे लंबे समय से वाम दलों का गढ़ माना जाता रहा, वहां इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में वापसी की है, लेकिन कांग्रेस को सीएम का चयन करने में पसीने छूट गए। सीएम के चयन के लिए प्रियंका और राहुल में ठन गई। दोनों अपने अपने करीबी को सीएम बनाने पर अड़ गए। चुनाव नतीजे आने के 15 दिन बाद तक केरलम में सीएम नहीं बन पाया था।

ममता को दूसरी बार हराया शुभेंदु ने

पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर सभी की नजरें टिकी थीं। यहां भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दूसरी बार सीधी चुनौती दी। भवानीपुर में जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने नामाकंन कराया था उस दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ थे। अमित शाह के कहने पर ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से नामाकंन कराया था। उसी दिन अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को भाजपा की जीत का शॉटकट बता दिया था। शाह ने कहा था कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को जिता दो पूरा पश्चिम बंगाल जीत जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1,956 वोटों से हरा चुके थे। इसलिए अमित शाह को भरोसा था कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही हरा सकते हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से ममता के मुकाबले पर उतारा गया। नतीजा चौकाने वाला आया ममता बनर्जी इस बार 15104 वोटों के बड़े अंतर से हार गई। एक स्ट्रीट फाइटर मुख्यमंत्री के लिए यह शर्मनाक हार कही जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी की गारंटी रही। ऊपर से पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की चुनावी सभाओं ने चुनावी हवा का रुख भाजपा की तरफ मोड़ दिया। पहली बार पीएम मोदी ने झालमूड़ी खाई और बंगाल भगवा हो गया।

असम में हिमंता की हैट्रिक

असम में भाजपा हैट्रिक लगा चुकी है और एक बार फिर हिमंता बिस्व सरमा की सरकार आ चुकी है। असम की जनता को हिमंता की योजनाएं, उनके राजनीति करने का स्टाइल बहुत पसंद है, यानी जो बोलना है सीधा बोलना है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमटकर रह गई। खुद कांग्रेस के सीएम चेहरा गौरव गोगोई अपनी मजबूत जोरहाज विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता दिया। यहां कांग्रेस की शर्मनाक हार के लिए उसके ही राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी बड़ा फेक्टर बने। एक तरह से पवन खेड़ा ने कांग्रेस के लिए चुनावी बखेड़ा खड़ा कर दिया था।

तमिलनाडु से भाजपा को उम्मीद

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बदलाव हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राज्य की पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों को जनता ने नकार दिया और अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके पर भरोसा जताया। टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़कर 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में 108 सीटों पर कब्जा जमाया है। भले ही स्टालिन की सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता से दूर रह गए। विजय अकेले तो सरकार बना नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। डीएमके गठबंधन सिर्फ 73 सीटें ही जीत सका। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन खुद कोलाथुर

- **असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता दिया, क्योंकि एआईयूडीएफ के मुकाबले कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर बदरुद्दीन की पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है।**
- **एक्टर विजय की टीवीके पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में 108 सीटें जीत ली, टीवीके ने तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर स्टालिन की सत्ता को उखाड़ फेंका, डीएमके गठबंधन सिर्फ 73 सीटें ही जीत सका, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन खुद कोलाथुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए।**

विधानसभा सीट से हार गए। भाजपा गठबंधन वाले एआईएडीएमके को 53 सीटें मिली हैं।

भाजपा अगला टारगेट केरलम

केरलम विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। एलडीएफ के 21 में से 13 मंत्री हार गए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत कुल 8 मंत्री किसी तरह जीत सके। कुल मिलाकर ये नतीजे एलडीएफ के लिए निराशाजनक हैं। केरलम में एलडीएफ की हार के बाद देश के सभी राज्यों से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया। हालांकि केरलम का चुनाव कांग्रेस के लिए राहत लेकर आया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 89 सीटों पर कब्जा कर वाम मोर्चे की 10 साल की सत्ता को उखाड़ दिया। एलडीएफ 35 विधानसभा सीटों पर सिमट गया, भाजपा गठबंधन का प्रदर्शन केरलम में भले ही कोई खास नहीं रहा हो, लेकिन भाजपा गठबंधन ने तीन सीटें जीत कर केरलम की धरती पर पैर रख दिया है। भाजपा सत्ता के लिए उतावली नहीं रहती बल्कि पश्चिम बंगाल में 2016 में 3 सीटें ही जीती थी। इसके बाद 2021 में भाजपा 3 सीटों से 77 पर पहुंच गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा का अगला टारगेट केरलम ही होगा। क्योंकि कांग्रेस को हराना भाजपा के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जबकि बंगाल में ममता को हराना कठिन था। हालांकि केरलम का किला भेदने के लिए भाजपा को कड़ी मेहनत करनी होगी।

पुडुचेरी में एनडीए की वापसी

केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की शानदार वापसी की है। 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई है। वहीं टीवीके तीन सीटें जीत सका है। इस चुनाव में यह साफ हो गया कि पुडुचेरी को एनडीए का विजन वोटर्स को खूब पसंद आया है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिले जनादेश के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस चुनाव की खासियत रिकॉर्ड मतदान और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रहा। उन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों व चुनाव से जुड़े हर बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 'अब पश्चिम बंगाल भयमुक्त हो गया है।' यह बदलाव का समय है, बदले का नहीं। उन्होंने सभी दलों से राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को त्यागने और राज्य के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन (संशोधन) विधेयक का विरोध की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को कड़ी सजा मिल रही है। बंगाल में टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण सीएम ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी है। जो नेता के रूप में माफिया डॉन बन गया था। सारी लूटपाट, अवैध वसूली, गौ तस्करी, टोलाबाजी महिला उत्पीड़न अभिषेक के संरक्षण में हो रहा था। भयमुक्त माहौल मिला तो पब्लिक ने तानाशाह सरकार का अंत कर दिया।

राहुल गांधी या राउल विंसी?

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर ही विवाद नहीं है, उनके नाम को लेकर भी विवाद है, उनका असली नाम राहुल गांधी है या 'राउल विंसी'? यह राज भी उनकी दोहरी नागरिकता वाले विवाद से जुड़ा है। यदि एलओपी और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के असली नाम के साथ दोहरी नागरिकता सही साबित हुई तो क्या उन्हें देश का पहला फ्रॉड नेता माना जाएगा?

डा.भारत भूषण
आईएफटीएम

भारतीय राजनीति में गांधी परिवार के चश्म-ओ-चराग, कुलदीपक और वंशज यानी राहुल गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे फूहड़, बदजुबान, उदंड, और असभ्य नेता के रूप में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो तो कोई अनपढ़ भी शायद नहीं बोलता होगा। उनकी भाषा उनके घमंड व अहंकार को नहीं बल्कि उनके फ्रस्टेशन, कुंठा और हताशा का प्रदर्शन करती है। वैसे राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ही विवाद नहीं है, उनके नाम को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। उनका असली नाम राहुल गांधी है या फिर 'राउल विंसी'? यदि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के असली नाम के साथ दोहरी नागरिकता सही साबित हुई तो उन्हें देश का क्या पहला सबसे बड़ा फ्रॉड नेता नहीं माना जाएगा? क्योंकि 17 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया और कुछ ही घंटों बाद अपने ही आदेश पलट दिया। आदेश पटने के पीछे तर्क दिया गया कि राहुल गांधी का पक्ष सुने बगैर एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं है, लिहाजा पहले नोटिस जारी कर राहुल गांधी का पक्ष सुना जाएगा। इसके बाद एक नया विवाद खड़ा हुआ और राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित याचिका की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी अचानक खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि क्या न्यायमूर्ति को याचिका पर सुनवाई के समय समझ नहीं आया कि राहुल गांधी का पक्ष सुनना भी आवश्यक है? इसलिए न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। खैर अब इस प्रकरण की सुनवाई दूसरी खंडपीठ करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम नागरिकों के लिए भी इस तरह की सुविधा न्यायपालिका में है? क्या रसूखदारों और गरीबों के लिए कानून अलग है? क्योंकि आम गरीब इंसान तो न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाकर थक जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता।

याचिकाकर्ता ने उठाए कोर्ट पर सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस विद्यार्थी ने पिछले हफ्ते राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में कोर्ट ने अपने ही इस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 17 अप्रैल को कहा था कि पहली नजर में मामला बनता दिख रहा है और राज्य सरकार चाहे तो इसे केंद्र सरकार के पास भेज सकती है। मगर बाद में उन्होंने खुद अपने आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस को ऐसा कोई भी निर्देश देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या इस मामले में राहुल गांधी का पक्ष सुना जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद इस केस की सुनवाई से अलग करने का फैसला भी किया है। मतलब अब कोई दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग क्यों क्या? दरअसल याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये नाराजगी जताई थी कि कोर्ट ने आदेश को वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया है? जबकि आदेश अपलोड न होने का वाजिब कारण रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन याचिकाकर्ता के पोस्ट से ऐसा लग रहा है जैसे वह कोर्ट की नीयत पर शक कर रहा है और ऐसा लगा रहा कि उसका न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। इस पर जस्टिस विद्यार्थी ने आपत्ति की कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर लोगों से सलाह मांगी है कि क्या उसे अदालत से राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने की मांग करनी चाहिए या नहीं। कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय सोशल मीडिया पर अदालत की आलोचना कर रहा है और केस से जुड़े फैसलों पर जनता की राय ले रहा है। जो कि गलत है। याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जो संकेत मिलता है कि उसने पहले कोर्ट पर आरोप लगाए। फिर उसने जनमत मांगा है कि क्या उसे इस मामले को इस अदालत के समक्ष आगे बढ़ाना चाहिए इसलिए इस मामले की आगे सुनवाई करना उचित नहीं होगा।

क्या ब्रिटिश के वोटर हैं राहुल?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम का राज उनकी दोहरी नागरिकता में ही छिपा है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर पहले भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सवाल उठाया था। इसके बाद कर्नाटक के भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने पहले रायबरेली की निचली अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता विग्नेश का दावा है कि राहुल गांधी का नाम यूनाइटेड किंगडम के मतदाता के रूप में भी दर्ज रहा है, जो उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े करता है। भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के 28 जनवरी के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। जबकि 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला जांच के दायरे में आता है। अदालत ने योगी सरकार को निर्देश दिया था कि वह स्वयं इस मामले की जांच कराए या फिर इसे किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दे। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने यह भी कहा था कि यदि इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होती है, तो राज्य सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह आगे की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकती है। बाद में न्यायमूर्ति ने खुद ही अपने आदेश पर रोक लगा दी।

क्या राहुल ब्रिटिश के नागरिक भी हैं?

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला शुरुआत में रायबरेली की विशेष अदालत में दायर किया गया था, जहां कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। याचिकाकर्ता की अपील पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को यह केस रायबरेली से लखनऊ की एमपी एएमलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नागरिकता से जुड़े विवादों पर फैसला लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। विशेष अदालत के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए विस्तृत जांच की मांग की थी। विग्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार से जुड़े कुछ दस्तावेज और ईमेल मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की तरफ इशारा करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने और लोकसभा सदस्य बने रहने के पात्र नहीं हैं।

भारत में सिर्फ एकल नागरिकता

दोहरी-नागरिकता का मतलब है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ दो या अधिक देशों का नागरिक माना जाता है। इससे उन्हें प्रत्येक देश के पासपोर्ट रखने, अन्य नागरिकों के समान कानूनी और सामाजिक अधिकारों का आनंद लेने, दोनों देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने और किसी भी देश में काम करने की अनुमति मिलती है। कई देश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इजरायल और पाकिस्तान दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। हालांकि इस स्थिति के रूल्स और रेगुलेशन देशों के बीच काफी अगल होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत भी दोहरी नागरिकता देता है? तो इसका साफ और सपाट जबाव है, नहीं। भारत अपने संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता। भारत के संविधान के तहत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करना होगा और भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी। हालांकि भारत दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रदान करता है। ओसीआई उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रवास नहीं किया है। योग्य आवेदकों के पास किसी ऐसे देश की नागरिकता होनी चाहिए जो किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्य, जीवन भर के वीजा मिलते हैं। ओसीआई कार्ड धारकों को किसी भी अवधि के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट मिलती है। उन्हें वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार मिलते हैं, सिवाय कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण के। हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने,

- **इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जस्टिस विद्यार्थी ने पिछले हफ्ते राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, बाद में कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी।**
- **भारत अपने संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता, भारतीय के संविधान के तहत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।**

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता है।

गृह मंत्रालय ने नहीं दी थी जानकारी

जिस समय राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का प्रकरण सामने आया था तब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। तब एक नागरिक ने सूचना का अधिकार एक्ट (आरटीआई) के माध्यम से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से संबंधित जानकारी मांगी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) और (जे) के तहत ऐसे किसी मामले का कोई खुलासा नहीं किया जा सकता। जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। वैसे एक सच ये भी है कि सबसे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2015 में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया था और उनकी दोहरी नागरिकता की शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि राहुल यूके में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक और सचिव पद पर रहे हैं। कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक के सालाना रिटर्न में राहुल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश और जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है। सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। राहुल को ब्रिटिश नागरिक होने के आरोपों पर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाएं। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रिटिश नागरिक हो गए।

राहुल गांधी ही क्या 'राउल विंसी' है?

गांधी परिवार के कुलदीपक राहुल गांधी ही क्या 'राउल विंसी' है? क्या वो अपनी पहचान छिपाकर देश के साथ धोखा कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर फर्जी नाम से देश को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का वास्तविक नाम 'राउल विंसी' है राहुल के इस छल को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने कानपुर देहात के घाटमपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, कि 'कांग्रेस के जिस नामदार को देश राहुल गांधी के तौर पर जानता है, उसका वास्तविक नाम तो राहुल गांधी है ही नहीं, देश को राहुल गांधी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता रहा है। जबकि उसका असली नाम तो 'राउल विंसी' है मुझे आश्चर्य होता है कि देश की आंखों में धूल झोंकने का कितना बड़ा पाप कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का वास्तविक नाम देश की जनता के सामने आना ही चाहिए। सीएम योगी ने कहा था कि 'ब्रिटेन और इटली जाकर खुद को 'राउल विंसी' कहेंगे और भारत में आकर फर्जी नाम से राहुल गांधी बन जाएंगे। इनके तो पूर्वज भी कहते थे कि वे 'एक्सीडेंटल हिंदू' हैं, लेकिन यहां पर खुद को हिंदू दिखाने का काम करेंगे। देश इसको अब स्वीकार नहीं करेगा। ●

'बगावत' या राष्ट्रहित?

आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और कमल नाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नकारात्मक राजनीति की धज्जियां उड़ा दी, एक तरह से राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की है कि उन्हें अभी राजनीति की समझ नहीं है न ही उन्हें विदेश नीति व कूटनीति का ज्ञान है, इन नेताओं ने मोदी की विदेश नीति व कूटनीति की तारीफ की है।

5

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

राज्यों में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। पहले शशि थरूर और अब आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और कमल नाथ जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर ने मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नकारात्मक बयानबाजी और राजनीति की धज्जियां उड़ा दी। एक तरह से राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की है कि उन्हें अभी राजनीति की समझ नहीं है न ही उन्हें विदेश नीति व कूटनीति का ज्ञान है। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आनंद शर्मा सहित चारों नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे के बयानों से अलग राय रखते हुए पश्चिम एशिया संकट में भारत की विदेश नीति और कूटनीति की तारीफ करते हुए देश हित में बताया। जिससे कांग्रेस की अंदरूनी मुश्किलें और क्लेश बढ़ गया है। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा है कि मौजूदा हालात में भारत को आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ और अपने रणनीतिक साझेदार देशों को साथ लाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए पश्चिम एशिया संकट पर अपना नजरिया स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता, आर्थिक और ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत सहित वे सभी देश जो कच्चा तेल, गैस और एलपीजी के लिए मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खासकर तब जब स्टेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। यह मुश्किल समय हमारी नीतियों और कूटनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। भारत के खाड़ी देशों के साथ पुराने संबंध हैं और ईरान के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

आंनद शर्मा ने दिखाया आइना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लिखा है कि तेल और गैस के अलावा, लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार, एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और विदेश से आने वाली लगभग 60 प्रतिशत कमाई को (रेमिटेंस) भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट में भारत की कूटनीति समझदारी और संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी समय पर दे दी है। यह बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देशहित में एकजुट और समझदारी का रवैया बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर आगे लिखा कि इस युद्ध ने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, बाजारों में गिरावट और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां सामने हैं, जिनका तुरंत और लंबे समय तक समाधान करना होगा। इस संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। जब वैश्विक व्यवस्था और नियम टूट रहे हों तब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। भारत हमेशा से शांति और नैतिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन आज बहुत कुछ दाव पर लगा है, खासकर युवाओं का भविष्य। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह ग्लोबल साउथ और अपने साझेदार देशों को साथ लेकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करे। इससे पहले पार्टी के मौजूदा सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी, दोनों ने ही पश्चिम एशिया संकट पर भारत की विदेश नीति को सही ठहराया और खाड़ी देशों में रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा करते हुए स्थिति के कुशल प्रबंधन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

शशि थरूर के मुताबिक भारत की इस कूटनीति का उद्देश्य तय है, वैश्विक न्याय की बात करते हुए भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखना, गांधी और नेहरू की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि उनके मूल्यों को समय के हिसाब से बुद्धिमानी से अपनाने की है, न कि ऐसे आत्म-संतोषी निंदाओं में जो राष्ट्रहित को खतरे में डाल सकती है।

प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं

इसके विपरीत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो जो मन में आता है वो बोलते हैं, ना तो राहुल गांधी राजनीतिक समझ है और न ही विदेश नीति और कूटनीति का ज्ञान है। घमंड इतना है कि वो रैलियों में पीएम मोदी के लिए आम तौर पर तू-तड़ाक की भाषा का उपयोग कर खुद को मोदी से बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। ये कम से कम भारतीय संस्कार नहीं हो सकते। हालांकि उनका एक ही टारगेट है वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दा कोई भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित हो या न हो लेकिन जब तक वो हर मुद्दे के बीच में मोदी का नाम नहीं लेते तब तक उनकी बात पूरी नहीं होती। पश्चिम एशिया संकट के दौरान राहुल गांधी सिर्फ एक ही टेप बजा रहे हैं-जो अमेरिका और इजरायल कहेगा पीएम नरेंद्र मोदी वही करेंगे। वो हिंदुस्तान के हित में काम नहीं करेंगे, किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा है कि 'हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। अब यह एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है लोगों को इसका नुकसान होगा। अभी केवल शुरुआत हुई है। अभी सभी चीजों में परेशानी होगी। अमेरिका और इजरायल जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वहीं करेंगे।' राहुल गांधी का दावा है कि आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल को लेकर समस्या आएगी। यानी राहुल गांधी भविष्य को लेकर पैनिक फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पश्चिम एशिया को लेकर कितने चिंतित हैं इसका एक उदहारण ये है कि सरकार ने जब ऑल पार्टी मिटिंग बुलाई तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो मिटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। राहुल गांधी एंड कंपनी ने 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो देश में रसोई गैस और डीजल व पेट्रोल को लेकर पैनिक फैलाना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर राहुल गांधी वो नेता है जो संकट के समय भी मोदी को हटाने और सत्ता पाने के लिए बेचैन रहते हैं। उनकी इस नकारात्मकता की वजह से ही कांग्रेस खोखली हो चुकी है।

कांग्रेसी कर रहे मोदी की कूटनीति की तारीफ

एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं, नरेंद्र सरेंडर का नारा बुलंद करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद मनीष तिवारी पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच केंद्र सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हैं। सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि भारत इस संघर्ष में एक सीमित भूमिका वाला देश रहा है और सरकार का सतर्क रुख बिल्कुल सही है। मनीष तिवारी ने कहा, 'यह समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया में सिर्फ एक युद्ध नहीं चल रहा है, बल्कि कई तरह के संघर्ष एक साथ हो रहे हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति है वह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि बड़े वैश्विक समीकरणों से जुड़ी है। फिर यह हमारी लड़ाई नहीं है।' 'हम हमेशा से इस क्षेत्र में एक सीमित भूमिका निभाते आए हैं। भारत को अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखनी चाहिए। अगर हम सोच-समझकर और सावधानी से कदम उठाते हैं, तो हम सही दिशा में हैं। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है अपने हितों की रक्षा करना और हालात के अनुसार संतुलन बनाकर चलना है।' इसी मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद व वरिष्ठ नेता नशशि थरूर ने भी सरकार के रुख की सराहना की है। उन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' में

राहुल गांधी में ना तो राजनीतिक समझ है और न ही विदेश नीति और कूटनीति का ज्ञान है, घमंड इतना है कि वो रैलियों व सभाओं में पीएम मोदी के लिए आम तौर पर तू-तड़ाक की भाषा का उपयोग कर खुद को मोदी से बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ये कम से कम भारतीय संस्कार तो नहीं हो सकते।

लेख ही लिखा डाला। लेख के माध्यम से कहा कि यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता और यह संप्रभुता और गैर-आक्रामकता के उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिनका भारत हमेशा समर्थन करता आया है। भारत ने इस पूरे संकट के दौरान लगातार बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट पर भारत सरकार के स्टैंड का खुलकर समर्थन किया है। थरूर पहले इस पर मीडिया में छिटपुट बोलते रहे हैं, लेकिन अब लेख लिखकर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों को जमीनी हालात और राष्ट्रहित में नई रणनीति के बारे में समझाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में राजनियक रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईरान युद्ध में भारत द्वारा अपनाई गई कूटनीति पर सवाल खड़े करने की भारतीय लिबरल्स की कोशिशों को आईना दिखाया है। थरूर ने लेख में लिखा है कि उनके जैसे जिन लोगों ने पश्चिम एशिया युद्ध पर सरकार की नीति की निंदा नहीं की, लिबरल्स उन्हीं पर निशाना साधने में लगे हैं। वे इसे नैतिक कायरता कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम यह मांग करें कि भारत नैतिक श्रेष्ठता दिखाते हुए युद्ध को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन घोषित करे। लेकिन मैं इस संघर्ष पर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं करूंगा। भारत की कूटनीति हमेशा ही सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन पर आधारित रहती है। जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता वाली नीति शीत युद्ध के समय शत्रुता में उलझने की जगह भारत की संप्रभुता और अस्तित्व पर आधारित थी। इस तरह से आज बहुध्रुवीय विश्व में भारत अलग-अलग ताकतों के साथ संबंध बनाकर चल रहा है, चाहे वे एक-दूसरे के दुश्मन ही क्यों न हों, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। शशि थरूर के मुताबिक भारत की इस कूटनीति का उद्देश्य तय है, वैश्विक न्याय की बात करते हुए भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखना। गांधी और नेहरू की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि उनके मूल्यों को समय के हिसाब से बुद्धिमानी से अपनाने की है, न कि ऐसे आत्म-संतोषी निंदाओं में जो राष्ट्रहित को खतरे में डाल सकती है।

लिबरल्स कर रहे युद्ध निंदा की मांग

शशि थरूर ने साफ शब्दों में बताया है कि जब भी राष्ट्रहित का टकराव सिद्धांतों से हुआ है, भारत ने चुप्पी को ही अपना हथियार बनाया है। इसके लिए उन्होंने सोवियत संघ द्वारा हंगरी (1956), चेकोस्लोवाकिया (1968) और अफगानिस्तान (1979) में किए गए अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों का उदाहरण दिया है, जिसकी निंदा करने से हमने बचने की कोशिश की थी। क्योंकि मास्को के साथ अपने रिश्तों को हम खतरे में डालने का जोखिम नहीं ले सकते थे। तब सोवियत आक्रमण पर हमारी चुप्पी का यह मतलब था कि हमने उसका समर्थन किया और अब न ही यूक्रेन में रूस के हमले का तथा ईरान पर इजरायल-अमेरिका के अटैक का समर्थन किया है। जो भारतीय लिबरल्स युद्ध की निंदा की मांग करते हैं, मोरल ऐब्सलूटिज्म को ही नैतिक साहस समझ बैठते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि विदेश नीति कोई शैक्षणिक सेमिनार नहीं है। यहां सिद्धांतों को शक्ति का सामना करना होता है और लिए गए फैसलों से लाखों जीवन प्रभावित होते हैं। परिणामों की परवाह किए बगैर निंदा पर अड़े रहना, जिम्मेदारी की कीमत पर सिर्फ बयानबाजी के विलास में लिप्त रहना है। भारत का न सिर्फ अमेरिका के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, बल्कि खाड़ी देशों में हमारा बहुत बड़ा हित दांव पर है, जहां ईरान अभी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। करीब 200 बिलियन डॉलर का सालाना व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। हमारी ऊर्जी सुरक्षा खाड़ी के तेल और गैस पर निर्भर है। वहीं इस क्षेत्र में 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा की भी चिंता है। भारत ने हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक न्याय की आवाज बुलंद की है और हमें पता है कि संवेदनशील मुद्दों पर कब चुप रहना ही उचित है। जियोपॉलिटिक्स की इसी सच्चाई को समझना जरूरी है। इसलिए यह नैतिक सरेंडर नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदार कूटनीति है।

वन्यजीवों की जान आफत में

उत्तराखंड में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून रहता है, सीजन में बस्तियों से ज्यादा आग जंगलों में लगती है, वनाग्नि की रोकथाम के लिए सरकार भी हर साल बजट की व्यवस्था करती है ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके, लेकिन सरकारी बजट कहां खर्च होता है यह बताने की जरूरत नहीं है, वनाग्नि की रोक थाम के लिए मॉक ड्रिल हो या अन्य कार्य सब फोटो सेशन तक सिमट कर रह जाते हैं।

डा.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर से करीब 54 किलोमीटर दूर अस्कोट्कस्तूरीमृग अभयारण्य है। समुद्र तल से करीब 5412 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस अभयारण्य की स्थापना 1986 में कस्तूरी मृगों (मोस्कस ल्यूकोगैस्टर) के आवास व संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा अभयारण्य बनाने का मूल उद्देश्य क्षेत्र की दुर्लभ वनस्पतियों और वन्यजीवों की वृहद जैव विविधता का संरक्षण करना भी था।600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस अभयारण्य में करीब 67 कस्तूरी मृग हैं। यह मृग अभयारण्य वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां कस्तूरी मृगों के अलावा हिम तेंदुए, हिमालयन थार, ब्लू भेड़, सेरोव, चाइर, काकड़, घोरड़, हिमालयी काले भालू, फेशियंस, चूकर्स, तहर, भरल और कोक्लासों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना है। इस क्षेत्र में ही कई छोटे स्तनधारी वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। यह अभयारण्य सागौन और नीलगिरी के घने जंगलों व बर्फीले पहाड़ों के बीच है। इस अभयारण्य से पंचचुली, नौकना पहाड़ और हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। अभयारण्य के पास ही धौली और इकली नदियों का उद्गम स्थल भी है। अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य की स्थापना लुप्त हो रहे कस्तूरी मृग के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। किंतु गर्मी बढ़ते ही प्रदेश के जंगल आग में धधकने लगते हैं। आग इतनी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रही है कि जंगल के आसपास रहने वाले परिवार भी दहशत में हैं। इस आग की चपेट में अस्कोट का कस्तूरी मृग अभयारण्य भी है। जिससे कस्तूरी मृग के साथ अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की जान आफत में पड़ गई है। वनस्पतियों और वन्य संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक होता है। इस सीजन में बस्तियों से ज्यादा आग की घटनाएं जंगल में होती है। क्योंकि सूखी घास और पत्तों में आग तेजी से फैलती है। वनाग्नि की रोकथाम के लिए सरकार हर साल बजट की व्यवस्था भी करती है ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके, लेकिन सरकारी बजट कहां खर्च होता है यह बताने की जरूरत नहीं है। वनाग्नि की रोक थाम के लिए मॉक ड्रिल हो या अन्य कार्य सब फोटो सेशन तक सिमट कर रह जाते हैं।

जंगलों में आग लगती है या लगाई जाती है यह बड़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि कई बार ग्रामीण सूखी घास में आग लगाते हैं ताकि पशुओं का पेट भरने के लिए बरसात में पर्याप्त चारा मिल सके, यही आग फिर जंगल में फैलती है,कई बार लकड़ी माफिया और वन्यजीव शिकारी भी आग लगाने का काम करते हैं।

हर साल आग में झुलसते है वन्यजीव

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में वनाग्नि लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने, सूखी पत्तियों और तेज हवाओं के कारण जंगलों में आग विकराल रूप ले लेती है। 2026 के फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस बार आग की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। आग की घटनाएं बढ़ेगी तो न सिर्फ जंगल जलेंगे बल्कि वन्यजीव, वनस्पति, वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचेगा। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया तो पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में ऐसी आग लगी जिसने जंगल जलकर राख हो रहे हैं। बेरीनाग, गंगोलीहाट, गणाई, थल, डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला सहित बागेश्वर जिले के धरमघर, कपकोट, कांडा और गरुड़ क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी है। जिससे एक तरफ अमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो रही है तो दूसरी ओर आग से पर्यावरण दूषित हो रहा है। जिससे स्थानीय निवासियों की सेहत को खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि वनाग्नि के कारण चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। जंगलों की लगी आग का धुआं आबादी तक फैल चुका है। इन हालात ने वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हैं। आग लगती है या जानबूझ कर लगाई जाती है यह बड़ी बहस का मुद्दा है। क्योंकि कई बार ग्रामीण सूखी घास में आग लगाते हैं ताकि पशुओं का पेट भरने के लिए बरसात में पर्याप्त चारा मिल सके। यही आग फिर जंगल में फैलती है। कई बार लकड़ी माफिया और वन्यजीव शिकारी आग लगाने का काम करते हैं। खैर इस पर अलग से बहस हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए कैम्पा परियोजना संचालन समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 339 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है, जिसमें वनाग्नि रोकथाम के कार्य भी शामिल हैं।

उत्तराखंड में वन विभाग की फायर लाइन चोक

वनाग्नि के नाम पर हर साल सरकार और वन विभाग करोड़ों रुपये फूंक देते हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है। उत्तराखंड का वन विभाग भी बाकी देशों की तरह जंगल की आग पर काबू पाने के नए-नए तरीके खोज रहा है। लेकिन सालों पुरानी तरकीब भूलता जा रहा है। इसका नतीजा वन्यजीवों और प्रदेश की जनता को भुगताना पड़ रहा है। वन विभाग तब सक्रिय होता है, जब जंगलों में आग विकराल रूप लेने लगती हैं। तब आनन-फानन में फायर लाइन को साफ करने का काम वन विभाग के कर्मचारी शुरू करते हैं। फायर लाइन तैयार की जाती हैं। राज्य में फायर लाइन की स्थिति देखें तो 2876.49 किलोमीटर क्षेत्र में 100 फीट की फायर लाइन बनी हुई है। 50 फीट की फायर लाइन की लंबाई 2520 किलोमीटर है, जबकि 30 फीट की फायर लाइन 1333.43 किलोमीटर तक फैली है। क्षेत्र के लिहाज से देखें तो कुमाऊं जोन में करीब 3000 किलोमीटर क्षेत्र में फायर लाइन है। गढ़वाल जोन में करीब 2500 किलोमीटर फायर लाइन है। वन्यजीव क्षेत्र में 1100 किलोमीटर फायर लाइन है।हालांकि राज्य में फायर लाइन बनाने को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। 1000 मीटर से ऊपर पहाड़ों पर पेड़ के काटने पर सख्त रोक है। लिहाजा यहां नई फायर लाइन नहीं बनाई जा सकती। वैसे सच ये भी है कि वन विभाग जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए 12 महीने काम नहीं करता। इसलिए राज्य की करीब 12 हजार किलोमीटर से ज्यादा फायर लाइन साफ नहीं हो पाती। जबकि राज्य में चीड़ के जंगल बहुत हैं। इनकी ज्वलनशील पत्तियां फायर लाइन में भर जाती हैं। जिससे फायर लाइन का महत्व ही खत्म हो जाता है। वन विभाग की इसी लापरवाही से फायर लाइन में कई जगह पेड़ भी उग गए हैं, जिन्हें काटने की पाबंदी है। इसलिए आग बुझाने का यह पारंपरिक तरीका भी फेल होता जा रहा है।

मॉक ड्रिल का क्या फायदा

वन विभाग फायर सीजन से पहले मॉक ड्रिल करता है। फिर भी अधिकांश स्थानों पर जंगल जल रहे होते हैं और मॉक ड्रिल करने वाला महकमा बेबस नजर आता है। अलबत्ता कुछ स्थानों पर वन विभाग कमी पुराने आग बुझाने के तरीके से ही आग बुझाते नजर आते हैं। जबकि बहुत से स्थानों पर लगी आग की तरफ वन विभाग देखना भी पसंद नहीं करता। वन विभाग के लिए 15 फरवरी से 15 जून तक का फायर सीजन जंगलों के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है। शीतकाल में यदि अच्छी वर्षा और बर्फबारी हो जाए, तो जंगलों में आग लगने की अवधि पीछे खिसक जाती है। मगर इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा बर्फबारी कम हुई है, जिससे गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगी हैं। अप्रैल में ही आग की घटनाएं अनियंत्रित रूप से सामने आ रही हैं। वनाग्नि की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि पहाड़ों पर चारों और धुआं छाया हुआ है। रात में जंगलों में लगी मैदानी इलाकों तक से देखी जा सकती है। जंगलों की आग जहां एक तरफ पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है, तो वहीं इंसानों के स्वास्थ्य के लिए इसका धुआं बेहद पीड़ादायक है। नई फायर लाइन बनाने में रुचि नहीं होने से भी हर साल वनाग्नि की समस्या विकराल होती जा रही है। लेकिन उत्तराखंड का वन विभाग है कि वो आग बुझाने के खोखले दावे किए जा रहा है। जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वन विभाग क्या वन्यजीवों के साथ वन्य संपदा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं है?

- **उत्तराखंड का वन विभाग भी बाकी देशों की तरह जंगल की आग पर काबू पाने के नए-नए तरीके खोज रहा है, लेकिन सालों पुरानी तरकीब भूलता जा रहा है, इसका परिणाम वन्यजीवों और प्रदेश की जनता को भुगताना पड़ रहा है, वन विभाग तब सक्रिय होता है, जब जंगलों की आग विकराल रूप ले लेती हैं।**
- **फायर सीजन जंगलों के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है, शीतकाल में यदि अच्छी वर्षा और बर्फबारी हो जाए, तो जंगलों में आग लगने की अवधि पीछे खिसक जाती है, मगर इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा बर्फबारी कम हुई है, जिससे गर्मी के शुरुआत में ही वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगी हैं।**

वनाग्नि को लेकर राजनीति

पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने प्रदेश सरकार को जंगल की आग बुझाने में पूरी तरह फेल होने का दावा किया है। उनका कहना है कि वन सम्पदा के नष्ट होने के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वन क्षेत्र के तहत आने वाला अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य धधक रहा है। अभयारण्य में भीषण आग लगने से क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ कस्तूरी मृग के जीवन पर खतरा मंडरा गया है। वनाग्नि ने अभयारण्य के बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लिया है। यदि जंगलों में लगी आग से वन्यजीव आबादी में घुसे तो इससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। यानी वन्यजीव मानव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। विधायक का आरोप है कि दुर्लभ वन्य जीवों के शिकार के लिए भी कुछ शिकारी जंगल में आग लगाते हैं। किंतु हैरानी की बात ये है कि अब तक न तो कोई शिकारी और ना ही आग लगाने वाला वन विभाग की पकड़ में आ सका है। ऐसे में वन विभाग के जंगलों को आग से बचाने और वन्यजीवों की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू का कहना है कि गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। कई स्थानों पर उन्होंने खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को साथ आग बुझाने का प्रयास किया। खजान गुड्डू का आरोप है कि सरकार और सरकार का वन विभाग सिर्फ आग बुझाने के खोखले दावे करता है, जबकि धरातल पर दूर-दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री का दावा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और प्रदेश की जनता अब सिर्फ बारिश का इंतजार कर रही है ताकि पहाड़ों के जंगलों में लगी आग शांत हो सके।

सियासी चेतना का निर्णायक दशक

आलोक इंदौरिया,

दिवाकर शर्मा

पश्चिम बंगाल की राजनीति का 2016 से 2026 तक का कालखंड केवल चुनावी परिणामों का क्रम नहीं है, बल्कि यह उस गहरे सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक परिवर्तन का विस्तृत इतिहास है जिसने राजनीति की पूरी संरचना को बदल दिया। इस दशक ने बंगाल को केवल सत्ता परिवर्तन के दौर से नहीं गुजारा, बल्कि उसने मतदाता की सोच, राजनीतिक दलों की कार्यशैली, वैचारिक संघर्षों और सामाजिक समीकरणों को भी नए रूप में ढाल दिया। यह वो समय है जब बंगाल की राजनीति ने अपने भीतर कई स्तरों पर बदलाव महसूस किया। एक ओर पुरानी राजनीतिक शक्तियां कमजोर होती गईं, तो दूसरी ओर नया राजनीतिक ध्रुव तेजी से उभरा। मतदाता का मानस बदला, राजनीतिक विमर्श बदला, चुनावी रणनीतियां बदलीं और सत्ता प्राप्ति के तरीके बदल गए। कभी बंगाल को वामपंथ की वैचारिक राजधानी कहा जाता था। उससे पहले कांग्रेस यहां की सबसे बड़ी सियासी शक्ति थी। फिर टीएमसी बंगाल की निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित हुई। लेकिन 2016 के बाद शुरू हुआ सियासी परिवर्तन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता का बदलाव था जिसमें जनता ने पहली बार महसूस किया कि बंगाल की राजनीति को एक नए मार्ग की जरूरत है। यह वो कालखंड है जब बंगाल की राजनीति 'विचारधारा आधारित स्थिरता' से निकलकर 'परिणाम आधारित प्रतिस्पर्धा' में बदल गई। जनता अब केवल राजनीतिक इतिहास और पुराने संघर्षों को देखकर मतदान नहीं कर रही, बल्कि वह अपने भविष्य को ध्यान में रखकर राजनीतिक विकल्प चुनने लगी है।

टीएमसी का चरम

2016 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के राजनीतिक प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक रहा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 211 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। उस समय ऐसा लगा कि बंगाल में टीएमसी को चुनौती देने वाला कोई विपक्ष मौजूद नहीं है। वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में थे, लेकिन उनकी राजनीतिक ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। भाजपा उस समय सीमित प्रभाव वाली पार्टी थी, जिसके पास केवल कुछ क्षेत्रों में सीमित समर्थन था। राजनीतिक भूगोल स्पष्ट था। दक्षिण बंगाल में तृणमूल का दबदबा था, जबकि उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी की संगठनात्मक पकड़ मजबूत थी। शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उस समय बंगाल की राजनीति को देखकर लगता था कि आने वाले वर्षों तक सत्ता का संतुलन नहीं बदलेगा। लेकिन राजनीतिक इतिहास अक्सर वहीं करवट लेता है जहां स्थिरता सबसे मजबूत दिखाई देती है।

वामपंथ व कांग्रेस का पतन

पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए वामपंथ व कांग्रेस के पतन को समझना आवश्यक है। वाम दल केवल राजनीतिक संगठन नहीं थे, बल्कि उन्होंने दशकों तक बंगाल की सामाजिक और वैचारिक संरचना को प्रभावित किया। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में वामपंथ ने बंगाल को वैचारिक पहचान दी। लेकिन समय के साथ संगठनात्मक जड़ता, उद्योगों के पलायन, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और बदलती सामाजिक आकांक्षाओं ने वाम राजनीति को कमजोर कर दिया। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने वामपंथ की छवि को गहरी चोट पहुंचाई।

इन्हीं आंदोलनों से ममता और शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक उभार हुआ। किंतु सबसे बड़ा संकट यह था कि वाम दल समय के साथ नई पीढ़ी से जुड़ने में विफल रहे। उनका संगठन बूढ़ा हो गया, नेतृत्व सीमित रह गया, जनता के मुद्दों से सीधा संबंध कमजोर पड़ गया। 2016 के बाद यह गिरावट और तेज हो गई। 2021 तक आते-आते स्थिति यह हो गई कि कभी बंगाल की राजनीति पर राज करने वाले वाम दल राजनीतिक शून्य में पहुंच गए। बंगाल मे कांग्रेस कभी राजनीति की मुख्य धुरी होती थी। लेकिन समय के साथ कांग्रेस कमजोर होती गई और उसका जनाधार टूट गया। टीएमसी स्वयं कांग्रेस से निकलकर बनी थी। इसलिए कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक पहले ही तृणमूल के साथ जा चुका था। बाद के वर्षों में जो समर्थन बचा, वह भी तृणमूल के साथ चला गया या भाजपा की ओर झुकने लगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व और संगठन की रही। कांग्रेस बंगाल में ऐसा मजबूत नेतृत्व तैयार नहीं कर सकी जो जनता के बीच विकल्प के रूप में उभर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस प्रतीकात्मक बनकर रह गई।

भाजपा का सत्ता व संगठन का संतुलन

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। पहले इसे केवल एक सीमित सियासी प्रयोग माना गया, लेकिन 2019 में भाजपा बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति बनकर उभरी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए संकेत दिया कि बंगाल का राजनीतिक संतुलन बदल रहा है। यही वह दौर था जब भाजपा ने बंगाल में संगठन का विस्तार तेजी से किया। 2021 तक भाजपा 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई। यह केवल चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि यह बंगाल की राजनीति के ध्रुवीकरण का प्रमाण था। भाजपा ने केवल सियासी मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, राष्ट्रवाद, विकास जैसे विषयों पर बड़ा अभियान चलाया। इससे उसे नए सामाजिक समूहों में समर्थन मिलने लगा। 2024 के बाद यह चर्चा बढ़ी कि पार्टी को नए क्षेत्रों में भी मजबूत आधार बनाना होगा। बंगाल इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना, भाजपा स्थाई संगठनात्मक ढांचा बनाने में सफल हुई। अब भाजपा बंगाल में स्थाई रूप से सत्ता में स्थापित हो गई है लिहाजा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि स्वयं अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुरक्षित रखना है। टीएमसी से आने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या पुराने भाजपाइयों के भीतर आक्रोश पैदा कर सकती है। अवसरवादी राजनीति भाजपा की मूल विचारधारा और अनुशासन को प्रभावित कर सकती है। यही वो बिंदु है जहां भाजपा को सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाना होगा।

जीत वाले विकल्प की राजनीति

बंगाल का मतदाता लंबे समय तक वैचारिक निष्ठा वाला मतदाता रहा है। लेकिन 2016 के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगीं। अब वोटर्स सिर्फ विचारधारा नहीं देख रहा, बल्कि वह ये भी देख रहा है कि कौन सत्ता में आ सकता है, कौन प्रभावी चुनौती दे सकता है और कौन परिणाम दे सकता है। यही कारण था कि वाम और कांग्रेस का वोट बैंक टूटने लगा। मुस्लिम और तथाकथित सेकुलर वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल के साथ गया, जबकि सत्ता विरोधी वोट भाजपा की ओर स्थानांतरित हो गया। यह परिवर्तन केवल गणितीय नहीं था, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। बंगाल की राजनीति पहली बार पूरी तरह द्विध्रुवीय मुकाबले में बदल गई। भाजपा की जीत सिर्फ चुनावी प्रचार का परिणाम नहीं है। इसके पीछे दीर्घकालिक संगठनात्मक रणनीति, बूथ स्तर तक विस्तार, सोशल मीडिया अभियान, केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और सुरक्षा का मुद्दा था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल को केवल एक राज्य चुनाव के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में देखा। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और हिंसा के खिलाफ मजबूत संदेश ने उन मतदाताओं में यकीन पैदा किया जो पहले भय के कारण मतदान ही नहीं करते थे। बंगाल का सत्ता परिवर्तन यह भी दर्शाता है कि भाजपा अब केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रही है। पूर्वी भारत में उसका विस्तार राष्ट्रीय राजनीति के नए संतुलन की ओर संकेत करता है। असम, त्रिपुरा, ओडिशा और बंगाल में भाजपा की उपस्थिति एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन 2016 के बाद यह और अधिक

2016 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के राजनीतिक प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक रहा, ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, तब ऐसा लगा कि बंगाल में टीएमसी को चुनौती देने वाला कोई विपक्ष मौजूद नहीं है, वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन में थे, लेकिन उनकी सियासी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही।

प्रमुख हो गया। भाजपा ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया, जबकि टीएमसी ने बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव को अपना हथियार बनाया। लिहाजा सीमावर्ती जिलों, आदिवासी क्षेत्रों और सामाजिक असुरक्षा वाले इलाकों में यह राजनीति अधिक प्रभावशाली रही।

टीएमसी की तानाशाही

टीएमसी ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्गों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन दूसरी ओर भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, महिला उत्पीड़न, राजनीतिक के अपराधिकरण और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप भी बढ़ते गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर सत्ता के केंद्रीकरण और लोकल नेताओं के प्रभाव को लेकर आक्रोश दिखने लगा। युवाओं में बेरोजगारी और उद्योगों के अभाव को लेकर भी निराशा बढ़ रही थी। बंगाल जो कभी उद्योग और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वहां निवेश और रोजगार के अवसर सीमित हो गए। इससे जनता के एक वर्ग में यह भावना मजबूत हुई कि केवल योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। बंगाल की राजनीति में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी अहम रहा। भाजपा ने इसे सुरक्षा, डेमाग्राफी चेंज और संसाधनों से जुड़े प्रश्न के रूप में उठाया। सीमावर्ती जिलों में यह मुद्दा चुनावी विमर्श का बड़ा हिस्सा बना। वहीं टीएमसी ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में इस मुद्दे का प्रभाव मतदाताओं की सोच पर दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे बंगाल का राजनीतिक इतिहास बेहद कठोर रहा है। यहां जनता सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करती, बल्कि राजनीतिक युग समाप्त कर देती है। कांग्रेस कभी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन आज उसका अस्तित्व संघर्ष में है। वामदल दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन अब हाशिये पर हैं।

चुनाव की प्रभावी ताकत महिलाएं

इस पूरे दशक में महिला मतदाता बंगाल की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरीं। टीएमसी ने महिला केंद्रित योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग में गहरी पकड़ बनाई। लेकिन समय के साथ महिलाओं के सामने केवल आर्थिक सहायता का प्रश्न नहीं रहा। सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, बच्चों का भविष्य और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बनने लगे। ग्रामीण बंगाल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तेजी से बढ़ी। उन्होंने मतदान में निर्णायक भूमिका निभाई और कई क्षेत्रों में चुनावी परिणामों की दिशा तय की। 2016 से 2026 तक का बंगाल यह स्पष्ट करता है कि भारतीय राजनीति अब तेजी से बदल रही है। मतदाता अब केवल परंपरागत विचारधारा, जातीय समीकरण या ऐतिहासिक निष्ठा के आधार पर मतदान नहीं करता। वह सुरक्षा, विकास, पहचान, सम्मान, नेतृत्व और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ देखकर निर्णय लेता है। बंगाल आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक बन चुका है। आने वाले वर्षों में यहां होने वाले परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि बंगाल आज एक प्रश्न बनकर पूरे देश के सामने खड़ा है कि क्या देश की राजनीति अब स्थाई वैचारिक गढ़ों से बाहर निकलकर पूर्ण प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है? यदि हां, तो आने वाले वर्षों में कौन-सा दल जनता के विश्वास, विकास और राष्ट्रीय दृष्टि के बीच सबसे मजबूत संतुलन स्थापित कर पाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर आने वाले समय की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।

बंगाल की राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्ट

रंग बदलता बुग्याल

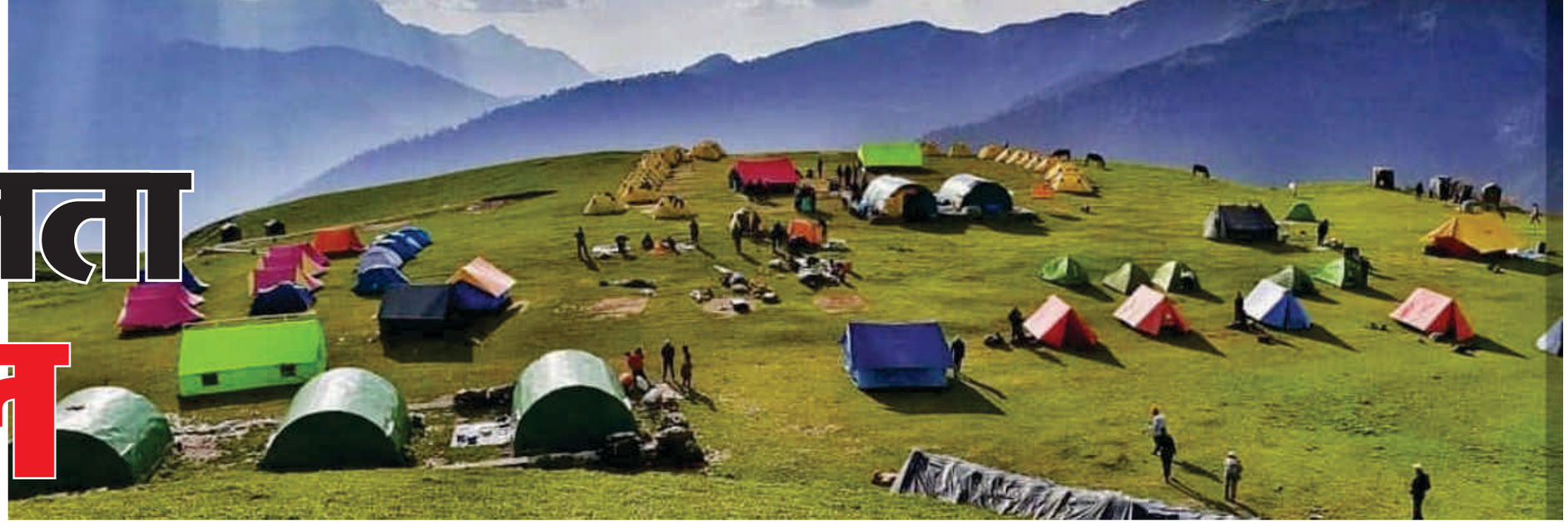

अली-बेदनी बुग्याल ट्रेक, ट्रेकर्स को अंतहीन घास के मैदानों की जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां टूरिस्ट हिमालय की सबसे भव्य चोटियों की सुंदरता को निहारने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं तो फिर नीचे करना भूल जाते हैं, ट्रेकर्स यह तय नहीं कर पाते कि कहां और किधर देखें? क्योंकि ट्रेक की हर दिशा में कुछ न कुछ ऐसा है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

राजेश पांडेय
देहरादून

उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती अद्वितीय और मनमोहक है। पहाड़ों की विशालता, हरियाली, घने जंगल, वादियां, झील और झरनों के साथ शांत वातावरण एक अलग ही सुकून और आनंद का अनुभव कराते हैं। भाग-दौड़ की जिंदगी के बीच सुकून के पल बिताने के लिए सालाना लाखों की संख्या में सैलानी उत्तराखंड की शांत वादियों का रुख करते हैं। बहुत से पर्यटकों को ट्रेकिंग पसंद है तो कुछ को उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन अच्छा लगता है। टूरिस्ट की हर पसंद उत्तराखंड के पहाड़ पूरा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहां धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक पर्यटन की भी बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन जिन्हें ट्रेकिंग पसंद है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के अली बेदानी बुग्याल जा सकते हैं। अली बेदनी बुग्याल का ट्रेक चमोली जिले के मुंडोली गांव में स्थित लोहाजंग बेस कैंप से शुरू होता है। अली और बेदनी बुग्याल जुड़वा हैं। यह उत्तराखंड के विशाल घास के मैदानों में से एक है। यह ट्रेक प्रकृति के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें हरे-भरे घास के मैदान, चरते हुए जानवर, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां, छोटे-छोटे गांव, चरवाहों की झोपड़ियां आदि शामिल हैं। बेदनी बुग्याल चमोली जिले में 3,354 मीटर यानी 11,004 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है। बेदनी बुग्याल, वान गांव के पास रूपकुंड जाने वाले रास्ते पर है। यहां से त्रिशूल और नंदा घुंटी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह हरा-भरा मैदान कई रंगा व प्रजातियों के फूलों का भी संसार है। इस मैदान के बीचोंबीच वैतरणी (बेदनी कुंड) नाम की छोटी झील भी है। बेदनी बुग्याल, रूपकुंड की यात्रा का शिविर स्थल है। यहां हर साल सितंबर और अक्टूबर में नंदा देवी जात का आयोजन किया जाता है।

नौसिखियों के लिए थोड़ा मुश्किल ट्रेक

उत्तराखंड के सभी ट्रेकों में से अली-बेदनी बुग्याल ट्रेक, ट्रेकर्स के लिए सबसे शानदार और अविश्वसनीय यात्रा हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें कठिनाई बहुत है। क्योंकि रास्ता नौसिखियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और 14,600 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करना ट्रेकर्स के लिए कठिन ट्रेक तो बनाता ही है। हालांकि यह ट्रेक 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसका कठिनाई स्तर मध्यम है, लेकिन इससे पहले उन्हें किसी भी प्रकार के ट्रेकिंग का अनुभव होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पहली बार ट्रेकिंग करने वालों या परिवारों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है? इसका जवाब ये है कि हिमालयी ट्रेक को आसान से मध्यम श्रेणी का माना जाता है, इसलिए यह किसी भी परिवार के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह शारीरिक क्षमता और हिमालयी ट्रेकिंग के अनुभव पर निर्भर करता है। ट्रेकिंग के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच होता है, जबकि सामान्य ट्रेकिंग के लिए अप्रैल से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मानसून के समय सड़क की समस्याओं से बचा जा सकता है। इस मनमोहक डेस्टिनेशन की यात्रा की योजना दिसंबर से मार्च के बीच बनाई जा सकती है, क्योंकि इस दौरान यह क्षेत्र सबसे ज्यादा आकर्षक दिखता है। यानी यहां का नजारा कल्पना से परे नजर आता है। बर्फ की चादर से ढके विशाल पहाड़ बेहद मनमोहक दिखते हैं। यह ट्रेक निस्संदेह एक आनंददायक है। फिर भी ट्रेकर्स को पर्याप्त कपड़े और बेहतर गुणवत्ता वाले ट्रेकिंग शूज साथ लाने चाहिए ताकि यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। पहाड़ के घटते बढ़ते तापमान में रहने के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। क्योंकि पर्वतीय तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। वैसे भी यह अधिक ऊंचाई वाला ट्रेक है इसलिए थोड़ी कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए गर्म कपड़े लाना आवश्यक है। हालांकि इस ट्रेक को मध्यम श्रेणी में रखा गया है, फिर भी उचित शारीरिक क्षमता होना आवश्यक है। ट्रेकर्स को बदलते मौसम की स्थितियों के लिए तैयार भी रहना होगा। स्थानीय रीति-रिवाजों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करना और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ट्रेक की हर दिशा खूबसूरत

अली-बेदनी बुग्याल ट्रेक, ट्रेकर्स को अंतहीन घास के मैदानों की जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां टूरिस्ट हिमालय की सबसे भव्य चोटियों की सुंदरता को निहारने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं तो फिर नीचे करना भूल सकते हैं। इस ट्रेक पर ट्रेकर्स यह तय नहीं कर पाते कि कहां और किधर देखें? क्योंकि ट्रेक की हर दिशा में कुछ न कुछ ऐसा है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यहां घास के मैदान जुड़वां है यानी अली और बेदनी। जो हर मौसम के साथ बदलते हुए अपना नया रूप धारण करते रहते हैं। इसलिए वास्तव में यह साल भर का ट्रेक बन जाता है। ये जुड़वा बुग्याल हर मौसम के रंगों को बड़ी खूबसूरती से धारण करते हैं। सर्दियों की सफेदी इन बुग्यालों को चमका देती है, जबकि मानसून में जंगली फूलों का खिलना इन्हें खुशी से भर देता है। ये सर्दियों से पहले के पीले रंग को एक अलग ही गर्व के साथ धारण करते हैं, जबकि गर्मियों में ये गर्माहट और समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। यानी बहुत से ट्रेक अपने हरे-भरे नजारों के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन अली बेदनी ट्रेक शरद ऋतु में होने वाले अपने अद्भुत रूपांतरण के लिए जाना जाता है। इस ऊंचाई पर घास एक खास प्रक्रिया से गुजरती है और सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे एक अनूठा चमकीला नारंगी और कांस्य रंग बनता है। ये रंग मिलकर एक विशिष्ट उच्च-परिभाषा वाला रंग संयोजन बनाते हैं, जिसमें चमकीले सफेद शिखर, गहरे नीले आसमान और सुनहरी जमीन दिखाई देती है। इस प्रकार ये घास के मैदान पूरे क्षेत्र में एकमात्र ऐसे स्थान बन जाते हैं जिन्हें स्वर्ण सागर के रूप में पहचाना जाता है। यह ट्रेक शांत गांव वान से शुरू होता है, जो पहाड़ों की हरी-भरी ढलानों पर बसा हुआ है। रास्ता छोटी-छोटी झोपड़ियों, पशुशालाओं और सीढ़ीदार खेतों से होकर गुजरता है। बच्चे अपनी मासूम मुस्कान से सैलानियों का स्वागत करते हैं और चरवाहे अपनी भेड़ों के झुंड के साथ इत्मीनान से चलते हुए निकल जाते हैं। अगर आप भी हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में ट्रेकिंग का प्लान बना रहे हैं तो अली और बेदनी बुग्याल ट्रेक यकीनन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

यह ट्रेक शांत गांव वान से शुरु होता है, जो पहाड़ों की हरी-भरी ढलानों पर बसा हुआ है, रास्ता छोटी-छोटी झोपड़ियों, पशुशालाओं और सीढ़ीदार खेतों से होकर गुजरता है, बच्चे अपनी मासूम मुस्कान से सैलानियों का स्वागत करते हैं और चरवाहे अपनी भेड़ों के झुंड के साथ इत्मीनान से चलते हुए निकल जाते हैं।

बेदनी बुग्याल का धार्मिक महत्व

जैसे ही पहाड़ों का दूसरा भाग आंखों के सामने खुलता है, त्रिशूल पर्वत की पहली झलक दिखाई देती है। पगडंडी पहाड़ी से नीचे नील-गंगा नदी तक जाती है, जो बेदनी बुग्याल से नीचे आती है। नील-गंगा नदी पार करने के बाद घने जंगल से होकर एक कठिन चढ़ाई शुरू होती है। चीड़ और रोडोडेंड्रोन के जंगल से गुजरते हुए, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और संकरी धाराओं की कलकल ध्वनि सुनते हुए ट्रेकर्स प्रकृति के और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए अली बेदनी बुग्याल ट्रेक पर ट्रेकिंग राजसी हिमालय की गोद में एक अद्भुत यात्रा है। यह बुग्याल ट्रेक लगभग 31 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में आमतौर पर 4 से 6 दिन लग सकते हैं। ट्रेक की शुरुआत लोहाजंग नामक एक शांत गांव से होती है, जो इसका बेस कैंप है। ट्रेक का सबसे ऊंचा बिंदु लगभग 3,550 मीटर (11,650 फीट) की ऊंचाई पर है। यह मनमोहक लहरदार घास का मैदान एशिया के सबसे बड़े उच्च-ऊंचाई वाले घास के मैदानों में से एक है। बेदनी बुग्याल का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह नंदा देवी राज जात तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है।

बेदनी बुग्याल, वान गांव के पास रूपकुंड जाने वाले रास्ते पर है, यहां से त्रिशूल और नंदा घुंटी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यह हरा-भरा मैदान कई रंगा व प्रजातियों के फूलों का संसार है, इसके बीचोंबीच बेदनी कुंड नाम की छोटी झील है, यहां हर साल सितंबर और अक्टूबर में नंदा देवी जात का आयोजन किया जाता है।

घास के मैदान के बीच स्थित शांत झील बेदनी कुंड विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का स्थल है और चिंतन के लिए एक शांत स्थान है। यह ट्रेक हिमालयी वनस्पतियों की समृद्ध विविधता को देखने का अवसर देता है, जिसमें दुर्लभ ब्रह्म कमल (साउसुरिया ओबवल्लाटा) भी शामिल है। पक्षी प्रेमी विभिन्न ऊंचाई वाले पक्षी प्रजातियों को भी देख सकते हैं।

मखमली हरे रंग की लहरदार पहाड़ियां

अली और बेदनी बुग्याल की विशाल क्षैतिज विमाएं ही इस ट्रेक को अन्य ट्रेक से अलग बनाती हैं। घास और झाड़ियों से ढके आम मिलरो घास के मैदानों के विपरीत ये असाधारण रूप से विस्तृत और घुमावदार घास के पठार हैं जो मीलों तक फैले हुए हैं। मखमली हरे रंग की लहरदार पहाड़ियां अनंतता का दृश्य प्रभाव पैदा करती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो आप किसी सुव्यवस्थित लॉन पर चल रहे हों, जो आकाश में निर्बाध रूप से बहता है और नीचे कालीन की तरह बिछी जमीन पर लहराता है। त्रिशूल पर्वत का सबसे नजदीकी दृश्य संभवतः 7,000 मीटर से अधिक ऊंची इस चोटी का अब तक का सबसे नजदीकी नजारा होगा जो किसी भी ट्रेकर्स को देखने को मिलेगा। जब ट्रेकर्स बेदनी रिज पर पहुंचते हैं, तो त्रिशूल केवल दूर से दिखाई देने वाला एक पहाड़ नहीं रह जाता, बल्कि आपके सिर के ऊपर मंडराता हुआ एक विशाल, सीधा पहाड़ प्रतीत होता है। इतनी नजदीक से शिखर से निकलते हुए त्रिशूल के कई बर्फीले खांचे और नुकीले किनारे आसानी से दिखाई देते हैं, जो ट्रेकर्स को रोमांचक का एहसास कराते हैं। इस ट्रेक का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा वातावरण में नाटकीय परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप होने वाला पारिस्थितिक विस्फोट है। घने भूरे ओक और रोडोडेंड्रोन के जंगलों में घंटों की ट्रेकिंग के बाद, जब ट्रेकर्स पेड़ों की घनी छतरी से बाहर कदम रखते हैं, तो अचानक ही चकाचौंध कर देने वाली धूप शरीर पर पड़ती है। एक हराभरा खुला मैदान खुल जाता है जहां से चारों ओर का नजारा दिखाई देता है। जंगल के अंदर (घुटन भरा) होने से लेकर खुले मैदान में (चारों ओर का नजारा) आने का यह बदलाव इस ट्रेक का एक अनूठा अनुभव है। कुल मिलाकर अली-बेदनी बुग्याल ट्रेक सिर्फ एक ट्रेक से कहीं बढ़कर है यह एक ऐसा अनुभव है जो हिमालय की सुंदरता और संस्कृति के सार को समेटे हुए है। चाहे रोमांच का अनुभव करना हो, आध्यात्मिक शांति या प्रकृति के साथ एक अनूठा मिलन करना हो, यह ट्रेक जीवन में कभी न भूलने वाली यादें बन जाता है।

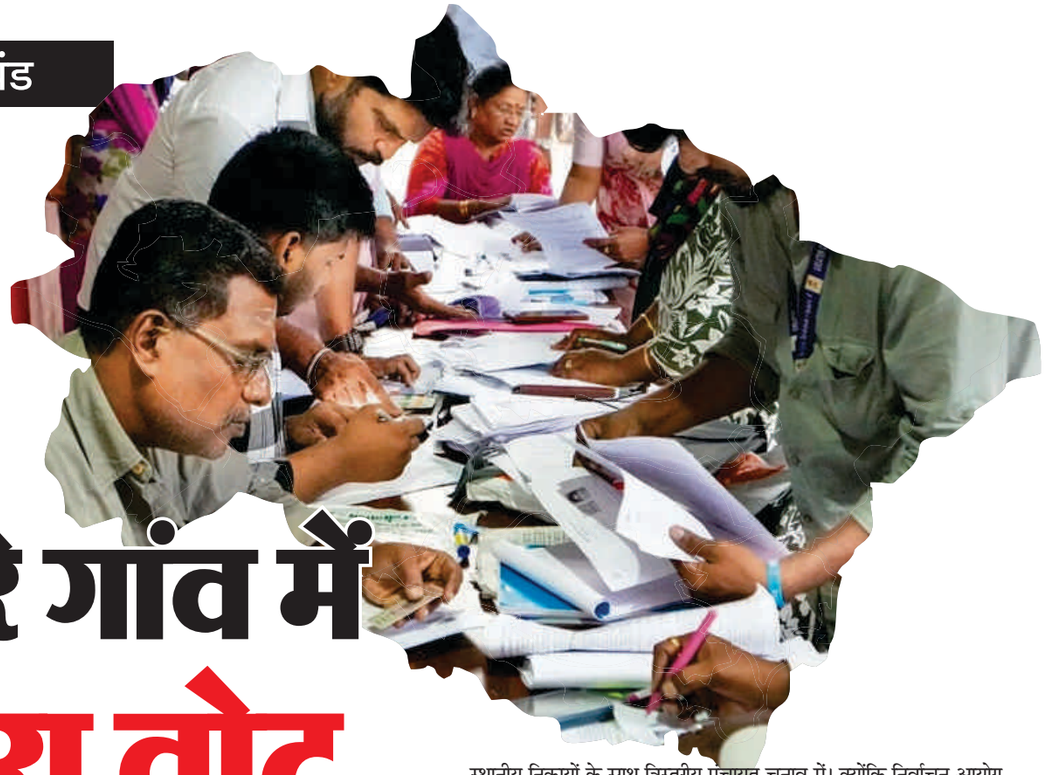

मेरे गांव में मेरा वोट

भाजपा नेताओं का मानना है कि पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने से कई सीटों पर असर पड़ा है, भारत सरकार जनसंख्या के आधार पर जो बजट देती है उस पर भी असर पड़ने जा रहा है, इसलिए भी मेरा वोट, मेरे गांव में, के इस अभियान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को तेजी से कार्य करने को कहा गया है।

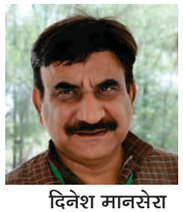

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होने से पहले भाजपा दूसरे राज्यों में काम करने वाले उत्तराखंड के नागरिकों को प्रदेश में उनके पैतृक गांव में वोट बनवाने की अपील कर रही है। इसके अलावा एसआईआर के माध्यम से राज्य में आने-जाने वाले मतदाताओं पर भी भाजपा की नजर बनी हुई है। उत्तराखंड में भाजपा 'मेरा वोट, मेरे गांव में' अभियान के तहत अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी कर रही है। इस अभियान के लिए उत्तराखंड भाजपा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से मतदाताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा है। एसआईआर होने के बाद उत्तराखंड में एक ही मतदाता सूची बनेगी जो संभवतः सभी चुनावों में काम आएगी। यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। क्योंकि निर्वाचन आयोग भी हर महीने होने वाले अलग-अलग चुनावों में हर बार नई-नई मतदाता सूची बनाए जाने के झंझट से बचना चाहता है। इसलिए ही मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम कराया जा रहा है। ऐसे बहुत से मतदाता है जिनके नाम देश में कई स्थानों पर रहने के कारण मतदाता सूची में दर्ज है। निर्वाचन विभाग इस 'डबलिंग' को खत्म करना चाहता है। यानी एक नागरिक एक ही स्थान पर मतदाता होगा। यदि मतदाता स्थान बदलता है तो उसे बदले हुए स्थान का मतदाता बनने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को पहले पुरानी मतदाता सूची से नाम कटवाना होगा और फिर नए स्थान पर अपना नाम अंकित कराना होगा।

10 साल में डेढ़ लाख स्थाई पलायन

उत्तराखंड के 13 जिलों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज्य और देश से बाहर काम कर रहा है। जिसमें सबसे बड़ी संख्या पर्वतीय क्षेत्रों की है। जहां अब भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों से मिलकर संवाद करेंगे और राज्य से बाहर रहने वाले लोगों से भी संवाद करके उन्हें उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव में अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। जिसके लिए सभी बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची का अध्ययन करना शुरू कर दिया

- **एसआईआर के बाद उत्तराखंड में एक ही मतदाता सूची बनेगी, जो संभवतः सभी चुनावों में काम आएगी, यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी अलग-अलग चुनावों में हर बार नई-नई मतदाता सूची बनाए जाने के झंझट से बचना चाहता है।**
- **एक आकलन के मुताबिक 2011 से 2022 के बीच प्रदेश से 1 लाख 47 हजार 512 लोग स्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं, हालांकि 2020-21 में कोविड काल के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गांव में रिवर्स पलायन किया है और अपने गांव में ही आज वह लोग रोजगार कर रहे हैं।**

है। उत्तराखंड में पलायन राज्य की बड़ी समस्याओं में से एक है जिसकी वजह से राज्य के कई ऐसे गांव हैं जो आज वीरान पड़े हैं। जिनको दोबारा बसाने और रिवर्स पलायन के लिए सरकार ने पहले से ही पलायन आयोग का गठन किया हुआ है। एक आकलन के मुताबिक 2011 से 2022 के बीच प्रदेश से 1 लाख 47 हजार 512 लोग स्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं। हालांकि 2020-21 में कोविड काल के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गांव में रिवर्स पलायन किया है और अपने गांव में ही आज वह लोग रोजगार कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी और भी प्रयास कर रही है कि ज्यादातर परिवारों को पैतृक गांव की तरफ रिवर्स पलायन कराया जाए। उत्तराखंड में उन्हें उपयुक्त रोजगार भी दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो राज्य में रिवर्स पलायन भी सरकार की सकारात्मक नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य में सरकार हर संभव प्रयास कर रहीं है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए है। मेरा वोट मेरे गांव अभियान पर उत्तराखंड के भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी संगठन राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके गांव से जोड़ने के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है।मूल गांव का वोटर बनाने की कोशिश

भाजपा नेताओं का कहना है कि पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने से कई सीटों पर असर पड़ा है। भारत सरकार जनसंख्या के आधार पर जो बजट देती है उस पर भी असर पड़ने जा रहा है, इसलिए भी मेरा वोट, मेरे गांव में, के इस अभियान में बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को तेजी से कार्य करने को कहा गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल कहते है कि हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासी अपने पैकृत गांव का वोटर बने और अपने आप को देवभूमि के देवों के साथ आत्मीय और सांस्कृतिक संबंध बनाए रहे। आगे राष्ट्रीय जनगणना भी होनी है इसलिए हम उन्हें रिवर्स पलायन के लिए विन्रम अनुरोध कर रहे है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भाजपा के इस अभियान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भाजपा भले ही अभियान चला रही है, लेकिन उनकी ही सरकार ने अभी तक ना तो पलायन पर कोई काम किया है और ना ही बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए रोजगार देने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले उत्तराखंड में 2026 में एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जानी है। जिसकी तैयारी हो रही हैं। निर्वाचन आयोग प्रदेश में प्री एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। लिहाजा एसआईआर उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया भी मानी जा रही है। राज्य के बहुत से जिलों में डेमोग्राफी चेंज की समस्या सामने मुंह उठाए खड़ी है। जो भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम को भी प्रभावित कर सकती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्री-एसआईआर मुक्कमल

निर्वाचन आयोग शत प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पर जोर दे रहा है। लिहाजा भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा शुरू की है। इसके तहत मतदाता एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। यानी मतदाता चुनाव आयोग की वोटर्स. ईसीआई.गोव.इन पर या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक होने के दो दिनों के भीतर ही संबंधित बीएलओ उस मतदाता से संपर्क करेगा। यानी एसआईआर शुरू होने से पहले ही प्री-एसआईआर में राज्य के सभी मतदाताओं की मैपिंग की जा सके। यह 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर वोटों का सत्यापन हो रहा है। उत्तराखंड में इस समय 81,84,092 मतदाताओं में से 69,97,131 मतदाताओं की मैपिंग मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो चुकी है। यानी 85.50 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जिलेवार मैपिंग की बात करें तो उत्तरकाशी में 2,44,113 मतदाताओं में से 2,25,873 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। चंपावत जिले में 2,06,890 मतदाताओं में से 1,92,558 मतदाताओं की

- **उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले उत्तराखंड में 2026 में एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसकी तैयारी हो रही है, निर्वाचन आयोग प्रदेश में प्री एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है, लिहाजा एसआईआर उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया मानी जा रही है।**
- **प्रदेश के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं हैं और उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम के आधार पर उनकी प्रोजनी के रूप में मैपिंग की गई है।**

मैपिंग हो चुकी है। बागेश्वर जिले में 98.76 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। पिथौरागढ़ जिले में 3,70,709 मतदाताओं में से 3,38,212 मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। अल्मोड़ा जिले में 5,30,784 मतदाताओं में से 4,96,479 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जिले में 92.37 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। टिहरी गढ़वाल जिले में 90.89 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। चमोली जिले में 90.31 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। नैनीताल जिले में 7,86,246 मतदाता हैं इनमें से 6,98,335 की मैपिंग हो चुकी है। ऊधमसिंह नगर जिले में 13,72,707 मतदाताओं में से 10,69,644 मतदाताओं की मैपिंग का काम हो चुका है। पौड़ी गढ़वाल जिले में 88.48 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। राजधानी देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 14,82,711 मतदाता हैं। इनमें से 11,13,296 मतदाताओं की मैपिंग का काम निपट चुका है। यानी बाकी जिलों के मुकाबले देहरादून में मैपिंग का काम तेजी से करने की आवश्यकता है। हरिद्वार जिले में 87.98 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। प्रदेश के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं हैं और उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम के आधार पर उनकी प्रोजनी के रूप में मैपिंग की गई है। जबकि जिन मतदाताओं की उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक है और उनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनकी सीधे बीएलओ ऐप से मैपिंग की गई है।

बीएलए नियुक्त करने में रूचि नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन में लगा हुआ है। एसआईआर को 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे उत्तराखंड में अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य तेजी से किया जा सके। उत्तराखंड में 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं इनमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआई (मार्क्सवादी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं जबकि यूकेडी क्षेत्रीय दल है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि राज्य में 11,733 बूथ हैं लेकिन अभी तक 4,155 बीएलए ही राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए हैं। भाजपा लगभग 2830 से ज्यादा बीएलए अपॉइंट कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने लगभग 1250 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। सीपीएम ने करीब 60 बूथ एजेंट तैनात किए हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी और एनएनपी ने अभी तक कोई बीएलए नियुक्त नहीं किया है। यानी भाजपा को छोड़कर जो बाकी राजनीतिक दल अभी बीएलए तैनात नहीं कर रहे हैं, वही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते आ रहे हैं। खासकर उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हैं। इसी कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एसआईआर को वोट चोरी बताते हैं। भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हैं। प्रेस के सामने वोट चोरी का प्रजेंटेशन करते हैं, लेकिन जब एसआईआर के लिए बीएलए नियुक्त करने का नंबर आता है तो उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं होते जिन्हें बीएलए का काम सौंपा जा सके। ●

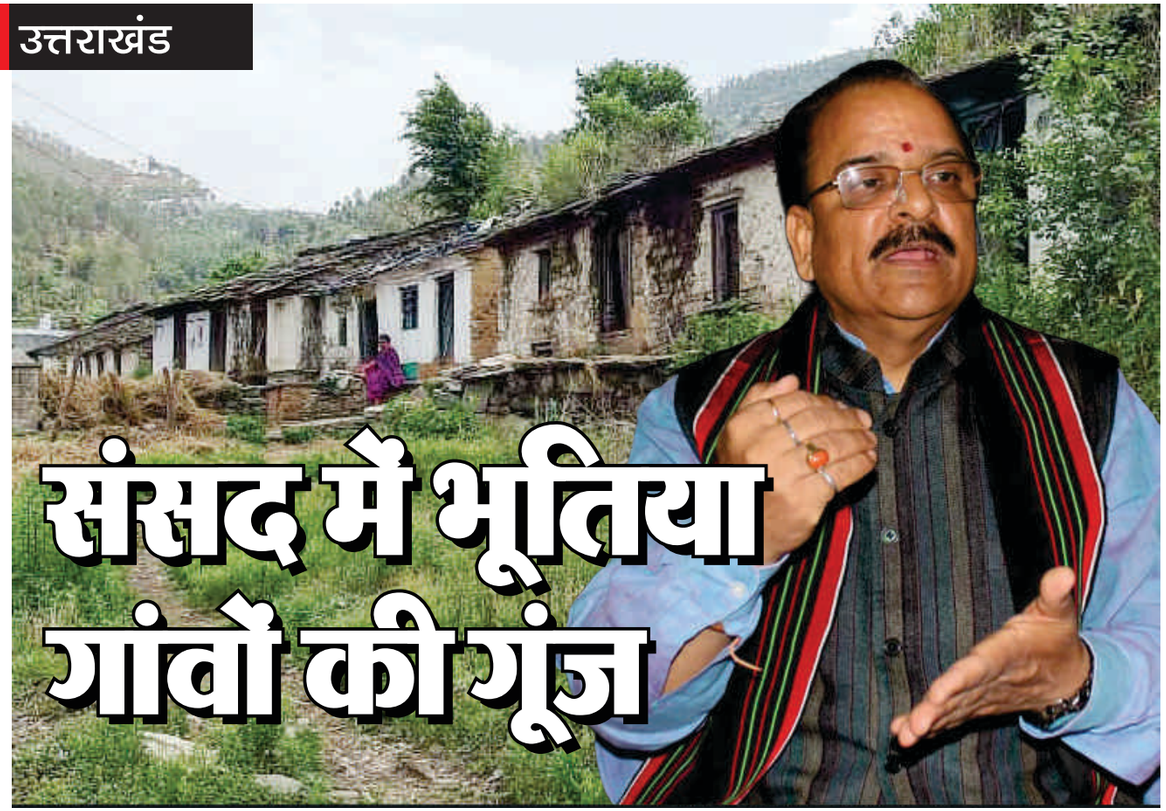

संसद में भूतिया गांवों की गूंज

2000 में जब राज्य का गठन हुआ था तब यही सोचा गया था कि उत्तराखंड में अपनी सरकार होगी, अपने संसाधन होंगे, अपना शासन होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में रोजगार मिलेगा, खुशाहाली दरवाजे पर खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका, लिहाजा राज्य गठन के बाद रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी जीवनशैली ने पलायन की रफ्तार बढ़ा दी।

अफजल फौजी
नैनीताल

उत्तराखंड में तेजी से गांव खाली हो रहे है। मकान टूटकर खंडहर हो रहे हैं और खेत बंजर हो रहे हैं। फिर भी सरकार का दावा है कि वो पलायन रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तराखंड से पलायन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आलम ये है कि अब गांवों के गांव खाली हो रहे हैं। लोग अपने पैतृक गांव ही नहीं अपनी जन्म भूमि को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि 10 वर्षों में छोटे से पहाड़ी राज्य से 17 लाख लोगों का पलायन हुआ है, जो मायने रखता है। हालांकि अकेला उत्तराखंड राज्य ही ऐसा नहीं है बल्कि हर राज्य से रोजगार की खातिर पलायन होता ही है, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और स्वरोजगार के बजाये नौकरी की चाहत ने पलायन की समस्या को पंख लगा रखे हैं। हालांकि 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था तब यही सोचा गया था कि उत्तराखंड में अपनी सरकार होगी, अपने संसाधन होंगे, अपना शासन होगा तो निश्चित ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा, खुशाहाली दरवाजे पर खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। इसलिए राज्य गठन के बाद रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी जीवनशैली ने पलायन की रफ्तार बढ़ा दी। बेरोजगार नौकरी की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं तो बच्चे और उनके माता-पिता बेहतर शिक्षा और चिकित्सा के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि गांवों में पूजा-पाठ, विवाह-शादी, नामकरण संस्कार, जनेऊ कराने वाले पुरोहित भी गांव में नहीं रहना चाहते। क्योंकि गांवों में पंडताई करने के एवज वो नहीं मिलता जिसकी उम्मीद होती है। शादी में हर काम दिल खोलकर किया जाता है, लेकिन जब पंडित या पुरोहित को दक्षिणा देने का नंबर आता है तो दिल कमजोर पड़ जाता है। पहाड़ों में अस्थिर आजीविका, कमजोर शैक्षिक ढांचा और सीमित स्थानीय रोजगार पलायन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब बच्चों और युवाओं को आसपास के स्कूलों के माध्यम से अच्छी नौकरियां मिलने के रास्ते नजर नहीं आते, तो परिवार अपने बच्चों की शिक्षा या उनके लिए रोजगार खोजने के लिए शहरों की तरफ जाने पर विचार करते हैं। बाल प्रवास पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षा की कमी परिवारों के पलायन के प्रमुख कारणों में से एक है। उत्तराखंड की शिक्षा नीति जलवायु के

पर्यावरण में हो रहा बदलाव आर्थिक चुनौतियों को जन्म दे रहा हैं, फसलों के पैटर्न बदल रहा है, पैदावार घट रही है और मौसमी रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जब खेत बुनियादी जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो पलायन अनिवार्य बन जाता है।

प्रति जागरूक, गतिशील आबादी को शामिल करने वाली और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी होनी चाहिए ना कि शहरी परिवेश के प्रमाण पत्र देने वाली।

भूतिया गांवों की चिंता

लोकसभा के बजट सत्र में पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने 24 मार्च को लोकसभा के शून्य काल के दौरान उत्तराखंड के खाली हो चुके गांवों को भूतिया गांव बताते हुए मांग की कि केंद्र सरकार विशेष आर्थिक पैकेज देकर भूतिया गांवों को फिर से आबाद करने का काम करे। मध्य हिमालय के सीमावर्ती गांवों का जिक्र करते हुए सांसद भट्ट ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज की तर्ज पर खाली पड़े गांवों में विकास व पुनर्वास नीति लागू की जाए। क्योंकि उत्तराखंड में 2025 तक 1700 से अधिक गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं, जिन्हें अब 'भूतिया गांव या घोस्ट विलेज' कहा जाता है। इन गांवों में घर खंडहर हो चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं। जहां कभी लोगों की चहल-पहल और बच्चों का शोर सुनाई देता था वहां अब सन्नाटा पसरा है। त्योहारों के गीत और सामूहिक उत्सव देखने को नहीं मिलते। इन भूतिया गांवों में अब बाघ, तेंदुआ, भालू, बंदर और अन्य वन्यजीवों का बसेरा बन गया है। दुर्गम गांवों में रोजगार के साधन नहीं है। खेती को वन्यजीव नुकसान पहुंचाते हैं, आजीविका संकट है, लिहाजा गांवों के युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। 1700 गांवों से तो एक-एक करके परिवार पलायन कर चुके हैं और गांव पूरी तरह भूतिया बन चुके हैं। इन गांवों में चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, बल्कि लोक संस्कृति, भाषा-बोलचाल और सामुदायिक जीवन की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। सांसद भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमावर्ती गांवों के लिए चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेज योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के 91 सीमावर्ती गांवों को चयनित करके बुनियादी ढांचा, आजीविका और सुरक्षा व्यवस्था सुधारी जा रही है। इस योजना से सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल रही है, इसी तर्ज पर मध्य हिमालय के गांवों के लिए भी अलग से नीति बनाई जानी चाहिए। ताकि भूतिया गांवों को फिर से आबाद किया जा सके। इसके लिए रोजगार-सृजन, कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यटन आधारित आजीविका और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाली एक विशेष केंद्रीय योजना बनाई जाए। केंद्र सरकार से इन गांवों के लिए ठोस रिवर्स पलायन नीति, विशेष आर्थिक पैकेज और गांवों को फिर से आबाद करने की योजना तैयार करने की मांग की गई। ताकि खंडहर को रहे गांवों में फिर से लोगों की चहल-पहल दिखाई दे सकें।

सुविधाओं के अभाव में पलायन

हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट चौकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बीते दस वर्षों में करीब 17 लाख लोग गांव छोड़कर शहरों में जाकर बस गए हैं। इस पलायन के कारण शहरों में आबादी का दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी आबादी बढ़ने से अवस्थापना विकास से लेकर सुविधाओं तक पर दबाव बढ़ा है। लिहाजा सरकार अब शहरों में अवस्थापना विकास के लिए नई योजना बनाने जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट अरबन क्लस्टर प्रोजेक्ट यानी यूएसयूसीपी तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहरों में बस रही नई आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजी से बढ़ रही आबादी के कारण प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम और नगर पालिका व नगर पंचायत का स्वरूप भी बदल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि तहसील व जिला मुख्यालयों तथा कस्बों में आबादी का प्रेशर ज्यादा बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहाड़ के गांवों से सबसे ज्यादा पलायन करने वाले परिवार नजदीकी कस्बों में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद पलायन करने वालों की पसंद तहसील मुख्यालयों के साथ जिला मुख्यालय हैं। क्योंकि तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, सड़क, बिजली पानी, सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये इंटरनेट

आर्थिक सर्वेक्षण में पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि तहसील व जिला मुख्यालयों तथा कस्बों में आबादी का प्रेशर ज्यादा बढ़ा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि पहाड़ के गांवों से सबसे ज्यादा पलायन करने वाले परिवार नजदीकी कस्बों में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बाद पलायन करने वालों की पसंद तहसील मुख्यालयों के साथ जिला मुख्यालय हैं।

का जमाना है, इसलिए कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदता है। गांवों तक पहुंची शहरी चकाचौध भी ग्रामीणों को शहरों में शिफ्ट कर रही है। ग्रामीणों के पलायन करने की एक वजह उत्तराखंड की कृषि, जल संसाधन और गांवों को सहारा देने वाला हिमालयी भूभाग तेजी से बदल रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने, खतरनाक हिमनदी झीलों के बनने और भूस्खलन, बाढ़ तथा कटाव जैसी मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन जोखिमों का सबसे ज्यादा प्रभाव खड़ी ढलानों पर रहने वाले छोटे भू-जोत वाले गावों के लोगों पर पड़ता है। इसलिए भी पहाड़ से मजबूरीवश पलायन हो रहा है।

बुनियादी ढ़ांचे को प्राथमिकता मिले

पर्यावरण में हो रहा बदलाव आर्थिक चुनौतियों को जन्म दे रहा हैं। फसलों के पैटर्न बदल रहा है, पैदावार घट रही है और मौसमी रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। जब खेत बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो पलायन अनिवार्य बन जाता है। हितधारकों के साथ हाल ही में हुई चर्चाओं में ग्लेशियर भंडार में आई भारी गिरावट और हिमालय में व्यापक कार्य योजनाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पश्चिमी हिमालय में पहले से ही पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं। पलायन पर्यावरणीय दबावों और सरकार के नीतिगत निर्णयों का भी मिला-जुला प्रभाव है, जिसने समय के साथ ग्रामीण जीवन को नष्ट कर दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए पर्वतीय समुदायों की बात सुनने, उनके ज्ञान को महत्व देने और कम आकर्षक लेकिन मजबूत सामुदायिक विकास के लिए निवेश का समर्थन करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। हिमालय के विकास पर पुनर्विचार करने का अर्थ है लोगों और पर्यावरण को प्राथमिकता देना, पर्वतीय जीवन को एक मजबूरी के बलिदान के बजाय एक सम्मानजनक विकल्प बनाना होना चाहिए। राजनीतिक निर्णय जो जन-केंद्रित विकास की तुलना में दृश्यमान बुनियादी ढ़ांचे को प्राथमिकता देते हैं। जब तक इन सभी कारणों को समझा और एक साथ हल नहीं किया जाता, तब तक पलायन और भी गहराता जाएगा।

अनिश्चित रोजगार भी समस्या

उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी जिलों में विकास का मुख्य मॉडल सड़कों का निर्माण, पर्यटन संरचना का विकास और अचल संपत्ति का विकास करना है। यह मॉडल सकल घरेलू उत्पाद में कुछ बढ़ोत्तरी तो दर्शाता है, लेकिन इससे मौसमी और अनिश्चित रोजगार पैदा होते हैं। आमतौर पर इन रोजगारों से स्थानीय निवासियों की तुलना में बाहरी निवेशकों को अधिक लाभ होता है। कृषि, पशुपालन और लघु शिल्प, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पर्वतीय आजीविका को सहारा दिया है, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और युवा पीढ़ी की अरुचि के कारण कमजोर पड़ गए हैं। उत्तराखंड से पलायन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कई गांव आंशिक या पूर्णतः वीरान हो गए हैं। शेष आबादी में वृद्ध, गरीब या बेबस है। स्थानीय स्तर पर स्थाई रोजगार के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि में निवेश करना होगा, स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना होगा, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करना होगा, स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा संचालित पर्वतीय पर्यटन मॉडलों को बढ़ावा देना होगा। दूरस्थ कार्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल को बढ़ाना होगा। यदि इन लक्षित रणनीतियों को लागू नहीं करते हैं, तो सृजित रोजगार अस्थाई बने रहेंगे।

बिहार में सम्राट की सत्ता

दूसरे दल से भाजपा में आने वाले सम्राट चौधरी भाजपा के दूसरे सीएम बने हैं, इससे पहले असम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हेमंता बिस्वा सरमा असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो भाजपा अथवा आरएसएस की विचारधारा वाले नहीं हैं, सम्राट दूसरे सीएम है जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से हुई और कई दलों में भटकने के बाद भाजपा में शामिल हुए।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

बिहार के सम्राट, सत्ता के चौधरी बन गए। ये एनडीए की एकता है, दूरदर्शिता, समीकरणों का खेल है। ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि जिस सम्राट चौधरी को बिहार की सत्ता सौंपी गई है वो न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हैं और न ही भाजपा की विचारधारा वाले हैं। बल्कि वो तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का प्रोडक्ट हैं। उनका राजनीतिक करियर 90 के दशक में आरजेडी से ही शुरू हुआ था। 1999 में आरजेडी की रबड़ी देवी सरकार में सम्राट चौधरी सबसे युवा मंत्री बने तो बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो गया था, लेकिन भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया तो किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। न ही किसी तरह के बगावती तेवर देखने को मिले। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने एक राज की बात बताई, वो ये कि 90 के दशक में वो सक्रिय राजनीति में तो आ गए थे, विधायक से लेकर मंत्री तक बन गए, लेकिन उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। लेकिन वो राजनीति में थे इसलिए कई नेताओं को फालो करते थे। इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र की विचारधारा उनकी राजनीतिक विचारधारा बन गई और 2017 में सब कुछ पीछे छोड़कर हमेशा के लिए भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में आते ही सम्राट चौधरी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए सम्राट अशोक जयंती का भव्य आयोजन करने का फैसला किया। बस इस आयोजन से ही उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया।

घर के आगंन में सीखी राजनीति

16 नवंबर, 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी राजनीतिक माहौल में खेलते-कूदते जवान हुए। राजनीति की एबीसीडी घर के आंगन में ही सीखी। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद सांसद, विधायक और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। तमिलनाडु की कामराज यूनिवर्सिटी से पीएचसी (प्री फाउंडेशन कोर्स) करने वाले सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पेशे से वकील हैं और उनकी दो संतान हैं। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर जो दर्ज है, उसके मुताबिक सम्राट को एक राजनीतिक मामले में 89 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। एक दौर वो भी आया जब सम्राट चौधरी को उनके बर्थडे के दिन ही राज्यपाल ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। सम्राट चौधरी वर्ष 2000 से 2010 तक विधायक चुने गए थे। वो ऐसे जनाधार वाले नेता हैं, जो आरजेडी के 13 विधायक लेकर जेडीयू का साथ देने के लिए चर्चा में रहे थे। उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन मन में बेचैनी थी, वो राजनीति में एक स्थाई ठिकाना चाहते थे, लिहाजा पीएम मोदी से प्रभावित होकर 2017 में भाजपा में शामिल हो गए। 8 अप्रैल, 2022 को पटना के बापू सभागार में भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक की जयंती का बड़ा आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और यूपी के उस समय के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लगभग 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं और कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया था। इनकी मौजूदगी में ऐलान हुआ था कि अगले साल यानी 2023 में पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी।

सम्राट चौधरी राजनीतिक माहौल में खेलते-कूदते जवान हुए, राजनीति की एबीसीडी घर के आंगन में ही सीखी, उनके पिता शकुनी चौधरी खुद सांसद, विधायक और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं।

भाजपा नेतृत्व की पहली पसंद सम्राट

ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आएगा कि सम्राट अशोक जयंती के आयोजन की चर्चा अब क्यों की जा रही है। इसका जबाव है कि इसी आयोजन के शीशे में सम्राट चौधरी के भाजपा में बढ़ते कद और पद की कहानी मिल जाएगी। जी हां इसी आयोजन ने ही सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में ला दिया था। इसके बाद से ही उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस की विचारधारा से न होने के बाद भी वो बड़े नेताओं की पार्टी में पहली पसंद बन गए। लिहाजा पहले विधान परिषद में पार्टी के नेता। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, फिर उपमुख्यमंत्री, वित्त विभाग और एक साल पहले डिप्टी सीएम के साथ गृह विभाग उनके हाथ में थमा दिया गया। यानी सम्राट चौधरी की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व के मन का सुकून दिया था। जो दशकों से बिहार में आक्रामक और हार्डलाइनर चेहरे की तलाश कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में आने के बाद सम्राट चौधरी भी समझ गए थे कि अब उनके सियासी करियर का ग्राफ आगे बढ़ेगा। बस धैर्य के साथ नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। सम्राट चौधरी के पक्ष में एक और जो बात रही वो थी उनकी जाति। वे कुशवाहा समाज से आते हैं। लव-कुश समाज की आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। उसके अलावा धीरे-धीरे ही सही अपनी पगड़ी के साथ अपने अहंकार और हार्डलाइन को नीतीश के लिए सरयू नदी में बहा देने के बाद सम्राट चौधरी शांत स्वभाव के बन गए थे। नीतीश कुमार भी उन्हें पसंद करने लगे थे। भाजपा को लगा कि सम्राट चौधरी जाति फैक्टर से, 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव के साथ रहे है लिहाजा वो लालू यादव और उनकी पार्टी की कमजोरी को भी समझते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं। लिहाजा भाजपा की समझ में आ गया कि फिलहाल तो यादव उसे एक मुस्त वोट नहीं करेगा। हालांकि भाजपा ने इससे पहले बिहार में यादव नेताओं को आगे करके कई प्रयोग कर चुकी थी। भाजपा को अनुमान था कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार करते हैं तो नीतीश कुमार के बिदकने के चांस थे। लिहाजा भाजपा ने वो काम किया, जो राजनीतिक रूप से उसके लिए फायदेमंद रहा।

बिहार के भाजपा नेताओं का दर्द

भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा का वो बयान याद कीजिए जब सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। तब विजय सिन्हा ने कहा था कि गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए ही हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था। हमारे त्याग, तपस्या और बलिदान से आज ये पल आया है। इस बयान की बानगी में बिहार भाजपा के उन नेताओं का दर्द साफ दिखाई देता है जो शुरू से भाजपा के रहे। आरएसएस के पसंदीदा रहे। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तेजी के साथ आगे बढ़े और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पीछे कर दिया तथा मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर पर सज गया। जानकार मानते है कि सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक की जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिलों में अपना मजबूत स्थान बना लिया था। जहां से सम्राट चौधरी के आगे बढ़ने की शुरुआत हुई थी। दूसरे दल से भाजपा में आने वाले सम्राट चौधरी भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले असम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हेमंता बिस्वा सरमा भाजपा शासित राज्य असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो भाजपा अथवा आरएसएस की विचारधारा वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी दूसरे सीएम है जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से हुई और कई दलों में भटकने के बाद भाजपा में शामिल हुए। भाजपा कहो या एनडीए इसके नेता और कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के फैसलों का समर्थन और सम्मान करते हैं। पहले असम और अब बिहार में गैर भाजपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कही से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी। अब इसकी तुलना यूपीए और इंडिया गठबंधन को छोड़िए कांग्रेस से करते हैं।

- **कांग्रेस में पहले तो हाईकमान कौन है यही कार्यकर्ताओं को नहीं पता, क्योंकि सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है और प्रियंका गांधी वाड्रा अलग पार्टी बनाकर बैठी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो इन तीनों कांग्रेस को ही हाईकमान मानते हैं।**
- **भाजपा नेतृत्व को अनुमान था कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार करते हैं तो नीतीश कुमार के बिदकने के चांस थे, लिहाजा भाजपा ने वो काम किया, जो राजनीतिक रूप से उसके लिए फायदेमंद रहा था, भाजपा इससे पहले बिहार में यादव नेताओं को आगे करके कई प्रयोग कर चुकी थी।**

कांग्रेस में हाईकमान कौन?

कांग्रेस में पहले तो हाईकमान कौन है यही कार्यकर्ताओं को नहीं पता। क्योंकि सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है और प्रियंका गांधी वाड्रा अलग पार्टी बनाकर बैठी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो इन तीनों कांग्रेस को ही हाईकमान मानते हैं। खैर ये पार्टी का अंदरुनी मामला है। मुद्दे पर लौटते हैं भाजपा में जहां नेतृत्व परिवर्तन बिना किसी बाधा के शांति के साथ हो जाता है वहीं कांग्रेस में एक सीएम को बदलने की ताकत तो गांधी परिवार में भी नहीं है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर-चंबल संभाग की कुल 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी। यह संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसके लिए गांधी परिवार तक में क्लेश हुआ और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस में नेता चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी का कितना ही करीबी क्यों न हो गांधी परिवार के अपने क्लेश में युवा कांग्रेसियों के साथ अन्याय ही हुआ है। शायद इसलिए 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों को साथ लेकर कमलनाथ की सरकार ही गिरा दी। अब वो केंद्र में मंत्री हैं। दूसरा किस्सा राजस्थान का है जहां कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दिया। पहले दिन से शुरू हुई लड़ाई पूरे पांच साल चली। सचिन पायलट संघर्ष करते रहे पर अशोक गहलौत के सामने बेबस ही बने रहे। हालांकि सत्ता परिवर्तन के लिए सचिन पायलट ने सड़क से लेकर सदन तक हाथ पैर मारे, तख्ता पलट का खुला खेल हुआ, एफआईआर तक हुई लेकिन गहलौत सीएम की कुर्सी से ऐसे चिपके कि कांग्रेस हाईकमान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलौत कहते थे कि वह तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद ही उन्हें नहीं छोड़ता तो वो भी क्या करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलौत सीएम बनने का आशीर्वाद दिल्ली से ले आए और पायलट देखते रह गए थे। फिर डिप्टी सीएम रहते हुए पायलट खुद को बेबस बताते रहे, गहलौत खेमे ने सचिन पर पार्टी से गद्दारी का आरोप लगाया। ऑडियो टेप कांड हुआ। अपनी ही सरकार में पायलट पर देशद्रोह तक की धारा तक लगा दी गई। पूरी ताकत मिलने के बाद गहलौत ने पायलट के एक-एक समर्थक विधायकों को किनारे लगा दिया था। इसलिए कांग्रेस बेलगाम पार्टी बन गई है। इसमें जिसके पास पावर है वही हाईकमान है। जबकि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता है इसलिए सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही है।

क्या महिला विरोधी है विपक्ष

अवसरवादी इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दल अपनी सहूलियत से गठबंधन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब सरकार विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन का संशोधित प्रस्ताव 'नारी वंदन अधिनियम 2026' लाती है तो पूरा इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण बिल के विरोध में खड़ा हो जाता है।

सुहेल जैदी
वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या उनकी टीम अथवा अवसरवादी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल। इनकी सोच जहां खत्म होती है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सोच शुरू होती है। इसलिए देश की सबसे बूढ़ी पार्टी कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल बसपा, सपा, आप, अकाली दल, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना (उद्धव), एनसीपी जैसे दल हासिये पर हैं। फिर भी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की राजनीति और रणनीति को समझ नहीं पाए हैं। देश के ये दो नेता वो हैं जो विपक्षी दलों को उनके बुने जाल में ही फंसाकर तमाशा देखते हैं। इसे आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी व कांग्रेस महागठबंधन की सरकार चला रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को संगठित करने का बीड़ा उठाया था। नीतीश कुमार ने अलग-अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा भी कर लिया था, लेकिन मोदी और शाह की रणनीति ने चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के मिशन को फेल कर दिया। इंडिया गठबंधन का संयोजक न बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने खुद को ही इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया और बिहार में महागठबंधन तोड़कर भाजपा के सहयोग से फिर सरकार बना ली। इसके बाद लोकसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़े। ऐसे ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की वो बेइज्जती की कि कोई स्वाभिमानी नेता होता तो शायद कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहता। किंतु अखिलेश यादव का स्वाभिमान से क्या वास्ता वो तो मौलाना द्वारा उनकी पत्नी डिम्पल यादव का अपमान किए जाने पर भी खामोश रहते हैं। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने अपने से दूर कर लिया। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पैर रखने तक की जगह नहीं दी, लिहाजा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं।

महिला आरक्षण का विरोध क्यों?

खैर ये अवसरवादी इंडिया गठबंधन है इसमें शामिल राजनीतिक दल अपनी सहूलियत से गठबंधन में आते जाते रहते हैं। लेकिन जब सरकार विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन का संशोधित प्रस्ताव 'नारी वंदन अधिनियम 2026' लाती है तो पूरा इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण बिल के विरोध में मजबूती से खड़ा हो जाता है। न कोई शोर-शराबा, न कोई सदन का बॉयकाट, न कोई गैरहाजिरी। सारे के सारे विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। फिर जैसे कि पहले से ही कायस लगाए जा रहे थे, 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है। लिहाजा सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के समर्थन के बावजूद इस संशोधित विधेयक का विरोध किया। विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण को परिसीमन और सीटों के विस्तार से जोड़कर सरकार चुनावी ढांचे में बदलाव करना चाहती है। विपक्ष सरकार के इस कदम को संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ बता रहा था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदान के तुरंत बाद एक्स पर लिखा कि यह संशोधन बिल गिर गया है। विपक्ष में दक्षिण भारत के उन राज्यों को लेकर विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। उनकी आशंका थी कि परिसीमन से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। विपक्ष का एक आरोप ये भी था कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित कराकर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में लाभ लेना चाहती है। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष की ये बेशर्मी ही कही जाएगी कि महिला आरक्षण बिल गिराकर, यानी देश की आधी आबादी का हक मारकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जश्न मनाया। महिलाओं का हक मारकर इसे विपक्ष की जीत बताया। देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में प्रवेश करने से रोक कर विपक्षी दल गदगद हैं। शायद ये विपक्षी दल सिर्फ अपने परिवारों की महिलाओं को सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं। आम महिलाओं के हक की बात तो करते हैं, लेकिन जब अधिकार दिए जाने का मौका आता है तो संसद से लेकर सड़क तक महिलाओं के अधिकारों का चीरहरण करते हैं। जैसे राजनीतिक परिवार की महिला सांसदों ने संसद में करके भी दिखाया। यानी परिवारवादी पार्टी की महिला सांसदों ने संसद में महिला आरक्षण बिल का खुलकर विरोध किया। इनमें प्रियंका गांधी, सपा की डिम्पल यादव, एनसीपी की सांसद भी शामिल थी।

जितने विपक्षी दल थे उतनी ही मांग थी, लेकिन एक जुटता सिर्फ महिला आरक्षण बिल को गिराने की थी, विपक्ष ये भूल गया कि मोदी-शाह की जोड़ी का यह इमोशनल कार्ड है, जिसका विरोध करना विपक्ष पर भारी पड़ेगा और भाजपा तब तक हर चुनाव में यह इमोशनल कार्ड खेलेगी जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता।

बस मोदी का विरोध करना है

महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में लम्बी बहस हुई। सत्ता पक्ष का कहना था कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है। इसके विपरीत विपक्षी दलों के अपने अपने मुद्दे थे। समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही थी। कांग्रेस अपना पुराना टेप बजा रही थी। कांग्रेस के जितने भी सांसदों ने चर्चा में भाग लिया सभी ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही 33 फीसदी सीट महिलाओं को आरक्षित करने का मुद्दा भी उछाला। जितने विपक्षी दल थे उतनी ही मांग थी, लेकिन एक जुटता सिर्फ महिला आरक्षण बिल को गिराने की थी। विपक्ष ये भूल गया कि मोदी-शाह की जोड़ी का यह इमोशनल कार्ड है। जिसका विरोध करना विपक्ष पर भारी पड़ेगा और भाजपा तब तक हर चुनाव में यह इमोशनल कार्ड खेलेगी जब तक कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता। हालांकि सरकार भी जानती थी कि महिला आरक्षण संशोधित बिल 'नारी वंदन अधिनियम 2026' पारित कराने के लिए उसके पास जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं है। फिर भी मोदी सरकार ने रिस्क लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा भी की थी। संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की कि महिला आरक्षण का विरोध करने से उन्हें (विपक्ष) को बड़ा नुकसान होगा। संसद में तो शोर या विरोध कर लो, लेकिन जब चुनाव होगा और विपक्षी नेता मैदान में उतरेंगे तब महिलाओं को कैसे बताएंगे कि हम ही हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। विपक्षी नेता किस मुंह से महिलाओं से वोट मांगेंगे। बारहाल ये पहला मौका है जब एनडीए सरकार अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में संशोधित 'नारी वंदन अधिनियम 2026' लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इससे पहले लोकसभा और राज्य सभा में जरूरी बहुमत न होने और विपक्ष के विरोध करने पर भी सरकार सभी बिल पास करा लेती थी। इनमें अनुच्छेद 370 समाप्त करना हो या फिर सीएए लागू करना हो, राम मंदिर का विरोध हो अथवा तीन तलाक को समाप्त करना जीएसटी लागू करना हो या नए संसद भवन का निर्माण। आयुष्मान भारत का विरोध किया, सेना को सशक्त बनाने के लिए सीडीएस के पद का सृजन करने का विपक्ष ने किया था। इसी तरह नक्सलवाद खत्म करने का भी विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यानी मोदी सरकार जो भी करती है वो भले ही जनकल्याणकारी हो उसका बिना सोचे समझे विपक्ष को विरोध करना है। इसलिए विपक्षी दल पतन की दलदल में फंसते जा रहे हैं।

संशोधित महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद विपक्षी नेता जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत बताकर पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि भविष्य में इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है, अब उनको भुगतना पड़ेगा।

क्योंकि जनता जान रही है कि उसके हित में क्या है और क्या नहीं है? लेकिन विपक्षी दल जनता का मूड समझने में लगातार गलती कर रहे हैं।

परिसीमन का कांग्रेस का खानदानी विरोध

नारी वंदन अधिनियम 2026 को लेकर संसद में बहस का जबाव देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस के खानदान तक को घसीटते हुए बताया कि सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया था। 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी थी। तब भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने कानून लाकर परिसीमन पर रोक लगाई थी, लेकिन कांग्रेस अब विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहती है। पहले भी कांग्रेस ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित कर रही है। शाह ने बताया कि 1976 में इस देश की आबादी 56.79 करोड़ थी और आज देश की आबादी 140 करोड़ है। तो क्या 56.79 करोड़ की आबादी का जितने सांसद प्रतिनिधित्व करते थे, उतने ही 140 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? परिसीमन न होने की वजह से कि देश में ऐसी 127 लोकसभा सीटें हैं जहां निर्वाचन क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मतदाता है। कुछ लोकसभा सीटे ऐसी हैं भी जिनमें मतदाताओं की संख्या 45 लाख तक है। जरा साचिए क्या एक सांसद 20 से 45 लाख मतदाताओं तक पहुंच सकता है? क्या इतनी बड़ी आबादी का एक सांसद प्रतिनिधित्व कर सकता है? जबकि कुछ लोकसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या छह लाख है। इसलिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक वोट का मूल्य समान नहीं है। अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन होता है तो हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हर वोट का मूल्य एक समान हो जाएगा।

अपने ही जाल में फंस गया विपक्ष?

संशोधित नारी वंदन अधिनियम बिल 2026 लोकसभा में गिराने के बाद भले ही विपक्षी नेता जश्न मना रहे हों, अपनी जीत बताकर पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि भविष्य में इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है। अब उनको भुगतना पड़ेगा। मोदी यदि कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई सच छिपा होता है। अब मोदी ने विपक्ष के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। यानी भाजपा और आरएसएस के साथ सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय निकायों के मेयर, चेयरमैन, सभासद, पार्षद, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान से लेकर बूथ लेबल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। ये सभी गांव-गांव और घर-घर जाकर आधी आबादी के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करने वाले विपक्ष को बेनकाब कर रहे हैं। विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं करा पाने के लिए देश की आधी आबादी से पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। साथ ही कह दिया है कि उनकी लड़ाई थमेगी नहीं बल्कि महिलाओं को उनका हक दिलाने तक जारी रहेगी। सरकार चाहती थी कि नारी वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित कराकर 2029 से ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया जाए, लेकिन विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा हो गया। ●

व्यंग्य

हारा नहीं हराया गया

96 चुनाव हारने के बाद भी सो कॉल्ड दत्तात्रेय का वंशज हार की सेंचुरी पूरी करने के लिए उतावला है, भई उस पे फर्क पड़े या न पड़े पर 96 हार से देश की सबसे बूढ़ी पार्टी की कमर तो टूट ही रही है, अब पार्टी बूढ़ी है तो दत्तात्रेय का वंशज भी क्या कर सकता है? क्योंकि इस पार्टी की इमारत तो लखोड़ी ईंटों से बनी है जो 141 साल से जैसे-तैसे सब कुछ झेल कर खंडहर हो रही है।

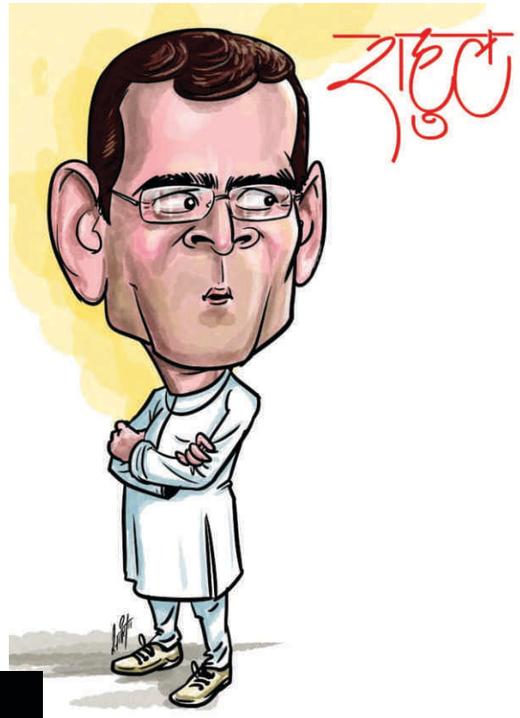

प्रदीप भट्ट
व्यंग्यकार, मेरठ

अपना भारत देश भी जो है न भाई साहब पूरा गजब से भरा हुआ है। यहां कौन क्या और कब कुछ ऐसा कर देता है जिसे समझने में ही लोगों के 5-7 साल निकल जाते हैं। बात अगर गांव की करें तो अलग ही कहानी चल रही होती है। वहां खाता न बही, जो प्रधान जी ने कही बस वही सही। आजकल जिसे देखो एसआरआई...एसआरआई...खेलने पे तुला है। वोटर कार्ड तो अपना भी है, लेकिन मुंबई का। अब भैय्या फार्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से दे दिया है। परंतु सूचना अब तक भी प्राप्त नहीं है। अब चूंकि हम अभी यहां नए हैं तो आस पड़ोस से पूछताछ की तो पता चला सबके वोट गांव के है। हमने पूछा ऐसा काहे? महराज बोला हमारे वोट की कीमत शहर में नहीं है बेटा लेकिन गांव में भरपूर है। गांव में चुनाव चाहे प्रधानी का हो या विधायक का या फिर लोकसभा का, ग्राम प्रधान महीने भर पहले से दे फोन दे फोन करके कंफर्म करता रहता है कि कहीं हम टपक तो नहीं गए। हमारे एक वोट से गांव की प्रधानी जा भी सकती है और मिल भी सकती है और खातिरदारी के तो क्या ही कहने। भाई साहब हमें पहली बार अपने वोट की कीमत का एहसास हुआ, साथ में बड़ा वाला दुःख भी हुआ कि हम गांव से छिटके क्यों और खुद छिटके तो ठीक, वोट काहे छिटकवा दिया? फिर भारत तो उत्सवों का देश है ही चुनावों का भी देश है इसलिए हलवाईयों की दुकान भी चलती रहती है। चुनाव के बाद वोटरों की लड्डू खाने की डिमांड जो रहती है।

गांव में प्रधानी की हनक

खैर एक बात तो पक्की है कि नेता चाहे छुटभय्या हो या बड़ैया, उनका जीत से बड़ा कोई नशा नहीं होता वरना क्या कारण है कि ग्राम प्रधानी या ब्लॉक के चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या और कैसे-कैसे जुगाड़ और जतन नहीं किए जाते हैं? जुगाड़-जतन से मतबल खून खराबे से है मियां। पहले विरोधी लाठी-डंडों से निबटाए जाते थे अब तमंचा काम में लिया जाता है। देसी तमंचे से काम चला तो ठीक वरना विलायती वाला, बस काम होना चाहिए। मजाल है कि पुलिस चू-चपड़ करे आखिर आधी पुलिस भी तो गांव को ही बिलांग करती है जी। खास बात ये है कि विलायती तमंचे से जो विरोधियों को निपटा देता है उसकी धाक और धमक तो गांव में वैसे ही बन जाती है। गांव खेड़े में बात पैसे की कभी नहीं होती, बात होती है तो बस मूंछों की। दो की जगह चार बीघा जमीन बिक जाए, लेकिन मूंछ नीचे नहीं होनी चाहिए। चुनाव जीतने के बाद नए प्रधान जी चौपाल में कुछ लठैतों, कुछ चमचों और सरकंडों से बनी प्रधान जी की बड़ी वाली कुर्सी, रोज शाम यहीं नजारा देखने गांव का गांव आ धमकता है। प्रधान जी के

बबुआ का पीडीए है, इसमें कौन-कौन शामिल है उसे ख़ुद को नहीं पता, लेकिन ख़ुद को ट्रंप से कम नहीं समझता, जैसे ट्रंप दुनिया को बर्बाद कर रहा है वैसे ही बबुआ और दत्तात्रेय का वंशज अपनी-अपनी पार्टी को तबाह करने का सपना देख रहे हैं, वैसे मेरी समझ में बबुआ के पीडीए का मतलब पी-यानी परिवार, डी यानी डिंपल और ए-यानी अखिलेश भैया से है।

किस्से कहानियां सुनो, मूड बनाना हो तो चौपाल के एक कोने में दो बूंद जिंदगी की भी ले लो और आधी परात पूरी सब्जी हलक से उतारकर बड़ी वाली डकार मारो और घर की तरफ प्रस्थान कर लो। अगर मूड हुआ तो दीन दुनिया की खबरों पर बहस भी कर लो। अब ट्रंप को तो जानते ही होंगे जो 30 हजार से ज्यादा झूठ बोल चुका है गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने ट्रंप पल-पल में बदलता है। इसलिए ट्रंप के चर्चे गांव तक में है। लिहाजा प्रधान जी ट्रंप में खुद को और कभी-कभी खुद में ट्रंप को देखते हुए चाय के साथ पारलेजी के पांच रुपये वाले बिस्किट को भिगोकर खाते हुए अपनी विशेष टिप्पणी देते और सभा बर्खास्त। लेकिन लेकिन लेकिन....।

हर चीज की एक्सपायरी फिक्स है

कैसा लगता होगा जब कोई चुनाव सिर्फ इसलिए लड़े कि उसे चुनाव हारना है तो। न...न...न...आप गलती से सही समझ रहे हो मियां। मैंने कहा था न अपने देश में एक से एक लकड़ बग्घे पड़े हैं जो गांधी जी की आत्मा को शांति दिलाकर ही मरना चाहते हैं वरना क्या कारण है कि 96 चुनाव हारने के बाद भी सो कॉल्ड दत्तात्रेय का वंशज हार की सेंचुरी पूरी करने के लिए उतावला है। भई उस पे फर्क पड़े या न पड़े पर 96 हार से देश की सबसे बूढ़ी पार्टी की कमर तो टूट ही रही है। अब पार्टी बूढ़ी है तो दत्तात्रेय का वंशज भी क्या कर सकता है? क्योंकि इस पार्टी की इमारत तो लखोड़ी ईंटों से बनी है जो 141 साल से जैसे-तैसे सब कुछ झेल कर खंडहर हो रही है। अच्छी बात ये है कि इस पार्टी की नींव रखने वाला एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज था। अगर कहीं ये मिंग-शिंग-झे होते तो चांद तो छोड़ो ये इमारत शाम से पहले ही अपनी मिट्टी पलीत करवा लेती। क्योंकि मिंग-शिंग-झे तो नो गारंटी वाला फार्मूला है। खैर ऊपर वाले ने हर चीज की एक्सपायरी फिक्स कर रखी है। पर दत्तात्रेय के वंशज एक्सपायरी का ठीकरा भी सामने वाले पर फोड़ते हैं, यानी वोट चोरी हो गए, ईवीएम ने धोखा दे दिया, जानबूझ कर हरा दिया गया। खैर जनसंघ की एक्सपायरी आई तो विलुप्त तो हुई पर भाजपा के रूप में जन्म ले लिया। यानी भाजपा का सूर्य सिर्फ उदय ही नहीं हुआ वरन चमका भी और खूब जोर से चमक भी रहा है। सीटों में भले ही फर्क आया हो लेकिन नीयत में कतई कोई फर्क नहीं है। जिन विचारों को लेकर जनसंघ चला, उन्हीं विचारों के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग-डेटिंग दोनों बढ़िया चल रही है। ऐसा इसलिए भी कि भाजपा के शीर्ष को ये मालूम है कि 'जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है...।' इसके उलट विपक्षी खासकर कांग्रेस अपने गढ़ बचाने में लाचार है। एक यूपी का बबुआ है वो भी दत्तात्रेय के वंशज की तरह भ्रमजाल में फंसा हुआ है। इस बबुआ का पीडीए है, इसमें कौन-कौन शामिल है उसे खुद को नहीं पता। लेकिन खुद को ट्रंप से कम नहीं समझता। जैसे ट्रंप दुनिया को बर्बाद कर रहा है वैसे ही बबुआ और दत्तात्रेय का वंशज अपनी-अपनी पार्टी को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। वैसे मेरी समझ में बबुआ के पीडीए का मतलब पी-यानी परिवार, डी यानी डिंपल और ए यानी अखिलेश भैया से है। इसमें बाकी की गुंजाइश कहां रह जाती है।

दत्तात्रेय के वंशज सेंचुरी के करीब

अब ऐसा तो है नहीं कि वो इस तरह की महत्वाकांक्षा पालने वाले पहले व्यक्ति हैं उनसे पहले भी जाने कितने आए और जाने कितने गए, लेकिन उनकी महत्वकांक्षा मरते दम तक उनके साथ चिपकी रही। आपको याद होगा 'धरती पकड़' अजी हां वही काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ बरेली वाले अजी वही उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जहां 1966 में मेरा साया फिल्म की नायिका साधना का झूमका गिरा था। एक सच्ची बात और जान लो भय्या कि 1941 में हरिवंश राय बच्चन की पत्नि तेजी बच्चन का सोने का झूमका वास्तव में बरेली में गिर गया था, राजा मेंहदी अली खान ने इस घटना को गाने में पिरो दिया और भय्या गाना भी सुपर-डुपर हिट हो गया। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 किलो का झुमका बरेली चौक में रखवा दिया यानी एक गाने ने कमाल कर दिया। तो भैय्या वही काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ (जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए उम्र भर उस कार्य से चिपका रहे जैसे काका जोगिंदर सिंह) ने कुल जमा 36 बरस में 350 से ज्यादा चुनाव लड़े और सारे के सारे हारे ही एक बार भी जमानत नहीं बची। वो खुद ही वोटरों से कहते थे भय्या मुझे वोट मति देना। इसके अलावा कानपुर के भगवती प्रसाद घोड़े वाला और ग्वालियर के मदन लाल। ये सभी चुनाव लड़े ही इसलिए कि चुनाव हार जाएं। काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ के अलावा तमिलनाडु के मैतुर शहर के पद्मराजन चिरस्थाई चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं ये महराज अभी तक 238 चुनाव हार चुके हैं । इन्हें भले ही जोगिंदर सिंह की तरह इलेक्शन किंग के रूप में याद न किया जाता हो किंतु इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में जरूर दर्ज किया गया है। अब दत्तात्रेय के वंशज विश्व रिकार्ड बनाने में खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। वो धरती पकड़ से इंप्रेस हैं कि चुनाव के दौरान भले वोट मांगे लेकिन कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लोग समझ जाते हैं कि दत्तात्रेय के वंशज को वोट की जरूरत नहीं है। लोग भले ही सेंचुरी सेंचुरी कर रहे हैं पर मुझे लगता है कि दत्तात्रेय का वंशज 96+4=101 का शगुन डाल कर ही मानेगा। चलो कोई तो है जो गांधी की आत्मा की तसल्ली के लिए कुछ तो योगदान कर रहा है। वरना धरती पकड़ हो या घोड़े वाला या कोई और उनका योगदान सिर्फ इतना था कि खुद के लिए

दत्तात्रेय का वंशज पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हारेगा और खुशी में मिठाई खाने विदेश भ्रमण पर निकल जाएगा, अगले चुनाव में हार के टिप्स लेकर आएगा और शान से सीना चौड़ा करके बोलेगा कि मैं हारा नहीं हराया गया हूं, यानी गिरे तो भी टांग ऊपर रहेगी।

लड़े खुद ही हारे लेकिन हंसते हुए। क्योंकि वो चुनाव लड़ ही हारने के लिए रहे थे। लेकिन ये दत्तात्रेय का वंशज पांच राज्यों में हारेगा और खुशी में मिठाई खाने विदेश भ्रमण पर निकल जाएगा। अगले चुनाव में हार के टिप्स लेकर आएगा और शान से सीना चौड़ा करके बोलेगा कि मैं हारा नहीं हराया गया हूं यानी गिरे तो भी टांग ऊपर रहेगी।

खेड़ा का पेड़ा बनेगा?

अब लो जी चलते चलते बात इलेक्शन कमीशन की भी कर लो जी। पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जहां इस बार धूम-धड़ाका, मार-काट, विस्फोट पर इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल कर रखा है वहीं वोटर्स से वादा किया है कि चुनाव के बाद भी उनकी सुरक्षा की जाएगी। बिना खौप के वोट डाले, लेकिन जिसकी सत्ता खिसक रही है वो वोटर्स को धमका रही है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में खोला होवे का मतलब बदल गया है। इस बार दीदी की जगह दादा आवे का खेला होवे है। यानी 4 मई ममता गई का खेला होवे? हम तो कई महीने पहले ही कह चुके हैं कि चार मई को खेला तो होवे ही होवे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स (दूसरे राज्यों के एसआईआर अधिकारियों) को नौ घंटे बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत भयंकर गुस्से में हैं। अब पता नहीं बंगाल का ऊंट इस बार क्या करवट बदलेगा? मुझे तो लगता है कि दीदी अपने कर्मों का फल इस बार अवश्य प्राप्त करेंगी। बात असम की भी जरूरी है क्योंकि अपने हेमंता बिस्वा सरमा असम की सपाट पिच पर अपनी धुंआधार बल्लेबाजी कर ही रहे थे कि दत्तात्रेय के वंशज के एक चेले ने बखेड़ा कर दिया। हेमंता को फंसाने के चक्कर में खुद ऐसा फंसा कि अब घर का है न बहार का, जान बचाने के लिए भागा-भागा फिर रहा है। जो टीवी पर बैठ कर कांग्रेस के दफ्तर में बैठ कर फुदकता था और मोदी शाह के लिए गंदी भाषा बोलता था उसको अब हेमंता बिस्वा सरमा पेलने वाले हैं। हेमंता ने साफ-साफ कह दिया है कि मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। काश हेमंता से पंगा न लिया होता तो खेड़ा दर बदर की ठोकर न खा रहा होता।

क्यों हारी ममता दीदी

मतदान से पहले और बाद में बहुत से लोगों ने बेखौफ होकर कहा कि यह ममता दीदी को हटाने की आंधी है, महिलाएं सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे खौफ के साये में जीवन व्यतीत करें, बंगाल की महिलाएं ही थी जो ताल ठोक रही थी कि परिवर्तन होकर रहेगा, ममता को हटना ही होगा।

उदयभान सिंह
लेखक

भा

रतीय साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायक कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता-

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप-विस्तार किया।

कविता की ये दो लाइन इस समय पश्चिम बंगाल की टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर सटीक बैठ रही है। क्योंकि 15 वर्षों से लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर सवार ममता बनर्जी इस बार के विधनसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल हो गई। एक स्ट्रीट फाइटक की छवि वाली महिला की शर्मनाक हार की कई वजह हो सकती है, लेकिन जब विवेक ही काम न करे तो फिर विरोधी तो हावी हो ही जाएंगे। ममता बनर्जी भी परिवारवाद का शिकार हो गई। भतीजे अभिषेक बनर्जी को लॉन्च करने के चक्कर में वो धृतराष्ट बन गई। भतीजा अभिषेक भी सत्ता की पावर में नेता की जगह डॉन बन गया। उसके संरक्षण में अवैध वसूली, टोलाबाजी, कटमनी, गौ तस्करी, महिला उत्पीड़न, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला होने लगा। पेशेवर अपराधियों ने पश्चिम बंगाल की हर सड़क पर टोलाबाजी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में घर बनाने से लेकर नया कारोबार शुरू करने के लिए टीएमसी के गुंडों से परमीशन लेनी होती थी। यहां तक कि यदि रेलवे स्टेशन या एयर पोर्ट से टैक्सी बुक करनी हो तो भी टीएमसी के गुंडे वसूली करते थे। टीएमसी में घोटालों की मास्टर माइंड आई-पेक कंपनी थी, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम भी करती थी। आई-पेक कंपनी टीएमसी की रणनीतिकार थी। इसलिए टीएमसी में उसका सिक्का चलता था। 2021 के बाद बंगाल के हर लोकल चुनाव तक में आई पेक ने ही प्रत्याशी तय किए। टीएमसी का टिकट बेचने का काम भी आई-पेक ही करती थी। विधानसभा चुनाव में भी आई-पेक ने जमकर टिकट बेचे। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले ईडी ने आई-पैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप था। साथ ही खबर आई कि आई-पेक ने अपने कर्मचारियों को चुनाव के दौरान छुट्टी पर भेज दिया है। कुल मिलाकर बंगाल में आई-पेक कंपनी और अभिषेक बनर्जी ने खुली लूट मचा रखी थी। इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिला।

ममता बनर्जी ने भी वही गलतियां की जो परिवारवादी पार्टियां करती है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने गलती की वही गलतियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की। बिहार में एसआईआर होने पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर 15 दिनों तक बिहार में यात्रा निकालते रहे ठीक वैसे ही ममता बनर्जी ने डेढ़ से दो महीने चुनाव आयोग से टकराव में बर्बाद कर दिए। यानी ममता बनर्जी का आम वोटर से फोकस हट गया। लेकिन एसआईआर न तो बिहार में और न ही पश्चिम बंगाल में रुका बल्कि जो समय 2026 के विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने, संगठन को सक्रिय करने और चुनाव जीतन के लिए जनता से जुड़ने का था वो समय ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से टकराव में बिता दिए। जबकि चुनाव में पीएम मोदी का जनता से जुड़ने अनोखा अंदाज देखा गया। पीएम मोदी के बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक गुमटी पर रुकने और 10 रुपये की झालमुड़ी खरीद कर खाने को एक आम नेता की छवि के रूप में देखा गया। इस विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का ये नारा भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया कि-'पालटानो दोरकार, चाई बीजेपी सोरकार।' यानी परिवर्तन जरूरी है और चाहिए बीजेपी सरकार।

ममता सरकार के घोटालों की फेरिस्त

ममता बनर्जी सरकार के 15 वर्षों में घोटाले पर घोटाले होते रहे। शिक्षक भर्ती घोटाला सबसे चर्चित घोटालों में से एक रहा। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरियां दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने 2016 के पूरे जॉब पैनल को ही रद्द कर दिया था, जिससे लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई और तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जेल जाना पड़ा। चिटफंड घोटाला जो एक पोंजी योजना थी जिसमें लाखों

पश्चिम बंगाल चुनाव के पुराने रिकार्ड को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी के लिए पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले अफसरों व कर्मचारियों को हटा दिया, कुछ अफसरों को पर्यवेक्षक बनाकर दूसरे राज्यों में चुनाव कराने के लिए भेज दिया, बंगाल के मतदाता बिना किसी भय के मतदान करें इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

निवेशकों से लगभग 2,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। यह सारदा से भी बड़ा घोटाला था। ममता सरकार पर कोयला घोटाला और पशु तस्करी का भी आरोप है। कोयले का अवैध रूप से उत्खनन खुलेआम कराया गया और उसे बेचकर मोटी रकम टीएमसी नेताओं ने हजम कर ली। इस घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंची और परिवार के सदस्यों से पूछताछ हुई। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की अवैध तस्करी में टीएमसी के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल को जेल यात्रा करनी पड़ी थी। नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती में धांधली के आरोप पश्चिम बंगाल की जनता भूली नहीं थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, जिसमें ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कई टीएमसी नेताओं को कैमरे पर रिश्वत लेते देखा गया था। ममता बनर्जी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड का भी दुरुपयोग हुआ। हालांकि ममता बनर्जी इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती है। टीएमसी के प्रमुख नेताओं के भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हर मतदाता के दिलो दिमाग में गहराई तक जख्म कर चुकी थी। क्योंकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना ने पश्चिम बंगाल की जनता में ममता बनर्जी की छवि एक महिला विरोधी तानाशाह की बना दी थी। यही जनआक्रोश मतदान में देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर नहीं देख रही थीं, बल्कि उन्हें हार का आभास हो रहा था। इसलिए एक रैली में मंच से लोगों का धन्यवाद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा 'रहा ये गुलशन, तो फूल खिलेंगे। रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे। अनेक-अनेक धन्यवाद' नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जोहार, इंशाअल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बस चलते-चलते ममता दीदी का ये संबोधन उनकी हताशा, निराशा, लाचारी और पराजय का दर्शन कराने वाला था। ममता बनर्जी की हार के यज्ञ में घी डालने का काम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में बढ़ते पोलराइजेशन की वजह से भाजपा को मौका मिला। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर राज्य में साफ-सुथरी सरकार चलती, तो हालात कुछ और होते।

चुनाव आयोग की सख्ती

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से टकराव भी सत्ता से बेदखली का बड़ा कारण बना। क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की शक्तियों को समझने में गलती कर दी। पश्चिम बंगाल चुनाव के पुराने रिकार्ड को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी के लिए पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले अफसरें व कर्मचारियों को हटा दिया। कुछ शातिर अफसरों को तो पर्यवेक्षक बनाकर दूसरे राज्यों में चुनाव कराने भेज दिया। बंगाल के मतदाता बिना किसी डर और भय के मतदान करें इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पश्चिम बंगाल ही क्या किसी भी राज्य में चुनाव ड्यूटी करने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों की ड्यूटी स्थानीय प्रशासन और पुलिस अफसर लगाते रहे हैं। जो स्थानीय पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्थानीय प्रशासन के स्थान पर पश्चिम बंगाल में ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ के अफसरों को दी गई। यानी सुरक्षा व्यवस्था से लोकल प्रशासन को अलग कर दिया। बस चुनाव आयोग के इसी एक्शन से टीएमसी के गुंडों की कमर टूट गई। क्योंकि 2021 के चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस या प्रशासन का आदेश मिले बगैर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जनता के बीच जाकर भरोसा दिलाया कि वो निडर होकर मतदान करें। सुरक्षा बल पर जनता ने भरोसा किया और 23 व 29 अप्रैल को बेखौफ होकर मतदान किया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के काण टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकल पाए और वोटर्स के मन से टीएमसी के गुंडों का खौफ निकाल गया। आम तौर पर बंगाल चुनाव में सुबह से दोपहर 2 बजे तक मतदाता वोट डालने आते थे। इसके बाद टीएमसी के गुंडे पुलिस की मदद से 2 बजे से 4 बजे तक फर्जी मतदान करते थे।

बंगाल के चुनाव में यूपी सुर्खियों में

यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा यानी 'सिंघम' नाम से चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित और सुर्खियां बटोरने वाले चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक रहे। शर्मा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस आब्जर्वर थे। उन्होंने ड्यूटी संभालते ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंच कर चेतावनी दी कि चुनाव में गड़बड़ी की तो सही से इलाज किया जाएगा। जवाब में जहांगीर ने फिल्मी अंदाज में चुनौती दे दी कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। बस फिर क्या था शर्मा टीवी डिबेट का विषय बन गए। टीवी डिबेट में पता चला कि जहांगीर चुनाव के दौरान गैर मुसलमानों के वोटर कार्ड जप्त कर लेता था और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देता था। इसके बाद तो टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा को धमकाना शुरू कर दिया। धमकी

ममता बनर्जी गलती पर गलती की, पहले चुनाव आयोग से टकराव फिर उनके समर्थकों ने द्वारा एक अप्रैल को मालदा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन में लगे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को खुले मंच से धमकाना इस बार के चुनाव में टीएमसी पर भारी पड़ा।

दी गई कि चुनाव बाद उन पर एफआईआर होगी और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर यूपी से घसीट कर अदालत लाया जाएगा। जहांगीर खान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खास है और डायमंड हार्बर से सटे फालता विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी है। लेकिन बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अजयपाल शर्मा को धमकी देने वाले बिना शर्त माफी मांगते नजर आए। जबकि जहांगीर खान तो बंगाल ही छोड़कर बांग्लादेश भाग गया।

टीएमसी के गुंडों का सरेंडर

यह वही पश्चिम बंगाल है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का झंडा लगाने वालों के घरों में टीएमसी के गुंडे आग लगा देते थे। परिवार की महिलाओं को उठाकर ले जाते थे। घरों पर बम से हमला कर देते थे। लूटपाट और हिंसा का तांडव होता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की सख्ती और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिले अधिकार की वजह से पश्चिम बंगाल में लोगों ने न सिर्फ घरों और दुकानों पर भाजपा के झंडे लगाए बल्कि खुलकर भाजपा का समर्थन भी किया। वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद बहुत से लोगों ने बेखौफ होकर कहा कि यह ममता बनर्जी को हटाने की आंधी है। हर किसी के जुबान पर परिवर्तन था। महिलाएं सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रही थी। महिलाएं दो टूक कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे खौफ के साये में जीवन व्यतीत करें। बंगाल की महिलाएं ही थी जो ताल ठोक रही थी कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, ममता को हटना ही होगा। सोशल मीडिया पर चल रहे ये संदेश ममता बनर्जी तक न पहुंचे हों ऐसा संभव नहीं था। इसलिए भी टीएमसी के गुंडों ने हथियार डाल दिए। फिर महौल बदलता देख बंगाल पुलिस ने भी पाला बदल लिया। जो कभी टीएमसी के गुंडों का संरक्षण देती थी वही पुलिस गुंडों को दौड़ा-दौड़ा कर न सिर्फ पीट रही थी बल्कि गिरफ्तार भी कर रही थी। साथ ही साइलेंट वोट ने चुपचाप कमल छाप कर किया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला चुनाव है जब बेखौफ होकर लोगों ने मतदान किया और ममता बनर्जी के महाजंगल राज को उखाड़ फेंका।

भाजपा के चक्रव्यूह में फंस गई दीदी

ममता बनर्जी क्या भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब ममता बनर्जी चुनाव आयोग से टकरा रही थी, एसआईआर में लगे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनवा रही थी तब तक भाजपा पन्ना प्रमुखों को घर-घर पहुंचा चुकी थी। पश्चिम बंगाल की जनता के दिल से भय निकाल चुकी थी। 8000 छोटी-छोटी बैठकें कर चुकी थी। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को यकीन दिलाया कि यह चुनाव ममता बनर्जी के जंगल राज से मुक्ति पाने का है। उन्होंने टीएमसी के भय काल को समाप्त करने और भाजपा के भरोसे के सेवाकाल का चुनाव बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में सनातन के नाम पर हिंदुओं को एकजुट किया। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इंशा अल्लाह और अल्लाह की कसम देकर धमकाती रही कि भाजपा का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा। ममता दीदी ने मुस्लमानों भी डराया कि भाजपा आई तो बुलडोजर चलेगा, मांस नहीं खाने देगी, बंगाल ने निकाल देगी। ममता बनर्जी ही नहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे थे कि 4 मई की दोपहर 12 बजे तक पश्चिम बंगाल में रुक कर दिखाना। लेकिन टीएमसी का कोई पैतरा काम नहीं आया। भाजपा ने रणनीति के तहत स्थानीय भाजपा नेताओं को फ्रंट पर रखा ताकि टीएमसी का वो नैरेटिव फेल किया जा सके जिसमें वो भाजपा को बाहरी बताती रही। समिक भट्टाचार्य, दलीप घोष, सुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, स्वपन दास गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पॉल और जगन्नाथ सरकार को आगे कर भाजपा ने टीएमसी के नैरेटिव को फेल कर दिया। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा था तो दूसरी तरफ टीएमसी पर प्रहार करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा, स्मृति ईरानी जैसे फायरब्रांड नेता टीएमसी को धो रहे थे। इस बार भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी हों या संगठन के अन्य नेता सभी मीडिया से दूर रहे। टीएमसी को जवाब देने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और स्थानीय लीडर सामने थे। बाकी पूरा संगठन ममता बनर्जी को हराने की बिसात बिछाने में लगा था। ये सब भाजपा की रणनीति का हिस्सा था। वैसे भाजपा पूरे मनोयोग से चुनाव जीतने के लिए ही लड़ती है।

बनलेखी गांव की अलौकिक सुंदरता

मुक्तेश्वर के करीब बनखेली गांव खूबसूरती के मामले में फेमस हिल स्टेशनों से कहीं आगे है, यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसमें खूबसूरत नैचुरल वाटरफॉल और हरे-भरे घास के मैदान भी हैं, अगर सुकून और खूबसूरती को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये गांव सैलानियों का इंतजार कर रहा है।

कमल कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड के पहाड़ खूबसूरत हैं, शानदार हैं जिनकी हरियाली को निहारने से आंखों के साथ मन को शांति मिलती है। कुमाऊं की सरोवर नगरी नैनीताल तो हमेशा अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। ये बिंदास और खूबसूरत पर्यटन स्थल हर मौसम में पर्यटकों की पहली पसंद होता है। हालांकि यहां जब से हाईकोर्ट बनी है, भीड़ कुछ ज्यादा बढ़ ही गई है। लिहाजा पर्यटक अब नैनीताल के बजाये इसके आसपास के पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं। सैलानियों को अब नैनीताल से करीब 52 किलोमीटर दूर एवं समुद्र की सतह से 2286 मीटर की ऊंचाई पर शांत मुक्तेश्वर धाम आकर्षित करने लगा है। क्योंकि मुक्तेश्वर फलों के बगीचों एवं देवद्वार के घने जंगलों से घिरा है। इस स्थान को 1893 में अंग्रेजों ने अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया था, जो अब भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र (आईवीआरआई) के रूप में जाना जाता है। यहां से हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ दिखाई देती हैं। वैसे मुक्तेश्वर अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। मुक्तेश्वर ही नहीं बल्कि इसके आसपास के गांवों को भी प्रकृति ने नैसर्गिक सुंदरता से नवाजा है। ऐसा ही एक गांव बनलेखी है जो पर्यटकों के लिए खास है। खूबसूरती के साथ-साथ इस गांव की सबसे खास बात ये है कि ये अभी तक गूगल मैप की पहुंच से बाहर है। गर्मी के दिन हों या सर्दी के, सैलानी शहरों से पहाड़ों की खूबसूरत वादियों की तरफ आते ही हैं। गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए और सर्दियों में बर्फ का लुत्फ लेने के लिए। लोग घूमने भी उन डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, जो देश और दुनिया में फेमस होते हैं। लिहाजा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन शांत नहीं रहते और शहर की तरह ही भीड़ और शोर वाले लगने लगते हैं। सीजन में फेमस डेस्टिनेशन के होटल के रूम का किराया दो से पांच गुना तक बढ़ जाता है। टैक्सी किराया भी मुंहमांगा हो जाता है। इसलिए भीड़ और महंगाई से बचना है तो फिर ऐसी जगह जाएं, जहां खूबसूरती और शांति दोनों हों। नैनीताल जिले के काठगोदाम यानी कुमाऊं के आखिरी रेलवे स्टेशन से 65 किलोमीटर दूर बनलेखी गांव शांति के लिहाज से परफेक्ट डेस्टिनेश है।

पहाड़ी जीवन का अनुभव करें

मुक्तेश्वर के करीब बनखेली गांव खूबसूरती के मामले में फेमस हिल स्टेशनों से कहीं आगे है। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसमें खूबसूरत नैचुरल वाटरफॉल और हरे-भरे घास के मैदान भी हैं। अगर सुकून और खूबसूरती को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये गांव सैलानियों का इंतजार कर रहा है। हालांकि बनलेखी इस इलाके के सबसे दूरदराज के गांवों में से एक है इसलिए शांत गांव है। यदि उत्तराखंड की जमीनी संस्कृति के बारे में जानने की उत्सुकता है तो फिर यह गांव एक शानदार पर्यटन स्थल हो सकता है। इस गांव को खूबसूरत यहां के पहाड़ और झरने ही नहीं बनाते हैं, ये जगह खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि यहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते हैं। चालाकी या फरेब करना इनके बसकी बात नहीं है। यहां के सीधे-साधे ग्रामीणों को मेहमानों का अपने घरों में स्वागत करने में बहुत खुशी होती है। इस गांव को पूरी तरह देखना और समझना है तो फिर पैदल घूमे, गांव के लोगों से बात करें, उनकी संस्कृति रहन सहन, खानपान, तीज त्योहार, विवाह संस्कार के साथ उनके पहाड़ जैसे पहाड़ी जीवन का अनुभव अवश्य करें। क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में जानने से ही सैलानियों को एक नई दुनिया के बारे में पता चलेगा। इसी बनलेखी गांव से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर भालू गाद वाटरफॉल है। वैसे भी इस गांव के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन ये भालू गाद वॉटरफॉल टूरिस्टों के बीच बहुत फेमस है। यदि आप इस तरफ यात्रा करने आएं तो इस बनलेखी गांव का नजारा जरूर देखें। यहां के शानदार नजारों और खूबसूरत वातावरण के बीच वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। यहां अपने दोस्तों और फैमिली के साथ पिकनिक पर भी आ सकते हैं। वॉटरफॉल आओ और उसमें डुबकी ना लगाई जाए, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए प्रकृति के इस साफ पानी में एक डुबकी जरूर लगाएं। इसी भालू गाद वॉटरफॉल के पास ही पक्षियों को देखने के लिए बढ़िया जगह है। यहां आएं तो अपने साथ एक दूरबीन और कैमरा अवश्य लाएं। ताकि कुदरत की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया जा सके।

बनलेखी गांव को पूरी तरह देखना और समझना है तो फिर पैदल घूमे, गांव के लोगों से बात करें, उनकी संस्कृति रहन सहन, खानपान, तीज त्योहार, विवाह संस्कार के साथ उनके पहाड़ जैसे पहाड़ी जीवन का अनुभव अवश्य करें, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में जानने से ही सैलानियों को एक नई दुनिया के बारे में पता चलेगा।

मुक्तेश्वर धाम में करें शिव परिवार की पूजा

मुक्तेश्वर की सैर करने वाले सैलानी जिनमें युवाओं की सबसे बड़ी संख्या होती है वो मुक्तेश्वर धाम में शिव परिवार की आराधना अवश्य करते हैं। मुक्तेश्वर धाम इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय ग्रामीणों की भी इस धाम में सबसे ज्यादा आस्था है। क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और नंदी को समर्पित है। मुक्तेश्वर का नाम शिव के एक 350 साल पुराने मंदिर से मिलता है, जिसे मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको धार्मिक यात्रा करना पसंद है, तो इस शानदार मुक्तेश्वर मंदिर को जरूर देखना चाहिए। यह मुक्तेश्वर के आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, ऐसा माना जाता है कि इसे पांडवों ने अपने निर्वासित जीवन के दौरान बनाया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक नजारों से गुजरेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप ट्रैकिंग के लिए तैयार नहीं हैं, तो सीढ़ियों से भी जाने का विकल्प चुन सकते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर के ठीक पीछे प्रसिद्ध चौली की जाली है। प्रकृति प्रेमी हों या एडवेंचर के शौकीन, इस जगह से यकीनन प्यार हो जाएगा। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल होगा कि आखिर इस जगह के बारे में इतना प्यारा क्या है, तो बता दें, चौली की जाली, रॉक क्लाइम्बिंग और रैपलिंग का अनुभव करने के लिए मुक्तेश्वर के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहां एक देवी और एक राक्षस के बीच युद्ध लड़ा गया था, इस वजह से भी ये जगह धार्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है।

अध्यात्म का केंद्र बनलेखी गांव

वैसे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में हर जगह एक अध्यात्मिक स्थान तो मिलता ही है। बनलेखी भी उसमें आता है। गांव के नजदीक ही शिव मंदिर, राजरानी मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर जैसे कई फेमस मंदिर है। लिहाजा यह सब देखने के बाद महसूस होता है कि बनलेखी की यात्रा प्राकृतिक और धार्मिक लिहाज से एक बेहतरीन यादगार यात्रा होती है। एक बार ऐसे डेस्टिनेशन पर आने के बाद बार-बार आने का मन करता है। मुक्तेश्वर और बनलेखी की एक खासियत और है वो ये कि सूर्योदय और सूर्यअस्त का नजारा बड़ा ही मनमोहक होता है। वैसे पहाड़ में सबसे सुंदर दृश्य सूर्योदय का ही होता है। जब पहाड़ की एक चोटी के पीछे से लालिमा को निकलते देखते हैं और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ रोशनी छा जाती है। ये कुछ देर का नजारा जीवन भर याद रहता है। ऐसे ही सूर्यअस्त का नजारा भी अच्छा लगता है। मुक्तेश्वरक की कोई भी यात्रा नंदा देवी चोटी से सूर्योदय के देखे बिना पूरी नहीं होती। नंदा देवी पर्वत देश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर सूरज को देखने के लिए जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह की सुरम्य हवा का अनुभव भी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर के पास ही एक ओर आकर्षक हिल स्टेशन है, जिसे सीतला के नाम से जाना जाता है। यह अपनी खूबसूरती से प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगहों का मिश्रण है। यह क्षेत्र कई औपनिवेशिक शैली के बंगलों से सुसज्जित है, जिसके आसपास हिमालय की शानदार चोटियां दिख जाएंगी। इस विचित्र पहाड़ी शहर की मनमोहक सुंदरता को निहारते हुए यहां ट्रैकिंग और बर्ड वाचिंग का भी मजा लिया जा सकता है।

भोजन का लुत्फ उठाएं

वैसे तो बनलेखी कभी भी आ-जा सकते हैं। यहां पूरे साल मौसम शानदार और खूबसूरत रहता है। इसलिए यहां गर्मियों और सर्दियों में आने की प्लानिंग कर सकते हैं। गर्मियों में मार्च से जून और सर्दियों में अक्टूबर से मार्च का समय आने के लिए बेस्ट है। जुलाई से सितंबर के महीनों में यहां बहुत बारिश होती है, लिहाजा मानसून के दिनों में यहां आने का विचार भी मन में न लाएं क्योंकि भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद मिल सकते हैं। भूस्खलन होता है तो बड़े-बड़े बोल्डर पहाड़ से नीचे आते हैं उनकी चपेट में भी आ सकते हैं। यदि बनलेखी गांव आना है तो फिर यहां खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। इसलिए या तो सैलानी खाने की व्यवस्था करके आए। दूसरा विकल्प ये है कि यदि यात्रा के दौरान गांव वालों के साथ बातचीत होती है तो फिर बनलेखी गांव के निवासी सैलानी को पहाड़ी खाने का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित अवश्य करेंगे। बढ़िया और लजीज जायका लेना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर जा सकते हैं। क्योंकि मुक्तेश्वर में बढ़िया कैफे, रेस्तरां और कई भोजनालय मिल जाएंगे। यहां न केवल अच्छी क्वालिटी वाले उत्तर भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं बल्कि पारंपरिक कुमाऊंनी फूड कप्पा, सिसुनक साग, अलू के गुटके और रस भी खा सकते हैं।

बनलेखी पहुंचने का रास्ता

मुक्तेश्वर और बनलेखी गांव सड़क मार्ग से जुड़े हैं लेकिन ट्रेन से भी यहां पहुंचा जा सकता है। अगर सड़क मार्ग से आना है तो नेशनल हाइवे 9 से बनलेखी गांव पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं बनलेखी के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। जहां से टैक्सी लेकर सीधे बनलेखी गांव पहुंचा जा सकता है। जो काठगोदाम से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। बनलेखी के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में है। पंतनगर से बनलेखी गांव की दूरी 100 किलोमीटर है यहां से टैक्सी बुक करके 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। बनलेखी दूरदराज वाला इलाका है लिहाजा यहां तक बहुत कम ही सार्वजनिक परिवहन जाते हैं। यदि आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस या प्राइवेट बसों से भी यात्रा कर बनलेखी गांव पहुंच सकते हैं। बनलेखी गांव में सिर्फ एक रिजॉर्ट है जिसमें ठहरने के साथ ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। हालांकि मुक्तेश्वर में ठहरने के बहुत ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं।

- **सैलानियों को अब नैनीताल से करीब 52 किलोमीटर दूर एवं समुद्र की सतह से 2286 मीटर की ऊंचाई पर शांत मुक्तेश्वर धाम और इसके आसपास के गांव आकर्षित करने लगे है, क्योंकि मुक्तेश्वर फलों के बगीचों एवं देवद्वार के घने जंगलों से घिरा है।**
- **मुक्तेश्वर के पास ही एक ओर आकर्षक हिल स्टेशन है, जिसे सीतला के नाम से जाना जाता है, यह अपनी खूबसूरती से प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगहों का मिश्रण है, यह क्षेत्र कई औपनिवेशिक शैली के बंगलों से सुसज्जित है, जिनके आसपास हिमालय की शानदार चोटियां दिख जाएंगी।**

खाती के युवा गांव नहीं छोड़ते

खाती गांव की सबसे बड़ी पहचान यहां की उपजाऊ जमीन और पारंपरिक खेती है, गांव में आलू और राजमा की खेती मुख्य रूप से की जाती है यही इस गांव की आर्थिक स्थिति की मजबूत रीढ़ हैं, खाती गांव का राजमा अपने स्वाद के लिए खास पहचान रखता है, यहां के अधिकांश ग्रामीण जैविक खेती को ही प्राथमिकता देते हैं, जिससे यहां पैदा होने वाले उत्पाद शुद्ध और पौष्टिक माने जाते हैं।

हरीश भट्ट
रामनगर

उत्तराखंड पलायन के लिए बदनाम है लेकिन कुमाऊं क्षेत्र का खाती गांव ऐसा है जहां के युवा पहले तो पलायन नहीं करते, यदि रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते भी हैं तो फिर कुछ पैसा कमाकर गांव लौट आते हैं। यानी इस गांव से स्थाई पलायन नहीं होता। कुमाऊं में पिंडारी और कफनी ग्लेशियर के पास बसा आखिरी गांव खाती सीढ़ीदार डिजानिंग वाला गांव है। इस खूबसूरत गांव की कहानी भी पांडवों से जुड़ी हुई बताई जाती है, जो स्वर्ग की ओर जाते हुए इस गांव से गुजरे थे। ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने न केवल पांच पांडवों को रहने के लिए घर दिया था, बल्कि उनका खूब ख्याल भी रखा था। यहां के छोटे लेकिन आकर्षक पत्थर के घर आकर्षित करते हैं। खाती गांव आज भी अपनी पारंपरिक जीवनशैली, सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य को पूरे मनोयोग से संजोए हुए है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गोमती और पिंडर नदियों के संगम क्षेत्र के पास बसा यह गांव पिंडारी, कफनी और सुंदरढुंगा ग्लेशियर ट्रेक का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। इसलिए हर वर्ष देश-विदेश से ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं और कुछ समय के लिए इस शांत पहाड़ी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। खाती गांव की सबसे बड़ी पहचान यहां की उपजाऊ जमीन और पारंपरिक खेती है। गांव के चारों ओर आलू और राजमा की खेती मुख्य रूप से की जाती है यही इस गांव की आर्थिक स्थिति की मजबूत रीढ़ हैं। खाती गांव का राजमा अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए स्थानीय बाजारों में खास पहचान रखता है। यहां के अधिकांश ग्रामीण जैविक खेती को ही प्राथमिकता देते हैं, जिससे यहां पैदा होने वाले उत्पाद शुद्ध और पौष्टिक माने जाते हैं। गांव में प्रवेश करते ही लकड़ी और पत्थर से बने पुराने पहाड़ी मकान, स्लेट की छतें, संकरी पगडंडियां और आसपास बहती नदियां किसी फिल्मी दुनिया की याद दिलाती हैं। आधुनिकता की दौड़ से दूर खाती गांव में आज भी लोक परंपराएं, रीति-रिवाज और सामूहिक जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। सुबह-शाम मंदिरों की घंटियां, खेतों में काम करते लोग और बच्चों की किलकारियां गांव के जीवन को जीवंत बनाती हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी खाती गांव तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहां पारंपरिक शैली में बने कई होम-स्टे उपलब्ध हैं, जहां पर्यटक 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन के किराये में ठहर सकते हैं। इन होम-स्टे में मंडुवे की रोटी, भट्ट की दाल, झंगोरे की खीर और स्थानीय सब्जियां व पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को और खास बना देते हैं। साथ ही ग्रामीणों की आत्मीय मेहमाननवाजी यहां आने वालों को बार-बार लौटने के लिए प्रेरित करती है। खाती गांव ट्रेकिंग के अलावा प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी

टावर है पर नेटवचोटियों के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं, जो सुबह और शाम के समय और भी मनमोहक हो जाते हैं। शहरी भीड़-भाड़, शोरगुल और तनाव भरी जिंदगी से दूर सुकून और शांति की तलाश करने वालों के लिए खाती गांव वास्तव में धरती का स्वर्ग है, जहां हर कदम पर प्रकृति मुस्कुराती नजर आती है जो हर किसी की टेंशन दूर करने के लिए काफी है।

नहीं

बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के इस खाती गांव पहुंचने में बागेश्वर जिला मुख्यालय से चार से पांच घंटे लगते हैं। खाती गांव सड़क मार्ग से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर है जहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है। पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित खाती गांव ऐसा क्षेत्र है जहां इंटरनेट के युग में आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पंहुचा है। यहां के लोग एक दूसरे से वॉकी-टॉकी से संपर्क करते हैं और जरूरी सूचना एक गांव से दूसरे गांव तक देते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय इस क्षेत्र में पहली बार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का टावर लगाया गया था। फिर भी हफ्ते में एक से दो दिन ही नेटवर्क बमुश्किल आ पाता है। इस गांव की खासियत ये है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के बाद भी गांव के अधिकतर युवा गांव में ही रहते हैं। जाहिर है कि हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि जब पलायन पूरे राज्य की गंभीर समस्या बना है तब खाती गांव के युवा गांव में रहकर आजीविका कैसे चला रहे हैं। इसका प्रश्न का उत्तर भी युवा सैलानियों को खुद दे देते हैं। वो बताते है कि इस गांव के पास आजीविका के लिए खेती के साथ पर्यटन और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मौजूद है वह हैं इनकी गांव की वन पंचायत, इनके अपने जंगल हैं। जंगल न केवल जंगली पशु-पक्षियों, कीट पतंगों को बल्कि इनके आस-पास बसे इंसानों को भी पालते हैं और आगे भी पालते रहेंगे। पिंडारी ग्लेशियर के इस भू-भाग के लोग इन्हीं जंगलों से पीढ़ियों से अपनी आजीविका चलाते आए हैं और अभी भी चला रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में कई तरह की जड़ी-बूटियां जैसे बाल जड़ी, हथा जड़ी, कीड़ा जड़ी, अतीस, गोकुल धूप, वन तुलसी और अनेक तरह के वन संपदा मौजूद है। साथ ही रिंगाल से बनने वाले सामान जैसे- टोकरी, सूप और चटाइयां भी यहां के कई दस्तकार बनाते हैं।

बिना युवाओं के गांव वीरान लगते हैं

ग्लेशियर होने के कारण गर्मियों के दिनों में सीजन होता है तो काफी पर्यटक भी यहां आते हैं। कई छोटे-छोटे होम स्टे और गेस्ट हाउस से लेकर ट्रेकिंग तक का काम यहां के युवा करते हैं। स्थानीय युवा इस मौसम में गाइड का काम करते हैं, साथ ही पास के बाछम गांव के लोग घोड़ों और खच्चरों के द्वारा सामान ढोने का काम करते हैं, जिससे इन सभी की आजीविका एक दूसरे से जुड़ जाती है। वैसे पहाड़ के गांव हमेशा ही खूबसूरत ही होते हैं हर कोई उसे देखना और महसूस करना चाहता है। लेकिन उसे जीवंत रखते हैं वहां के लोग, वो भी युवा पीढ़ी। जैसे बिना बच्चों के कोई भी घर सुनसान लगता है। ठीक उसी तरह गांव भी बिना युवाओं के वीरान लगते हैं। हालांकि पलायन ने उत्तराखंड की ग्रामीण हालत को बहुत खराब किया है। गांवों से युवाओं की संख्या तेजी से घटती जा रही है। कोई बेहतर जीविका की तलाश में तो कोई बेहतर शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए गांव छोड़ रहा है। बचे हुए लोग जो किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत है, वो भी अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए राज्य के मैदानी (तराई) क्षेत्रों या देश के महानगरों की तरफ दौड़ रहे हैं। लोग पलायन क्यों करते हैं? यह भी समझना जरूरी है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र का जीवन पशुपालन और कृषि पर आधारित है लेकिन इससे गांव के सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलता। विकास में असमानता भी ग्रामीणों को शहर की तरफ जाने के लिए मजबूर करती है। साथ ही शिक्षा की कमी, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की कमी में भी पलायन करने को विवश करती है। कई गांवों में तो जातीय संघर्ष की वजह से भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते हैं। गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती है।

सीजनल पलायन

जब अंग्रेज भारत में आए तो वह धीरे-धीरे पूरे देश भर में फैल गए थे। अंग्रेजी शासकों ने ठंडे स्थानों नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोसानी, शिमला, दार्जिलिंग आदि का चयन अपने रहने के लिए किया। खाती गांव में भी ब्रिटिशकाल

गर्मियों के सीजन में काफी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं, कई छोटे-छोटे होम स्टे और गेस्ट हाउस चलाने के साथ ट्रेकिंग तक का काम यहां के युवा करते हैं, स्थानीय युवा इस मौसम में गाइड का काम करते हैं, साथ ही पास के बाछम गांव के लोग घोड़ों और खच्चरों के द्वारा सामान ढोने का काम करते हैं, जिससे इन सभी की आजीविका एक दूसरे से जुड़ जाती है।

का एक बंगला आज भी मौजूद है जो 1890 में बनाया गया था। अब इसे लोकनिर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर से पिंडारी तक ब्रिटिशकाल में ही एक पैदल मार्ग बनाया गया था जो इस क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों के आने जाने का सुगम रास्ता है, यह आज भी देखने को मिलता हैं। हालांकि पहाड़ के किसी भी क्षेत्र के लिए मुख्य सड़क से जुड़ना जरूरी माना जाता है। क्योंकि उससे क्षेत्र में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ यातायात की सहूलियत मिल जाती है। बागेश्वर के बाछम से खाती गांव को भी मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। यही ब्रिटिश काल का पैदल मार्ग था जो अब सड़क का रूप ले चुका है। लेकिन कई बार हम खतरों को नजर अंदाज कर देते हैं। क्योंकि भविष्य में संसाधन बढ़ेगे तो इस क्षेत्र के लोगों के कई रोजगार के साधन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भविष्य में जब पर्यटक सीधे अपने साधनों से खाती गांव पहुंचने लगेंगे तो इन गांवों के लोग घोड़ों खच्चरों से पर्यटकों का सामान ऊपर लाने या नीचे पहुंचाने का काम कैसे करेंगे? यानी घोड़े-खच्चरों के सहारे आजीविका चलाने वालों का क्या होगा? पहले बागेश्वर से बाछम तक ही सड़क मार्ग था, तो इस क्षेत्र के युवा अधिकतर पिंडारी जाने वाले पर्यटकों का सामान खाती गांव तक घोड़ों और खच्चरों से पहुंचाते थे। बाकी समय खेती और होम स्टे, छोटे-छोटे होटल चलाकर अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन जब संसाधन बढ़ते हैं तो फिर नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर ब्लाक की तरह पूरे पहाड़ पर होटल और रिसोर्ट की बाढ़ सी आ जाती है।

वन विभाग ने लगाया प्रवेश शुल्क

अगर खाती और बाछम जैसे गांवों की बात करें तो यहां के लोगों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों की स्वायत्तता और हक हुकूकों को नजरअंदाज करते हुए उनकी प्राकृतिक संपदा को लूटने की कोशिश है। जिसके लिए वन विभाग व सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हाल ही में वन विभाग द्वारा कई संस्थाओं पर टूरिज्म के नाम पर लोगों से रख रखाव के नाम पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूलना शुरू किया है। लेकिन वन विभाग किसी तरह का रखरखाव नहीं करता। इसलिए शुल्क लेने का वन विभाग को कोई अधिकार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्योंकि वन विभाग की मनमानी से टूरिस्ट इस इलाके में आने से बच रहे हैं। वन विभाग लोगों की स्थानीय वन उपज के उपयोग पर भी पाबंदी लगा रहा है जिससे लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ने लगा है। समय रहते अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब वन विभाग इन जंगलों से मिलने वाली प्राकृतिक वन संपदाओं पर नियंत्रण हासिल करके किसी कंपनी को ठेके पर दे देगा और अपने ही जल जंगल जमीन से लोगों को दूर होना पड़ेगा।

जड़ी बूटी से कमाई

गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो गांव के युवा बुगयालों में जड़ी बूटी खोजने के लिए निकल जाते हैं जिससे एक व्यक्ति दो महीनों में लगभग 60 से 80 हजार रुपये तक की जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेते हैं। जिस घर में जितने अधिक लोग होंगे उनकी कमाई उतनी ही अधिक होती है। इसलिए गांव के जो युवा काम के लिए या उच्च शिक्षा पाने के लिए शहरों या अन्य राज्यों में जाते हैं, वो सभी युवा इस समय छुट्टी लेकर वापस अपने गांव आ जाते हैं। यहां के कुछ लोगों का मौसमी पलायन मध्य प्रदेश, यूपी व बिहार जैसे राज्यों की तरफ होता है। यानी कुछ युवा मैदानी या दूसरे राज्यों में मजदूरी अथवा निजी कम्पनियों में काम करने चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अपने घर लौट आते हैं। यानी यहां के कुछ युवा सीजनल पलायन अवश्य करते हैं।

प्रेरक कथा

मानापमान क्या है?

आप किसी को बदल नहीं सकते, बदलना तो खुद को ही पड़ेगा, स्वयं को परिवर्तित कर सको तो जमाना न केवल बदलता प्रतीत होगा अपितु बदलेगा भी लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, धैर्य अथवा सहिष्णुता का विकास करना भी एक अच्छा परिवर्तन और एक अच्छी शुरुआत है।

सीताराम गुप्ता
पीतमपुरा दिल्ली

निदंक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय मशहूर-ओ-मारूफ उर्दू शायर मिर्जा 'गालिब' का एक शेर हैः-

निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन,
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

ये इज्जत-आबरू, ये बेइज्जती अथवा मानापमान क्या है? हमारे शरीर में इनका स्थान कहां पर है? वस्तुतः इनकी भौतिक सत्ता होती ही नहीं। ये सब मन के स्तर पर घटित होता है और मन तो, इसको जैसा समझाओगे, बताओगे वैसा ही मान लेगा और करेगा। जैसा हमने मन में सोच रखा है वैसा हो जाए तो सुख अन्यथा दुःख। दूसरों से जैसा आचरण हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो इज्जत अन्यथा बेइज्जती। एक शेर और

खुल्द से आदम न निकले होंगे इस तौकीर से,
उस ने खुद उठ कर उठाया अपनी महफिल से मुझे।

ये साहब तो न सिर्फ 'गालिब' को चार कदम पीछे छोड़ देते हैं अपितु इनका तो अंदाज ही निराला है। इनके लिए तो महफिल से निकाला जाना और खुद महबूबा द्वारा महफिल से निकाला जाना तौकीर अर्थात प्रतिष्टा की बात है जो इन्हें हजरत आदम से भी बड़ा कर देती है। अपना-अपना अंदाज है। मानापमान से बचना है तो इससे अच्छा उपचार और क्या हो सकता है? थोड़ा-सा दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की जरूरत है और थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है फिर किसमें ताकत है जो आपका अपमान कर दे अथवा आपको दुख पहुंचा दे? यह आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करता है कि आप किसी घटना को किस रूप में लेते हैं। यदि वास्तव में कोई ऐसी छोटी-मोटी घटना घट जाती है जो आपके लिए अपमान या बेइज्जती का सबब बन जाती है तो सोचिए क्या एक छोटी-सी घटना आपको विचलित करके रख देगी और आप स्वयं पर नियंत्रण खो बैठेंगे। बिलकुल नहीं। यदि आप कहते हैं कि हां ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है और मैं इसे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आप में धैर्य या सहिष्णुता नाम की कोई चीज है ही नहीं और इस स्थिति में आप सचमुच अपमान के अधिकारी हैं। आप स्वयं अपना अपमान करवाना चाह रहे हैं। आप स्वयं अपने अपमान का कारण बन रहे हैं। आप में खुद का तमाशा बनते देखने की चाह पैदा हो रही है। आप इस स्थिति को स्वीकार कर स्वयं खुद को अपमानित करने की स्वीकृति दूसरों को दे रहे हैं। वास्तव में आपकी सहमति के बिना कोई आपका अपमान नहीं कर सकता।

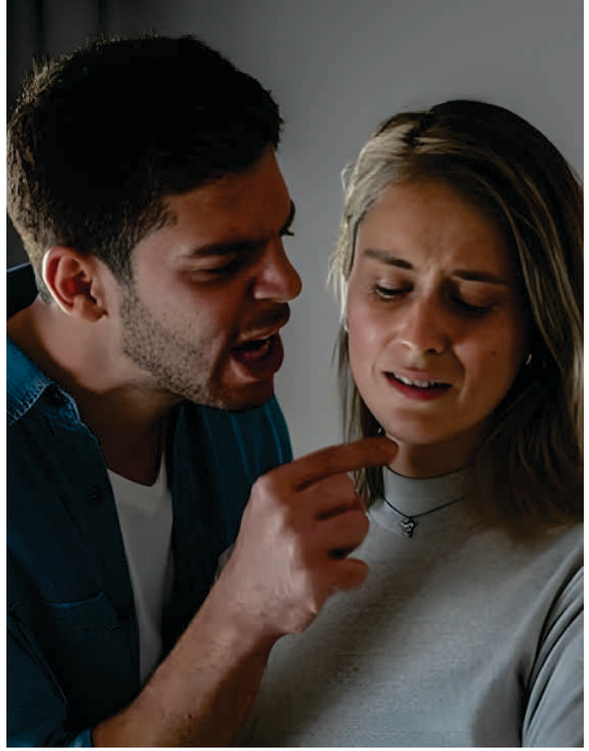

निदंक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय,
बिनु साबुन पानी बिनु निर्मल करे सुभाय।

आपको रोकने-टोकने वाला, आपकी गलती बताने वाला आपका शत्रु या अपमान करने वाला नहीं अपितु आपका परममित्र और शुभचिंतक है। बशीर बद्र का एक शेर हैः-

जिसकी मुखालफत हुई मशहूर हो गया,
इन पत्थरों से कोई परिंदा गिरा नहीं।

अपनी परवाज को, अपनी उड़ान को सलामत रखना है, ऊंचे उड़ते रहना है तो विरोध या अपमान को स्वीकार करना सीखें। संसद से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक में सभी जगह विपक्ष या विरोधी या आलोचक की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानापमान एक सापेक्ष स्थिति है। जीवन में हम न जाने कितनी बड़ी-बड़ी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी आर्थिक संकट तो कभी भयंकर बीमारी। कभी कोई भीषण दुर्घटना तो कभी अपने किसी प्रियजन के बिछोह की स्थिति। जीवन में घटित इन बड़ी-बड़ी समस्याओं से किसी के द्वारा कही गई छोटी मोटी कड़वी बात या कटूक्ति या अपमानजनक टिप्पणी को उसकी तुलना में तुच्छ समझकर बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इससे भी अपमानजनक स्थिति आ सकती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। उर्दू शायर शुजाअ खावर कहते हैंः-

गुजारे के लिये हर दर पे जाओगे 'शुजाअ' साहब,
अना का फलसफा रह जाएगा दीवान में लिखा।

अपमानित या मर्माहत होकर व्यक्ति न केवल नई दृष्टि तथा दृष्टिकोण का विकास कर सकता है अपितु नई दृष्टि और नए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विषम परिस्थितियों में ही सहजता से किया जा सकता है, हर स्थिति व्यक्ति को आत्म-विश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है।

सच जब जीवन-वृत्ति या रोजगार की बात आती है तो हम देखते हैं कि इसके लिए कितने समझौते करने पड़ते हैं। जो काम पसंद नहीं वो करना पड़ सकता है। आदमी जिन सिद्धांतों के लिए जीवनभर संघर्ष करता रहा एक पल में उन सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़ जाती है। बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए न जाने कितने लोगों की सलाह और सहायता लेनी पड़ सकती है। अनेकानेक विषम परिस्थितियों से जूझते जाना और सही रास्ता निकाल लेना ही जीवन है और इन परिस्थितियों में निंदा, अपमान और विरोध जैसी परिस्थितियां भी सम्मिलित हैं। एक शेर हैः-

हकपरस्ती है बड़ी बात मगर,
रोज किस-किस से लड़ा कीजेगा।

आप किसी को बदल नहीं सकते। बदलना तो खुद को ही पड़ेगा। स्वयं को परिवर्तित कर सको तो जमाना न केवल बदलता प्रतीत होगा अपितु बदलेगा भी लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। धैर्य अथवा सहिष्णुता का विकास करना भी एक अच्छा परिवर्तन और एक अच्छी शुरुआत है। विरोध कम से कम हो तो मानव की ऊर्जा की बचत ही है और इस ऊर्जा का उपयोग अन्य रचनात्मक कार्यों अथवा अन्य किसी सकारात्मक दिशा में किया जा सकता है। समझदार व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपेक्षा फेंकी गई ईंटों को एकत्र कर उनसे मजबूत दीवार बना लेता है। मानापमान पूर्णतः एक काल्पनिक स्थिति है। आप भी मानापमान के प्रति निरपेक्ष होकर तथा अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन करके सुखी-संतुष्ट जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाइए। इस प्रेरक कथा का सार सझने के लिए आसान सी एक कहानी बुद्ध से जुड़ी है।

मानापमान अथवा उपेक्षा के भय से स्थितियों से पलायन करना अविवेकपूर्ण निर्णय है, स्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, कि मैं अपमान करने का प्रयास करने वाले या मिथ्या दोषारोपण करने वाले को अपना मित्र बनाकर ही दम लूंगा न कि उसको नीचा दिखाने का अवसर खोजें, यदि आप भी बदले की भावना से कार्य करेंगे तो उसे कभी सही और गलत का पता नहीं चल सकेगा।

बुद्ध की कहानी

एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का मुखिया कुछ ज्यादा ही नाराज था। वह तो बुद्ध को गंदी से गंदी गालियां ही दे रहा था। लेकिन बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद-मंद मुस्कराते रहे। मुखिया काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा। लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई है, तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देख कर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं। लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मंद-मंद मुस्करा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते, तो मजा आ जाता। क्योंकि दस वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूं। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ चुका हूं। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में अस्मर्थ हैं। तुमने मुझे जो गालियां दीं, यह तुम्हारी भावना है। लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा, जब मैं इसमें भागीदार हो जाउंगा। जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं। इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूं। हैरान गांव का मुखिया कहने लगा कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सरेआम तुम्हें गालियां दी हैं और वो पूरे गांव के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? इस पर बुद्ध ने समझाया कि कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और मुझसे उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है। इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया। क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं, तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है न? इसके बाद तो सबके सब बुद्ध के चरणों में पड़ गए। ●

उत्तरांचल दीप
पत्रिका

उत्तराखंड की तेजी से बढ़ती मैगजीन
चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने, नैनीताल रोड हल्द्वानी
देहरादून कार्यालयः-11 लिटन रोड देहरादून (उत्तराखंड)

सदस्यता फार्म

प्रबंधक
उत्तरांचल दीप
हल्द्वानी (नैनीताल)

मान्यवर,
मैं उत्तरांचल दीप पत्रिका की एक वर्ष की सदस्यता लेना चाहता हूं। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रुपये 450 नकद, बैंक ड्राफ्ट,चेक संख्या.......................................भेज रहा हूं। मुझे पत्रिका भिजवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मेरा पता इस प्रकार है। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट उत्तरांचल दीप के नाम से स्वीकार होगा।

सदस्य का नामः-

पिता अथवा पति का नामः-

डाक का पताः-

तहसीलः-

जिलाः-

मोबाइल नंबरः-

ई-मेलः-

यदि आपको लेखन में रुचि है तो आप लेख अथवा स्टोरी लिखकर उत्तरांचल दीप पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं। संपदकीय टीम द्वारा आपकी स्टोरी का चयन करने पर आपके लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। याद रखें कि स्टोरी अथवा लेख आपका मूल होना चाहिए। अच्छी स्टोरी व लेख को उत्तरांचल दीप पत्रिका द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

संपादक

उत्तराखंडी जनजीवन का जीवंत रेखांकन

पुस्तक को अपने जीवनकाल पर केंद्रित करते हुए कुबेर सिंह ने एक आम उत्तराखंडी ग्रामीण व्यक्ति की जीवन कथा को सार्वजनिक किया है, इसमें हम-सब अपने जीवनीय हिस्सों की तस्वीरें देख और समझ सकते हैं, एक पहाड़ी बालक की नैसर्गिक सहजता, संकोच, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य के प्रति दृढ़ता इसमें है।

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी (गढ़वाल)

फरवरी, 1970, भिकियासैण के शिवरात्री मेले में एक 14 वर्षीय किशोर किताबों के फड़ के आस-पास संकोच और जिज्ञासा से बहुत देर तक किताबों के पन्ने पटलता जा रहा था। मेले में वह दोस्तों से बार-बार अलग होकर फिर उसी किताबों के फड़ में आकर अन्य किताबों को टटोलता। यह क्रम पूरे दिन भर थोड़े-थोड़े अंतराल में कई बार चलता रहा। आखिर उसने साहस कर पुस्तक विक्रेता से पूछ ही लिया कि क्या उसकी भी लिखी पाण्डुलिपि किताब के रूप में प्रकाशित हो सकती है? पुस्तक विक्रेता चिंतामणि पालीवाल ने 'कुमाऊंनी साहित्य मंडल, दिल्ली' का संपर्क सूत्र देकर किशोर की पुस्तक प्रकाशन की राह आसान कर दी। 'पुस्तक हाथ में आने के बाद उसे अनेक बार देखता रहा लेकिन जी नहीं भरा। रात को बार-बार नींद खुलती तो पुस्तक को देखकर सीने से लगा लेता। यह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय, सुखद और आश्चर्यजनक घटना थी। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी पुस्तक इतनी जल्दी प्रकाशित हो जायेगी।' यह किस्सा 1971 की किसी रात का किशोरवय कुबेर सिंह कड़ाकोटी का है, जो मात्र 65 पैसे मूल्य की अपनी तरोताजा प्रकाशित किताब 'शिव-पार्वती विवाह' को पाकर रात-भर आनंदित रहा। कुबेर सिंह कड़ाकोटी की सृजनात्मक प्रतिभा का ही कमाल था कि किशोरावस्था में स्वरचित उनका कुमाऊंनी खंड काव्य 'शिव-पार्वती विवाह' को 'कुमाऊंनी साहित्य मंडल, दिल्ली' द्वारा प्रकाशित किया गया था।

कुबेर सिंह कड़ाकोटी का सानिध्य मिला

लोक साहित्य के मर्मज्ञ चिंतामणि पालीवाल और नारायणदत्त पालीवाल के संयोजन में संचालित 'कुमाऊंनी साहित्य मंडल, दिल्ली' द्वारा 'शिव-पार्वती विवाह' पुस्तक को 1971 की सर्वश्रेष्ठ कुमाऊंनी काव्यकृति से सम्मानित किया गया था। उसी किशोर कड़ाकोटी ने 'शिव पार्वती विवाह' के बाद 1971 में ही 'कुमाऊंनी रामलीला' नाटक लिखा। वर्तमान में कुमाऊंनी लोक-साहित्य की ये दोनों अनुपम कृतियां मानी जाती है। खुशी की बात ये है कि 1971 के 48 साल बाद 2019 में 'शिव-पार्वती विवाह' पुस्तक पुनः प्रकाशित हुई है। शिक्षक, लेखक और लोकप्रिय समाजसेवी कुबेर सिंह कड़ाकोटी की सामाजिक प्रतिबद्धता जग-जाहिर है। मेरा सौभाग्य है कि राजकीय सेवाकाल में मुझे उनका आत्मीय सानिध्य और मार्गदर्शन मिला। उनके विचारों की स्पष्टता और कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना उनकी गरिमामयी उपस्थिति को विशिष्ट बना देती थी। उनका सानिध्य मुझे और बेहतर कार्य करने की ओर प्रेरित करता था। मेरे लिए वे मार्गदर्शी की भूमिका में रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पिता और पुत्र आपके बिल्कुल बराबर के पक्के मित्र हों। संयोग से बड़े भाई कुबेर सिंह कड़ाकोटी और उनके सुपुत्र संजय मेरे परम मित्र रहे हैं। कुबेर सिंह कड़ाकोटी की नवीनतम आत्मकथ्यात्मक पुस्तक 'यादों का सफर' रोचकता से विगत शताब्दी के उत्तरखंडी जनजीवन को रेखांकित करती है। चार खंडों में यथा- 'यादें बचपन की', 'सफर जवानी का', 'यात्रा बासठ वर्ष तक की' और 'सेवानिवृत के बाद' 75 उप शीर्षकों में उन्होंने अपने जीवन के सार को उकेरा है। पुस्तक में चारु तिवारी, चंद्रशेखर सिंह बनकोटी, देवकी पाण्डे, रवींद्र प्रकाश, बीडी सती, बाला दत्त शर्मा, हरीसिंह कड़ाकोटी, गिरधर सिंह बिष्ट, जगत सिंह कड़ाकोटी, गिरीश चंद्र भट्ट, पुष्कर कांडपाल, मदन मोहन चौधरी, नृपेंद्र कुमार जोशी आदि चर्चित महानुभावों ने कड़ाकोटी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं। इस पुस्तक की भूमिका डॉ. गजेंद्र सिंह 'बटोही' ने लिखी है।

किस्सा 1971 की एक रात का है जब कुबेर सिंह कड़ाकोटी की 65 पैसे मूल्य की अपनी तरोताजा प्रकाशित किताब 'शिव-पार्वती विवाह' को लेकर रात-भर आनंदित रहा, कड़ाकोटी की सृजनात्मक प्रतिभा का ही कमाल था कि किशोरावस्था में स्वरचित उनका कुमाऊंनी खंड काव्य 'शिव-पार्वती विवाह' को 'कुमाऊंनी साहित्य मंडल, दिल्ली' द्वारा प्रकाशित किया गया था।

15 पुस्तकों का लेखन और संपादन

हरनोली गांव (भिकियासैण), अल्मोड़ा में 7 फरवरी, 1952 को जन्मे कुबेर सिंह कड़ाकोटी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंतगांव, सिनोड़ा, भूल बगड़ और चौनलिया से प्राप्त की। चौनलिया से 1966 में 10वीं पास करने के बाद आर्थिक अभावों के कारण आगे पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं हो पाया। जूनियर हाईस्कूल, पंतस्थली में वे शिक्षक बन गए। कुछ महीने रोजगार के लिए दिल्ली में भटके, वहां बात नहीं बनी तो पहाड़ आकर जंगलात विभाग में काम चलाऊ नौकरी की। बीटीसी करने के बाद 22 नवंबर, 1971 को अपने ही गांव हरनोली में प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए। संयोग से उनके पिता भी उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में पहले से ही कार्यरत थे। हरनोली, भिकियासैण, चौखुटिया और पटलगांव उनकी शैक्षिक कर्मभूमि रही है। लगभग 43 वर्षों की शैक्षिक सेवा के उपरान्त वे 31 मार्च, 2014 को प्राथमिक विद्यालय, पटलगांव से सेवानिवृत्त हुए। शैक्षिक सेवा में सुयोग्य शिक्षक के साथ शिक्षक संगठन में उनकी सक्रिय भागेदारी रही। वे इस दौरान उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सदस्य रहे। सराहनीय शैक्षिक सेवाओं के लिए उन्हें शैलेश मटियानी राज्य स्तरीय शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार-2011 में मिला। कड़ाकोटी आकाशवाणी के नियमित वार्ताकार रहे हैं। सांस्कृतिक, शैक्षिक और बाल साहित्य पर केंद्रित कुबेर सिंह कड़ाकोटी ने 15 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है। राजकीय सेवा के उपरान्त कुबेर सिंह कड़ाकोटी ने अपनी सामाजिक दायित्वशीलता को और व्यापक किया। इसके तहत, 'नशा विरोधी अभियान' और 'पारस' पुस्तकालय, भिकियासैण का संचालन उनका एक सार्थक और अभिनव प्रयास है। उनकी रचनाशीलता वर्तमान में निरंतर गतिशील है।

पर्वतीय व्यक्ति की जीवन कथा

इस पुस्तक में मित्र चारु तिवारी ने कुबेर सिंह कड़ाकोटी के बारे में लिखा है कि 'एक शिक्षक के रूप में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि शिक्षा में नवाचार के कई सफल प्रयोग किए। स्कूल में पढ़ने के माहौल और स्कूल से बाहर पढ़ने की संस्कृति को लेकर उनके प्रयोग मील के पत्थर साबित हुए हैं। शिक्षक हितों, शिक्षा की बेहतरी तथा शैक्षिक नीतियों के निर्माण के लिए वह लम्बे समय तक शिक्षक संगठनों से जुड़कर आवाज उठाते रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बच्चों में नैतिक बोध, सामाजिक दायित्वशीलता और शिक्षा की उपयोगिता को बहुत व्यावहारिक तरीके से रखा। सेवानिवृत के बाद भी उनका शिक्षा और सामाजिक सरोकारों से नाता टूटा नहीं, बल्कि उन्होंने और सक्रियता के साथ इसे आगे बढ़ाया। नशे के खिलाफ वे स्कूलों और अलग-अलग जगहों पर बहुत सारे जन-जागरण अभियान चला रहे हैं। पढ़ने की संस्कृति को लेकर वह इतने सजग रहे हैं कि भिकियासैण जैसी जगह पर उन्होंने एक पुस्तकालय खोला है।' इस पुस्तक को अपने जीवनकाल पर केंद्रित करते हुए कुबेर सिंह ने एक आम उत्तराखंडी ग्रामीण पर्वतीय व्यक्ति की जीवन कथा को सार्वजनिक किया है। इसमें हम-सब अपने-अपने जीवनीय हिस्सों की तस्वीरें देख और समझ सकते हैं। एक पहाड़ी बालक की नैसर्गिक सहजता, संकोच, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य के प्रति दृढ़ता इसमें है। वह बालक युवापन में पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति एक जागरूक नागरिक और वर्तमान में कुबेर सिंह जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस संदर्भ में यह किताब एक व्यक्ति की जीवनीय कहानी से बढ़कर एक संदर्भ साहित्य के रूप में सार्वजनिक हो रही है। नई पीढ़ी के लिए इसमें यह संदेश है कि उनके आज को संवारने के लिए पिछली पीढ़ी ने किन-किन कठिन संघर्षों का सामना किया था। अतः इस रूप में युवा पीढ़ी को भी उसके सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देती है।

अभावग्रस्त जीवन

'मेरे जेवर बेच दो पर मेरे कुबेर को तुम आगे पढ़ा दो। मुझे नहीं चाहिए ये जेवर। मेरे जेवर तो मेरे बच्चे हैं...। पिताजी ने इजा को समझाकर कहा कि एक लड़के को पढ़ाने के लिए जेवर बेच देगी तो और बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? बात सही भी थी। आठ लोगों की गुजर-बसर पिताजी के अल्प वेतन से होती थी। पिताजी की आर्थिक विवशता से मैं आगे न पढ़ सका। इस तरह 14 साल 4 माह की उम्र में ही मेरी स्कूली शिक्षा ने दम तोड़ दिया।' आर्थिक अभावों के चलते 10वीं के बाद जब आगे पढ़ना संभव नहीं हुआ तो मां और दुकानदार लाला सिंह बूबू जैसे प्रेरक व्यक्तित्वों ने आगे पढ़ाई जारी

कड़ाकोटी ने बड़ी बारीकी, मासूमियत और मुलामियत से बिल्कुल बच्चा बन कर हम सबके बचपन को इस किताब में जीवंत किया है, 'सफर जवानी का' की 20 घटनाओं में कड़ाकोटी के जीवनीय संघर्षों और रचनात्मकता का अदभुत संगम है।

रखने के लिए उत्साहित किया। हरनोली से पंतगांव 2 किलोमीटर रोजाना मां की पीठ पर स्कूल जाना उन्हें बार-बार याद आता है। कड़ाकोटी मानते हैं कि उस दौर की निरक्षर मां बच्चों को जीवनीय संघर्षों से जूझते हुए जीतना सिखाती थी और आज की पढ़ी-लिखी अधिकांश मां वास्तविक संघर्षों से बच कर एक आभासी दुनिया का परिचय करा रही हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। किताब के प्रथम खंड 'यादें बचपन की' में 20 ऐसी घटनाओं का जिक्र लेखक ने किया है जिनसे हमारी पीढ़ी के सभी महानुभाव गुजरें हैं। शैतानियां और बड़ों की डाट-फटकार का अनवरत सिलसिला, गुल्ली-डंडा, गिराबौल, कागज की कश्ती, पटले की सवारी, अंठी, कबड्डी, अड्डू, गुच्छी, पिच्चड़, लुक्का-छिपी, ढप्प, बाघ-बकरी, रस्सी कूद, लम्फू की रोशनी में पढ़ना आदि का रोमांच इनमें है। कड़ाकोटी ने बड़ी बारीकी, मासूमियत और मुलामियत से बिल्कुल बच्चा बन कर हम सबके बचपन को इस किताब में जीवंत किया है। 'सफर जवानी का' की 20 घटनाओं में कड़ाकोटी के जीवनीय संघर्षों और रचनात्मकता का अदभुत संगम है। एक तरफ नौकरी और वैवाहिक जीवन की मधुर शुरूआत तो दूसरी तरफ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की चुनौतियां हर समय मुंहबांए रहती थी। परंतु विकट अभावों में सहजता, सरलता और संयम की प्रवृत्ति ने उनका साथ दिया।

हमारा अभियान-व्यसन मुक्त इंसान

कड़ाकोटी ने अपने शिक्षक पिता के साथ 1971 में अपने गांव हरनोली से कड़ाकोटी ने शिक्षकीय सेवा शुरू की थी। नौकरी के साथ उच्च शिक्षा जारी रखते हुए उनका एमए (हिंदी) के बाद पीएचडी का विचार किया था। परंतु अचानक आंख की रोशनी कम हो गई, इस कारण ये संभव नहीं हो पाया। इसकी कसक उनको अभी तक है। कड़ाकोटी की मुख्य शैक्षिक कर्मभूमि चौखुटिया रही है। इसी क्षेत्र में 1980 से 2014 तक पूरे 34 साल शिक्षक के रूप में काम किया। रंगीली बैराट घाटी चौखुटिया की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में वे पूर्णतया रच-बस गए थे। 1980 में शांतिकुंज परिवार से उनका जुड़ना हुआ। राजकीय सेवा निवृत्त होने के बाद वे पूर्णतया सामाजिक सरोकारों में सक्रिय हुए हैं। जीआईसी पटलगांव से 14 नवंबर, 2014 को उन्होंने 'हमारा अभियान-व्यसन मुक्त इंसान' नारे के तहत नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए। यह जन-अभियान 2 लाख से अधिक बच्चों व युवाओं तक पहुंचा चुका है। पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति के प्रचार-प्रसार में समर्पित पारस पुस्तकालय, भिकियासैण में 10 हजार से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनका दृढ़मत है कि बड़े ही छोटों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते बल्कि छोटे बच्चों के प्रयास बड़ों की आदत सुधारने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही छोटी उम्र में ही यदि जिंदगी की अच्छाई-बुराई का ज्ञान हो जाए तो अच्छी आदतें बनती चली जाएंगी। कड़ाकोटी ने इस पुस्तक में अपने मित्रों और मार्गदर्शी व्यक्तित्वों, नवीन चंद्र पाठक, पीसी तिवारी, चद्रशेखर बनकोटी, टीका सिंह अधिकारी, चंद्र सिंह ग्वाल, मोती सिंह कड़ाकोटी, अनन्त गंगोला, चंदन सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार, रविंद्र प्रकाश, दयाकृष्ण जोशी, हीरासिंह राणा, संजय कड़ाकोटी, जसोदा देवी, लक्षमण सिंह मनराल, हरिचंद्र सिंह, कड़ाकोटी, मदन चौधरी, पूरन चंद्र उपाध्याय, लीला संगेला जोशी आदि को पूरी तन्मयता से याद किया है। अध्येता और अग्रज मित्र कुबेर सिंह कड़ाकोटी कई कड़े जीवनीय अघातों से गुजरें हैं। आर्थिक अभावों से उभरे तो नियति के अघातों से उनको समझौता करना पड़ा। परंतु उनकी सामाजिक दायित्वशीलता के कर्तव्यबोध को ये आघात शिथिल नहीं कर सके। आज भी, उनके चेहरे पर हर समय विराजमान हल्की मुस्कान के पीछे के दर्द को भांपना आसान नहीं है। हर स्थिति में सहज, संयम और संतुष्ट का भाव रखना हम मित्रों ने उनसे बखूबी सीखा है। ●

बगोरी गांव का अनोखा सौंदर्य

बगोरी के लोग जड़ी-बूटियों का व्यापार करते हैं, यहां की चाय बहुत मशहूर है, यहां के लोग चाय में एक प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिससे चाय में अलग ही तरह का स्वाद आता है, सैलानियों को यहां मशरूम की कई प्रजातियां मिल जाएंगी, अगर पर्यटक खाने के शौकीन हैं, तो उन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजन यहां खाने को मिल जाएंगे।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

प्रकृति प्रेमी और घूमने के शौकीन लोगों को हमेशा ही नए-नए डेस्टिनेशन की तलाश रहती है, जहां वो कुछ अलग देख सकें और कुछ अलग अनुभव कर सकें। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा तो पहाड़ पर ही बसा है। लेकिन घूमने का मजा तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उस स्थान का कोई सांस्कृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व भी हो। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत से प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा गांव मौजूद है, जहां सैलानी खूबसूरत दृश्यों के साथ, कई नायाब चीजें देख सकते हैं। ऐसा ही एक गांव बगोरी उत्तरकाशी जिले में है। जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। यहां टूरिस्ट को कई सारी इमारतों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बेहद अनोखे अंदाज देखने को मिलते हैं। यह बागोरी गांव खेती, बाग, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के लिहाज बहुत खास है। साथ ही, यहां पर्यटकों को हाथ से बनी हुई कई कलाकारी यानी हस्तकला देखने को मिल जाएगी। खासतौर से यहां के लोग जड़ी-बूटियों का व्यापार करते हैं। इसलिए यहां की चाय बहुत मशहूर है, क्योंकि यहां के लोग चाय में एक प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिससे चाय में अलग ही तरह का स्वाद आता है। इसके अलावा सैलानियों को यहां मशरूम की कई प्रजातियां भी मिल जाएंगी। यहां के लोग खाने में मशरूम ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्यटक खाने के शौकीन हैं, तो उन्हें कई स्वादिष्ट व्यंजन यहां खाने को मिल जाएंगे। यह गांव चीन से बहुत नजदीक है इसलिए यहां पर्यटकों को कई चाइनीज खाने के व्यंजन मिल जाएंगे जैसे, नूडल्स, मोमोज आदि। पर्यटक इन व्यंजनों का भी लुत्फ भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर बागोरी गांव किसी जन्नत से कम नहीं है।

- **'ग्रीन विलेज' यानी हरित गांव के नाम से भी बगोरी को जाना जाता है, ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है, इस गांव में चारों ओर हरियाली है, आपको यहां तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति, आजीविकाओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा।**
- **बगोरी गांव में एक बौद्ध मठ के साथ-साथ मंदिर भी है, जहां सभी आस्था के साथ सिर झुकाते हैं, बगोरी में जादुंग और नेलांग के मूल निवासी रहते हैं, जिन्हें जाड़ कहा जाता है, इसके अलावा गांव में एक आबादी ऐसी भी है, जो यहीं की मूल निवासी है, यहां कुल मिलाकर 250 के करीब परिवार निवास करते हैं, जो सिर्फ गर्मियों में यहां रहते हैं।**

ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन

उत्तराखंड में अन्य हिल स्टेशन के साथ बगोरी गांव की भी सैर जरूर करनी चाहिए क्योंकि यह गांव अपने आप में बेहद खास है। कहा जाता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान सीमा पर बसे जादुंग और नेलांग गांव खाली हो गए थे और वहां के अधिकतर परिवार बगोरी गांव में आकर बस गए थे। इसलिए यहां ज्यादातर तिब्बती परिवार मिलेंगे। हालांकि बगोरी बहुत छोटा-सा गांव है, यहां की आबादी भी बहुत कम है। यह जगह बहुत शांत है अगर आपको शांति पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां आपको कई प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेंगे। इस गांव के बराबर से जलनधारी नदी भी बहती है, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। साथ ही यहां का सारा एरिया पाइन और चीड़-मजनू के पेड़ों से पटा पड़ा है। सर्दियों में यहां खूब बर्फ गिरती है। यहां टूरिस्ट को सेबों के कई खूबसूरत बाग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो हर्षिल कैंट एरिया के पास छोटा सा मार्केट भी है। जहां से पर्यटक अपनी पसंद का कुछ हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यह 'ग्रीन विलेज' यानी हरित गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह ईको-फ्रेंडली डेस्टिनेशन पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। इस गांव में चारों ओर हरियाली है। अगर आप इस गांव का रुख करते हैं, तो आपको यहां तिब्बती लोग और उनकी संस्कृति, आजीविकाओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। यहां आप तिब्बत के पारंपरिक खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। कुछ स्थान अनछुए होते हैं, जिसे छुआ तो मैले होने का डर रहता है। लिहाजा उन्हें छूकर नहीं, बल्कि देखकर महसूस किया जा सकता है। जैसे उसकी खूबसूरती और उसका नायाबपन अनोखा हो। भोटिया गांव बगोरी अपने आप में खूबसूरती के अलग-अलग आयाम समेटे हुए है। लेकिन यह गांव अभी तक पर्यटकों की नजरों से दूर है, किंतु अब धीरे-धीरे पर्यटक बागोरी गांव पहुंचने लगे हैं। गांव में लकड़ी के खूबसूरत घर और सेब के बगीचे बगोरी गांव की सबसे बड़ी खासियत है।

बगोरी गांव का ऐतिहासिक महत्व

पर्यटन ग्राम हर्षिल से महज एक किलोमीटर की दूरी तय कर बगोरी गांव पहुंच सकते है। दोपहिया गाड़ी भी गांव तक जा सकती है, लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे तो कल-कल बहती नदी पर बने सुंदर पुलों और बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार आसानी से कर पाएंगे। हिमालय की गोद में बसे इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। गांव के चारों ओर नजर घुमाएं तो बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के घने जंगल नजर आते हैं। हर्षिल से बगोरी तक के सफर में सात छोटे-छोटे पुल आते हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं। वहीं गांव के आखिरी छोर पर भागीरथी और सिंहगाड का संगम है, जहां हिमालय की गोद में बहती नदी का नजारा वाकई विहंगम होता है। कहा जाता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध से पहले जादुंग और नेलांग के लोग तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था। बगोरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे तिब्बत से नमक का व्यापार करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और उन्होंने आजीविका के नए साधन तलाश लिए। अब सेब की बागवानी के अलावा भी लोग अलग-अलग रोजगारों से जुड़ गए हैं। बगोरी गांव में एक बौद्ध मठ के साथ-साथ मंदिर भी है, जहां सभी आस्था के साथ सिर झुकाते हैं। बगोरी में जादुंग और नेलांग के मूल निवासी रहते हैं, जिन्हें जाड़ कहा जाता है। इसके अलावा गांव में एक आबादी ऐसी भी है, जो यहीं की मूल निवासी है। यहां कुल मिलाकर 250 के करीब परिवार निवास करते हैं, जो सिर्फ गर्मियों में यहां रहते हैं। सर्दियों में गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है इसलिए यहां के परिवार नीचे डुंडा और उत्तरकाशी के आसपास के गांवों की तरफ चले जाते हैं। गांव की एक खासियत यह है कि गांव में सभी घर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से बने हैं। यानी घरों पर फूलों से लेकर बेलों तक की शानदार नक्काशी की गई है। घरों के दरवाजों से लेकर खंभों तक की बनावट बरबस ही मन मोह लेती है। वहीं कई घरों पर बौद्ध मंत्र भी खुदे हैं, तो कहीं लोगों ने अपना नाम खुदा रखा है। गांव की पतली सी गली से गुजरते हुए हर एक घर पर नजर ठहर जाती है। पुराने घरों के अलावा यहां कई नए घर सीमेंट से भी बन गए हैं।

ग्रामीणों का जड़ी बूटी का ज्ञान

जंगल और पहाड़ों में रहने वाले बगोरी गांव के अधिकांश परिवारों को जड़ी-बूटियों की पहचान होती है। यहां के लोग चाय में एक विशेष प्रकार की जड़ी-बूटी डालते हैं, जिसका अलग ही स्वाद आता है। यहां आने वाले वो पर्यटक खुशनसीब होते हैं जिन्हें यह जड़ी-बूटी वाली चाय पीने का अवसर मिलता है। यहां मशरूम की कई प्रजातियों का लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। बगोरी गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोगों के भी सेब के बगीचे यहां हैं। अप्रैल में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ग्रामीणों के बगोरी आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह सीजन सेब के फ्लावरिंग का होता है और यहां के निवासियों को अपने सेब के बगीचों की देखभाल करनी होती है। इस दौरान वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और सेब की तुड़ाई तक यहीं रहते हैं। हर्षिल में खाद्य और प्रसंस्करण की एक यूनिट है, जहां कोल्ड स्टोरेज भी है। इसके अलावा हर्षिल और बगोरी के सेब की मार्केट में भी काफी डिमांड है। बगोरी गांव जाने के लिए सबसे उचित समय अप्रैल अंत और मई के बाद का है, जब ग्रामीण यहां आ जाते हैं और काफी चहल-पहल होती है। देहरादून से 220 किलोमीटर का सफर तय कर बगोरी गांव पहुंचा जा सकता है। हर्षिल तक चार पहिया और दोपहिया गाड़ियां जाती हैं, लेकिन बगोरी जाने के लिए सिर्फ बाइक या पैदल ही सफर तय करना होता है। बगोरी गांव में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर्षिल में आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। यहां गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी है, जिसमें आप रिवर व्यू रूम लेकर कल-कल कर बहती भागीरथी को करीब से महसूस कर सकते हैं।

बगोरी गांव में लोक उत्सव पर बकरे की बलि की परंपरा है, जिसे स्थानीय देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और गांव की खुशहाली व सुरक्षा के लिए 'निकाली पूजा' जैसे अनुष्ठानों के तहत किया जाता है, हालांकि बलि की यह प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी समस्या के निवारण के लिए बलि देते हैं।

बंद होनी चाहिए बलि प्रथा

बगोरी गांव में लोक उत्सव पर बकरे की बलि की परंपरा है, जिसे स्थानीय देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और गांव की खुशहाली व सुरक्षा के लिए 'निकाली पूजा' जैसे अनुष्ठानों के तहत किया जाता है। हालांकि बलि की यह प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी समस्या के निवारण के लिए बलि देते हैं, हालांकि अब कई जगहों पर फल और फूलों का प्रसाद चढ़ाने का प्रचलन बढ़ रहा है। बगोरी जैसे गांवों में हर तीन साल में होने वाली इस विशेष 'निकाली पूजा' में बकरे की बलि दी जाती है, जिसे ग्रामीण देवी-देवताओं को समर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि ये प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने, बुरी शक्तियों से बचाने और गांव में सुख-समृद्धि लाने के लिए प्रचलित है। जैसा कि मध्य प्रदेश के एक गांव में भी बकरे की बलि के बाद विकास होने की मान्यता है। बगोरी गांव के कई लोग मानते हैं कि यह अनुष्ठान मां काली जैसी देवियों को प्रसन्न करता है और आशीर्वाद दिलाता है। कुछ स्थानों पर खासकर जहां बलि के बाद समस्याएं (संक्रमित मांस खाने) सामने आई हैं, वहां अब फल, नारियल और फूलों से पूजा करने का चलन बढ़ रहा है। नई पढ़ी लिखी पीढ़ी बलि जैसी प्रथा के खिलाफ नजर आ रही है। जेन जी सवाल उठाता है कि बलि देना कहां तक सार्थक है। क्या हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए भगवान के नाम पर ये बलि देते है? एक युवा गांव आया तो घर में पूजा, जागर का कार्यक्रम हुआ। 5 बकरियों की बलि दी गई। अपने सामने ये सब कुछ देखकर युवा के मन में कई सवाल पैदा हुए। एक निरीह जीव जो अपनी पीड़ा कह नहीं सकता उस पर ये अत्याचार क्यों? जबकि हमारे पैर में एक कांटा भी चुभ जाता तो दर्द से तड़पने लगते है, लेकिन इनका क्या कौन समझेगा बेजुबानों का दर्द? शायद वही समझ पाएगा जिनके अंदर संवेदना होगी। सवाल ये भी कि क्या बलि के नाम पर यह प्रथा खत्म नहीं की जा सकती है? अल्मोड़ा के गोल्जू देवता के मंदिर में ये प्रथा खत्म हो चुकी है। युवाओं को ऐसी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। जिससे बेजुबानों पर अत्याचार होने से थम सके।

लाल चावल का क्रेज बढ़ा

लाल चावल का पोषण इसे बेहतरीन मुख्य भोजन बनाता है, लाल चावल में मुक्त कणों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, इसके पोषक तत्व उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हृदय रोग को रोकने में मदद करते हैं और रक्त शर्करा को कम करते हैं, यह मोटापे के खतरे को भी कम करता है, कई रोगों के उपचार में सहायता करता है।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड से हिमालय में जैविक रूप से उगाए जाने वाला लाल चावल, कुरकुरे बनावट और एक विशिष्ट स्वाद के साथ अत्यधिक पौष्टिक चावल है। यह प्राकृतिक रूप से गैर प्रदूषित उत्तराखंड के इलाकों में उगाया जाता है। इसमें बहुत अधिक पोषक तत्व, फाइबर सामग्री और एंटी ऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। हिमालयन रेड राइस हृदय के लिए भी अच्छा है और मधुमेह में भी उपयोगी है। उत्तरकाशी जिले की गंगा व यमुना घाटी में लाल धान की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। इस मुहिम को शुरू करने के लिए जिलाधिकारी ने खुद खेतों में उतर कर ग्रामीणों के साथ जुताई व रोपाई की थी। लिहाजा लाल धान की पैदावार के नतीजे नई उम्मीदों को जगा रहे हैं। इससे उत्साहित घाटी के किसानों ने अपनी पहली उपज को बीज के लिए सहेज कर रखा है। ताकि अगले खरीफ के दौर व्यापक स्तर पर लाल धान की खेती की जा सके। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में परंपरागत रूप से बड़े पैमाने पर लाल धान (चरधान) की खेती की जाती है। रवांई क्षेत्र में पुरोला ब्लॉक की कमल सिरांई व रामा सिरांई क्षेत्र में लाल धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके साथ नौगांव व मोरी ब्लॉक के निचले इलाकों में भी लाल धान उगाया जाता है। इन इलाकों में लाल धान की सालाना उपज करीब 3000 टन है। पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर लाल चावल की रंगत और अनूठा स्वाद इसको आम चावलों की तुलना में खास और कीमती बनाता है। इसकी देश-विदेश में काफी मांग भी है। प्रसिद्धि और मांग में निरंतर वृद्धि तथा किसानों के फायदे को देखते हुए लाल धान का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत निरंतर महसूस की जा रही थी। किसानों की बेहतरी की व्यापक संभावना को देखते हुए प्रशासन की पहल पर कृषि विभाग ने पहली बार जिले की गंगा घाटी में भी लाल धान पैदा करने की योजना बनाई है। शुरूआती दौर में चिन्यालीसौड, डुंडा और भटवाड़ी ब्लॉक के पैंतीस गांवों के लगभग 450 किसानों को इस प्रायोगिक मुहिम से जोड़ा गया। 8 कुंतल बीज की नर्सरी तैयार कर लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लाल धान की रोपाई की गई थी। वैज्ञानिक ढंग से एकत्र किए गए क्रॉप कटिंग के आंकड़ों तथा काश्तकारों की प्रतिक्रिया के आधार पर गंगा घाटी में लाल धान उगाने का शुरुआती प्रयोग सफल माना गया है।

लाल धान की पैदावार से किसान उत्साहित

इस मुहिम से जुड़े उतरौं गांव के किसान पूर्व सैनिक की मां शिव देई लाल धान की पैदावार से काफी उत्साहित है। क्योंकि खाद व रसायनों की कम जरूरत तथा सामान्य धान की तुलना में दो से तीन गुना अधिक कीमत मिलने पर किसानों को इससे अधिक लाभ मिलना तय है। सिमूणी के ही वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनकी लाल धान की फसल तेज हवा या भारी बारिश के झोंकों में भी खड़ी रही और उपज लगभग दूसरे धान के बराबर ही रही, साथ ही इसकी पुआल पशुओं के चारे के लिए अपेक्षाकृत बेहतर मानी जा रही है। मुख्य कृषि अधिकारी कहते हैं कि उतरौं गांव में जसदेई देवी तथा अन्य किसानों के प्रदर्शन प्लॉटों की क्रॉप कटिंग से नतीजों के आधार पर इस क्षेत्र में धान की औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर चालीस कुंतल से भी अधिक आंकी गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य धान की बाजार कीमत 25 से 30 रुपये प्रति किलो है जबकि लाल धान 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम आसानी से बिक रहा है। लिहाजा लाल धान से किसान को न्यूनतम से दोगुना फायदा होना तय है। अगली खरीफ में लाल धान का रकवा बढ़ाने व किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग कोशिश करने लगा है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में लाल चावल जैविक रूप से उगाया जाता है। यह बेहद पौष्टिक चावल सख्त बनावट और स्वाद के साथ आता है और इसे पकाने में सफेद चावल के समान ही समय लगता है। उच्च ऊंचाई वाली हिमालयी घाटियों में भारी बारिश इसकी ठोस बनावट और दिलचस्प स्वाद के लिए प्रतिकूल महौल बनाती है। हालांकि लाल चावल उत्तराखंड के बागेश्वर समेत कई पर्वतीय जिलों में उगाया जाता है। इसे हिमालयन रेड राइस या वीडी राइस भी कहा जाता है। यह चावल उत्तराखंड के अलावा उत्तरी भारत और हिमालय के सीमावर्ती राज्यों में भी उगाया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सफेद चावल से ज्यादा होती है।

कभी पहाड़ों में दाल-भात के रूप में इस्तेमाल होने वाला लाल चावल अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा है, स्वाद और सेहत के प्रति जागरूक लोगों की वजह से दुर्गम पहोड़ियों से निकल कर देहरादून, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में धूम मचा रहा है, देश भर में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ गई है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर लाल चावल

वैसे तो धरती पर चावल की हजारों किस्में हैं, और स्वास्थ्य लाभों के मामले में चावल सबसे अधिक फायदेमंद लगता है। किंतु लाल चावल उपलब्ध चावलों में सबसे शुद्ध प्रकारों में से एक है। यह पारंपरिक सफेद चावल खाने वालों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है जो अधिक पोषक तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्य वर्धक आहार भी है। लंबे और दानेदार चावल में वर्णक एंथोसायनिन के कारण लाल रंग का रंग होता है, जो पानी में घुलनशील होता है। लाल चावल, पूर्ण या आंशिक रूप से छिलके वाली किस्मों में उपलब्ध है, इसमें पौष्टिक स्वाद और पॉलिश किए गए चावल की तुलना में अधिक पोषण मूल्य होता है। आयुर्वेद में इसे रक्तशाली के रूप में जाना जाता है, लेकिन केरल में जहां इसका सबसे अधिक सेवन किया जाता है। केरल में इसे मट्टा चावल, केरल लाल चावल, या पलक्कड़न मट्टा चावल कहा जाता है। लाल चावल का पोषण इसे एक बेहतरीन मुख्य भोजन बनाता है। लाल चावल में मुक्त कणों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके पोषक तत्व उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हृदय रोग को रोकने में मदद करते हैं और रक्त शर्करा को कम करते हैं। यह मोटापे के खतरे को भी कम करता है, कई रोगों के उपचार में सहायता करता है। हड्डियों को मजबूत करने में भी इसके पोषक तत्व काफी अहम साबित हुए हैं। क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीज, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वजन को कम करते हैं। यह पाचन क्रिया को अच्छा करने में मददगार होता है। त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। लाल चावल में मौजूद जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। लाल चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा विकल्प है।

पहाड़ों से बाहर निकला लाल चावल

कभी पहाड़ों पर दाल-भात के रूप में इस्तेमाल होने वाला लाल चावल अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा है। स्वाद और सेहत के प्रति जागरूक लोगों की वजह से दुर्गम पहोड़ियों से निकल कर देहरादून, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में धूम मचा रहा है। देश भर में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ गई है। लोग अब इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे किसानों को भी अच्छे दाम यानी 120 से 200 रुपये प्रति किलो तक मिल रहे हैं। सर्दियों में पहाड़ों में लाल चावल की खीर तो हर घर में बनती है। इसे पारंपरिक तरीके से धीमी आंच पर दूध में पकाया जाता है और फिर गुड़ या शहद, देसी घी और मेवा के साथ परोसा जाता है। यह खीर शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देने के साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतरीन पौष्टिक आहार मानी जाती है। रात के भोजन में लाल भात खाना सेहत के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना गया है। आज जब लोग हेल्दी फूड की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड का यह पारंपरिक लाल चावल देश भर के लोगों के लिए सुपर फूड बनकर उभरा है।

- **पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर लाल चावल की रंगत और अनूठा स्वाद इसको आम चावलों की तुलना में खास और कीमती बनाता है, इसकी देश-विदेश में काफी मांग भी है, प्रसिद्धि और मांग में निरंतर वृद्धि तथा किसानों के फायदे को देखते हुए लाल धान का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत निरंतर महसूस की जा रही है।**
- **लाल चावल उत्तराखंड के बागेश्वर समेत कई पर्वतीय जिलों में उगाया जाता है, इसे हिमालयन रेड राइस या वीडी राइस भी कहा जाता है, यह चावल उत्तराखंड के अलावा उत्तरी भारत और हिमालय के सीमावर्ती राज्यों में भी उगाया जाता है, यह ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा सफेद चावल से ज्यादा होती है।**

भारत में पांच रंगों के चावल

क्या कल्पना की जा सकती है कि भारत में कहीं कोई चावल न खाता हो। यह असंभव सा लगता है। 70 प्रतिशत भारतीय प्रतिदिन एक या दो बार चावल खाते हैं। भारत प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ टन चावल का उत्पादन करता है। जिसमें से 1 करोड़ टन चावल की खपत हर साल देश के भीतर ही हो जाती है। भारत सरकार के लिए 1 से 5 करोड़ टन चावल का परिचालन स्टॉक और 2 करोड़ से 5 करोड़ टन का रणनीतिक भंडार बनाए रखना अनिवार्य है। लगभग 12 करोड़ टन चावल के उत्पादन में से, भारत सालाना 1 करोड़ टन चावल की खपत कर पाता है। उत्पादन में उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए प्राकृतिक आपदाओं या किसी भी ऐसी स्थिति के लिए सुरक्षा कवच के रूप में भी चावल का स्टाक रखा जाता है। जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इन तथ्यों से भारत में चावल के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता हैं। यह पेट भरने वाला, पकाने में आसान और पौष्टिक भी होता है। इसी भारत में चावल के अलग-अलग रंग भी पाए जाते हैं। यानी भारत में चावल मुख्य रूप से 5 रंगों में पाया जाता है। इनमें भूरे रंग का चावल जो बिना पिसे चावल का प्राकृतिक रंग है, जिसमें भूसी और चोकर की परतें बरकरार रहती हैं। भूसी और चोकर को हटाने के बाद निकलने वाला चावल एकदम सफेद होता है। इसमें सफेद स्टार्चयुक्त एंडोस्पर्म बच जाता है। लाल चावल यह उत्तराखंड, हिमाचाल और हिमालय में बसे राज्यों में पैदा होता है। केरल में इसे अक्सर रोजमट्टा कहा जाता है, चावल की यह किस्म चोकर की परत में मौजूद एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण लाल-भूरी होती है। काला चावल मणिपुर की चक्रवाला किस्म की तरह है, इस किस्म का रंग गहरे काले रंग का होता है, जो बीज के बाहरी आवरण (पेरिकार्प) में मौजूद एंथोसायनिन वर्णक के कारण होता है। बैंगनी चावल केरल की कवुनी या असम की काला भट्ट जैसी किस्मों में आते है जो चोकर की परत में मौजूद एंथोसायनिन वर्णक के कारण बैंगनी रंग का होता है। ये सभी रंगीन चावल हमारे दैनिक पोषण के लिए बहुत अच्छे हैं। लाल चावल मुख्य रूप से उत्तराखंड ओडिशा, मणिपुर, केरल, कर्नाटक और असम में पैदा होता है। इसी लाल चावल में मुख्य रूप से स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ होते है। यानी लाल चावल कैंसर कोशिकाओं को रोकने में सहायक साबित होता है। लाल चावल के अनगिनत फायदों के बावजूद, लाल चावल के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन दुष्प्रभावों में गैस बनना, सूजन या पेट दर्द जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती है। लाल चावल के उपयोग को सुनिश्चित करने और इसके प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिए डॉक्टर का परामर्श और दुष्प्रभाव सामने आने पर आवश्यक दवाएं जरूर लें।

राकेश बेदी का सितारा बुलंद

फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पर बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही है और कमाई भी अच्छी कर रही है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट और निर्देशन आदित्य धर का है, हमने तो कलाकार के तौर पर काम किया, जो काम हमें करने के लिए कहा गया, लेकिन 'असल मेहनत आदित्य धर की है।'

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

बॉलीवुड के कब किसके सितारे बुलंद हो जाते हैं और कब सितारे डूब जाते हैं ये कोई नहीं बता सकता। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता ने उन कलाकारों को आज स्टार बना दिया है, जो बरसों से गुमनामी में कहीं खो गए थे। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म में राकेश बेदी ने अपने 'जमील जमाली' के किरदार से सबका दिल जीत लिया है। इस फिल्म की सफलता के साथ ही राकेश बेदी फिर शूटिंग में व्यस्त हो गए है। वो 'धुरंधर 2' के बाद वो वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और प्राइम वीडियो पर आने वाली सीरीज 'राख' में दिखने वाले हैं। दोनों की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही रिलीज की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब जब 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने सफलता का रिकार्ड बनाया तो मायानगरी में राकेश बेदी का सितारा भी बुलंद होने लगा। हाल ही में मीडिया के कई मंचों पर राकेश बेदी ने अपने किरदार को लेकर बेबाक बातें की हैं। लेकिन ये साफ कर दिया कि 'धुरंधर 3' नहीं आने वाली है। फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पर बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही है और कमाई भी अच्छी कर रही है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट और निर्देशन आदित्य धर का ही है। हमने तो कलाकार के तौर पर काम किया, जो काम हमें करने के लिए कहा गया, लेकिन 'असल मेहनत आदित्य धर की है।' राकेश बेदी ने कहा फिल्म 'धुरंधर 2' में जमील जमाली के किरदार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि 'हर किरदार के लिए मेहनत करनी पड़ती है।' जैसे हम विराट कोहली को छक्का मारते देखते हैं तो देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन असल में आसान होता नहीं है। ऐसे ही हर किरदार को निभाने से पहले बहुत कुछ करना होता है। वहीं फिल्म में रणवीर सिंह को असली धुरंधर बताते हुए एक्टर राकेश बेदी ने कहा, 'जिस तरीके से किरदार की मांग थी, सभी किरदारों ने वैसा ही रोल प्ले किया है। मेरा किरदार रणवीर सिंह को बचाने का था क्योंकि अगर कोई स्पाई दूसरे देश में जा रहा है तो कोई सपोर्ट करने वाला और बचाने वाला भी होना चाहिए।' कॉमेडी से 'धुरंधर 2' में 'जमील जमाली' के निगेटिव रोल को निभाने के सवाल पर एक्टर बेदी ने कहा, कि 'आदित्य धर को लगा कि मैं ये किरदार कर सकता हूं तो मुझे चुना गया। मैं वैसा विलन नहीं बना, जैसी छवि भारतीय सिनेमा में रही है। मुझे तो चालाक और मेरे डायलॉग (मेरा बच्चा है तू) वाला विलन बनाया गया।

कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा लग रही है फिल्म

जहां एक तरफ फिल्म 'धुरंधर 2' को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे 'प्रोपेगेंडा' बताकर सवाल उठा रहे हैं। फिल्म में 'जमील जमाली' का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने इस सवाल का जवाब दिया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए राकेश बेदी ने साफ कहा कि 'मैं राजनीति में नहीं, बल्कि सिनेमा में विश्वास रखता हूं। हर किसी को फिल्म पसंद या नापसंद करने का हक है, लेकिन किसी फिल्म को राजनीतिक सोच से जोड़ देना सही नहीं है। दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा फैसला होता है और 'धुरंधर' तथा 'धुरंधर 2' को लोग पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' पर तंज कसते हुए कहा कि हाल में कुछ राजनीतिक विषयों पर बनी फिल्में आईं, लेकिन वो ज्यादा दिन थिएटर में टिक नहीं पाईं. इसके मुकाबले 'धुरंधर' की कहानी और स्क्रीनप्ले काफी मजबूत है और फिल्म बड़े स्तर पर बनाई गई है, जो दर्शकों को आकर्षित करने में सफल रही है।

कैसे की किरदार की तैयारी

फिल्म धुरंधर में जमील जमाली के किरदार में एक्टर राकेश बेदी ने कमाल कर दिखाया है। राकेश बेदी की दमदार एक्टिंग के फैंस मुरीद हो गए हैं। सोशल मीडिया पर राकेश बेदी ट्रेंड करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी उनके खूब चर्चे हो रहे है। फिल्म से राकेश बेदी के कई डायलॉग्स वायरल हैं। अब एक्टर राकेश बेदी ने बताया है कि जमील जमाली के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने किस तरह तैयारी की। उन्होंने जमील जमाली का किरदार निभाने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के स्पीच पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टाइल पर बारीकी से ध्यान दिया। उनके बारे में पढ़ा। हालांकि राकेश बेदी ने ये भी कहा कि जमील जमाली से पहले साल 1981 में आई फिल्म 'एक दूजे के लिए' में उनका चक्रवर्ती का किरदार भी उस समय काफी फेमस हुआ था। उनके किरदार के खूब चर्चे हुए थे। आज की तुलना में उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पहुंच सीमित रही। जमील जमाली के किरदार को मिली सफलता से वो काफी खुश हैं।

साधारण लाइफस्टाइल

आदित्य धर द्वारा निर्देशित सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार राकेश बेदी को ऑन स्क्रीन जितना पसंद किया जाता है वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी उनके चाहने वाले कम नहीं हैं। दशकों से चकाचौंध भरे हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में अपने काम का लोहा मनवाने वाले राकेश असल जिंदगी में अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण सी लाइफस्टाइल जीते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रही है। वे अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं, खासतौर से शादी के इतने सालों बाद भी उनका पत्नी के साथ रिश्ता, उनके प्रति प्रेम, सम्मान कुछ नहीं बदला है। कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। वैसे ही राकेश की जिंदगी में उनकी पत्नी आराधना बेदी का सपोर्ट और साथ अहम रहा है। उनकी और उनकी पत्नी आराधना बेदी की प्रेम कहानी यह साबित करती है कि असली प्यार दिखावे से नहीं, बल्कि भरोसे और समझ से बनता है।

- **राकेश बेदी ने बताया कि जमील जमाली के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने किस तरह तैयारी की, उन्होंने जमील जमाली का किरदार निभाने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के स्पीच पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टाइल पर बारीकी से ध्यान दिया, उनके बारे में पढ़ा।**
- **दशकों से चकाचौंध भरे हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में अपने काम का लोहा मनवाने वाले राकेश असल जिंदगी में अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण सी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रही है।**

अरेंज मैरिज, पर प्यार बेसुमार

हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन राकेश बेदी की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। खास बात यह है कि उनकी शादी लव मैरिज नहीं, बल्कि अरेंज मैरिज है, जो समय के साथ एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई। राकेश और आराधना को पहली नजर में ही पहला प्यार हो गया था और कुछ उतार चढ़ाव के बाद उनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि राकेश बेदी और आराधना बेदी का रिश्ता उनके परिवार के माध्यम से तय हुआ था। उनकी शादी एक टिपिकल अरेंज मैरिज है, जहां दोनों के कुछ रिश्तेदार एक-दूसरे को जानते थे और उन्हीं के जरिए यह रिश्ता सामने आया था। राकेश की मामी और आराधना की मोसी आपस में अच्छी दोस्त थीं। उन्होंने ही इस रिश्ते का प्रस्ताव रखा और दोनों को एक-दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट माना था। जो बात बेशक आज उनकी शादी के 35 सालों बाद सच भी साबित हुई है। जब राकेश बेदी, आराधना से पहली बार मिलने गए थे, तभी ये मुलाकात उनके लिए बेहद खास बन गई थी। आराधना को पहली नजर में देखते ही राकेश उन्हें दिल दे बैठे थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पहली नजर में ही आराधना से प्यार हो गया था। यही वजह थी कि यह अरेंज मैरिज धीरे-धीरे सच्चे प्यार में बदल गई। हालांकि इस रिश्ते में एक छोटी-सी बाधा भी आई थी। दरअसल आराधना के माता-पिता को राकेश बेदी के पेशे को लेकर चिंता थी। उस समय एक्टिंग को एक स्थिर करियर नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें बेटी के राकेश संग भविष्य को लेकर थोड़ा संदेह था। लेकिन राकेश के सादगी और सच्चाई भरे व्यक्तित्व और दोनों के मजबूत रिश्ते को देखते हुए आखिरकार उन्होंने भी इस शादी के लिए हां कर दी थी। राकेश और आराधना की शादी में कोई फिल्मी ड्रामा या बड़ा सा आयोजन नहीं था। यह रिश्ता सादगी, समझ और परिवार के विश्वास पर टिका हुआ था। समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। राकेश बेदी ने अपनी लंबी और सफल शादी का राज बताते हुए कहा कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है आपसी सम्मान और समझ। उनका मानना है कि छोटे-छोटे पलों में खुशियां ढूंढना और एक-दूसरे का साथ निभाना ही किसी भी शादी को मजबूत बनाता है। हालांकि हर कपल की तरह, उनके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया। एक इंटरव्यू में राकेश बेदी ने बताया था कि तमाम झगड़ों के बावजूद, उन्होंने एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर

राकेश बेदी ने अपनी लंबी और सफल शादी का राज बताते हुए कहा कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है आपसी सम्मान और समझ, उनका मानना है कि छोटे-छोटे पलों में खुशियां ढूंढना और एक-दूसरे का साथ निभाना ही शादी को मजबूत बनाता है, हालांकि हर कपल की तरह, उनके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया।

करेंगे और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे। राकेश बेदी और आराधना बेदी दो बेटियों, रिधिमा और रितिका के माता-पिता हैं। राकेश का अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता है। उनकी बड़ी बेटी की शादी 2022 में हुई थी और यह उनके लिए एक बेहद भावुक पल था।

राकेश बेदी की असल जिंदगी भी फिल्मी

राकेश बेदी ने अपनी लाइफ में एक ऐसा फैसला लिया था। जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने अपने सिक्योर करियर को छोड़ कर अपने जुनून को चुना और वही उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया। दिल्ली के करोल बाग में पले-बढ़े राकेश बेदी ने एंड्रयूज गंज के सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बेदी के सामने भी वही आम सपना था। अच्छी पढ़ाई, आईआईटी में दाखिला और एक सिक्योर नौकरी। उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा भी दी, लेकिन दिल कहीं और था। कहा जाता है कि उन्होंने 39 में से सिर्फ 7 सवाल हल किए और बीच में ही परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा हॉल से निकलकर वो सीधे थिएटर रिहर्सल के लिए पहुंच गए। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद उन्हें लंबे समय तक तंगी का सामना करना पड़ा। राकेश बेदी ने अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। धीरे-धीरे उन्होंने टीवी और फिल्मों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने 'श्रीमान श्रीमती', 'ये दुनिया गजब की', 'भाबी जी घर पर हैं' जैसे कई पॉपुलर टीवी शो किए। फिल्मों में भी 'चश्मे बद्दूर' और 'बेवफा सनम' जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी यादगार रही। लेकिन फिल्म धुरंधर में उनके द्वारा निभाए किरदार 'जमील जमाली' ने उन्हें नई पहचान दी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना करेगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। आपका प्रिय आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता न करें, आपकी गैरहाजिरी में सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और लाभकारी समय की ओर ले जाएंगे। अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। उपाय: किसी नेत्रहिन की मदद करे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

कर्कः-

इस माह दूसरों के सफलता की सराहना कर आप सहानुभूति का लुत्फ ले सकते हैं। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। परिवार के लिए किसी अच्छे और ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए समझ-बूझकर थोड़ा खतरा उठाया जा सकता है। एक तरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा। आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। जरूरत के वक्त आपका जीवनसाथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय: गाय को हरा चार खिलाने से कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

तुलाः-

इस माह कुछ बदलाव आपके रूप-रंग को आकर्षक बनाएगा। बैंक से जुड़े लेन-देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोशिश करें की कोई आपकी बातों या काम से आहत न हो और पारिवारिक जरूरतों को समझें। नये रोमांस की संभावना प्रबल है, प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन समय है। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। आप और आपका जीवनसाथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। उपाय: मंगल शांति मंत्र 21 बार सुबह शाम जपे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

मकरः-

इस माह अपने काम पर एकाग्रता रखने में परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाये कुछ ऐसा करें जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। आप अपने साथी के नजरिए को नजर अंदाज करेंगे, तो वह अपना आपा खो सकता है। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक न करें। आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे। अपने जीवनसाथी की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसान कर सकते हैं। उपाय: जल प्रधान वस्तुओं का सेवन करें (नारियल पानी, पपीता, खीरा आदि) कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

वृषभः-

इस माह आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो हालात बेहतर होते हुए महसूस करेंगे। उपाय: हरे तोते व तोती के जोड़े को आजाद कराए कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

सिंहः-

इस माह आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। जेवर और एंटीक सामान में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको राहत दे सकती है। आपका रुमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकता है। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिसे आप सुनना चाहते थे। जरूरत के वक्त आपका जीवनसाथी आपके परिवार को तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय: गाय को आलू पर हल्दी लगाकर खिलाए कार्य सिद्ध हांगे। भाग्यांक 8

वृश्चिकः-

प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच-बस जाएं, तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। जिंदादिल और गर्मजोशी पूर्ण व्यवहार आपके आस-पास के लोगों को खुश कर देगा। आपके प्यार के बीच कोई आ सकता है। लंबे समय से लटके कार्य जल्द पूर्ण होंगे। उपाय: घर से निकलते हुए इत्र लगाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

कुंभः-

इस माह खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। परिवार की मदद से आर्थिक तौर पर फायदा होगा। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज़ देखने को मिल सकता है। आप यात्रा कर रहें है तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। इस माह जीवनसाथी के साथ की एहमियत महसूस करेंगे। उपाय: बैडरूम में कृस्टिल बॉल लगाने से कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

मिथुनः-

इस माह किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश करेगी। ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया समय है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। आपका घर मेहमानों से भर सकता है जो आपको खुशियां देगा। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाओं का आइडिया देगा। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय आ गया है। क्या आपको पता है कि आपका जीवनसाथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है। उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद-ब-खुद नजर आएगी। उपाय: बट वृक्ष पर जल चढ़ा कर चार परिक्रमा लेकर मिट्टी का टीका लगाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

कन्याः-

नियमित व्यायाम करने से वजन नियंत्रित रहेगा। अतिरिक्त धन को रिअल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। घर पर मेहमानों का आना बढ़िया और खुशगवार वातावरण बना देगा। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिस कार्य का चयन करेंगे उससे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। जीवनसाथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। उपाय: काले सफेद कुत्ते को दूध व रोटी खिलाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

धनुः-

इस माह सेहत में गड़बड़ी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं। रोमांटिक मुलाकात बहुत रोमांचक रहेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। अपने जीवनसाथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदा हो सकते हैं। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मीनः-

इस माह आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने-हंसाने की शैली है, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। पैसा अचानक आपके पास अएगा, जो अपके खर्च को संभाल लेगा। दोस्तों के साथ घूमें-फिरें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम के नजरिए से यह माह आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह माह शानदार रहेगा। उपाय: दही घी मिश्री कपूर दूध धर्मस्थल पर दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 5

KEEP CALM, STUDY HARD AND BECOME A DOCTOR

MBBS IN RUSSIA

- ★ English Medium MBBS Course .
- ★ No Entrance Exam , No Donation.
- ★ Low Cost Tuition Fee.
- ★ MCI Recognized Medical University.
- ★ Degree Valid for Government Job in India.
- ★ 50% Marks in 12th in PCBE . NEET Exam Qualifying Marks is Necessary.

ThinkMBBS.com

Mob.
7060741233
9759180746

Address :
Opposite Maa Jagdamba Banquet Hall, Talli Bamori, Haldwani, Distt- Nainital .
www.thinkmbbs.com

A Head Start towards the Career of Your Dream.An Opportunityis Never Lost. It is Just Found By Someone Else